चिंतन

दुनिया को समाधान देने की ओर बढ़ रहा भारत

आज दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। खाड़ी संकट ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। जलवायु परिवर्तन का संकट गहरा रहा है, एआई नई संभावनाओं के साथ नई चिंताएं भी पैदा कर रहा है, ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न बनी हुई है और तकनीकी प्रतिस्पर्धा वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर रही है। ऐसे दौर में केवल वही देश प्रभावशाली भूमिका निभा पाएंगे, जो समस्याओं की पहचान ही नहीं, बल्कि उनके समाधान भी पेश कर सकें। फ्रांस में आयोजित 'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि भारत अब केवल वैश्विक परिवर्तनों का दर्शक नहीं बना रहना चाहता, बल्कि उन्हें दिशा देने की तैयारी कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का यह कहना कि भारत नवाचार का देश है और दुनिया भारत के साथ मिलकर इनोवेशन करना चाहती है, कोई साधारण टिप्पणी नहीं है। यह उस बदलती वैश्विक धारणा का प्रतिबिंब है, जिसमें भारत को अब केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान, तकनीक और नवाचार के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि समाधान देने वाला देश भी बन रहा है। पिछले एक दशक में भारत ने जिस तेजी से तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में प्रगति की है, उसने दुनिया का ध्यान खींचा है। डिजिटल भुगतान व्यवस्था, आधार आधारित सेवाएं, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और कम लागत वाले तकनीकी समाधान आज कई देशों के लिए अध्ययन का विषय हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप नेटवर्क में शामिल हो चुका है। दो लाख से अधिक स्टार्टअप केवल रोजगार सृजन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ये कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त, अंतरिक्ष और कृत्रिम मेधा जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं भी विकसित कर रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती साझेदारी भी इसी परिवर्तन का हिस्सा है। दोनों देशों के संबंध अब केवल रक्षा सौदों या कूटनीतिक बैठकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि कृत्रिम मेधा, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष विज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा है। यही कारण है कि 'भारत इनोवेट्स' जैसे मंचों को केवल एक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इन्हें भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में समझा जाना चाहिए। हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष भी उतना ही अहम है। नवाचार की वास्तविक ताकत केवल स्टार्टअप्स की संख्या से नहीं मापी जाती, बल्कि उससे पैदा होने वाले प्रभाव से तय होती है। भारत को अनुसंधान एवं विकास पर खर्च बढ़ाना होगा। युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि समाधान विकसित करने वाला बनाने की दिशा में शिक्षा व्यवस्था को भी बदलना होगा। यह भी सच है कि आज दुनिया ऐसे देशों की तलाश में है जो प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग का रास्ता दिखा सकें। यही कारण है कि जलवायु परिवर्तन से लेकर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तक, भारत के मॉडल को दुनिया गंभीरता से देख रही है। भारत के पास यह अवसर है कि वह विकासशील देशों की आवाज बनने के साथ-साथ तकनीकी समाधान का नेतृत्व भी करे। 21वीं सदी में किसी भी देश की असली ताकत उसकी सैन्य क्षमता या आर्थिक आकार से नहीं, बल्कि दुनिया को दिए गए समाधानों से तय होगी। भारत उसी दिशा में आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ा चुका है।

आधी दुनिया

डॉ. मोनिका शर्मा

हमारी बेटियों की सशक्त कदमताल

हाल ही में समानता और सशक्तिकरण के पथ पर कदमताल करती बेटियों और भारतीय सेना के लिए एक और विशेष दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। ध्यातव्य है कि देश में पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी के पहले महिला बैच की चौदह बेटियां एक साल का कठिन प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना और वायुसेना में अफसर बनी हैं। देहरादून और हैदराबाद दोनों जगहों को मिलाकर कुल 746 कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। इनमें देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी और हैदराबाद की डुंडीगुल एयर फोर्स एकेडमी में आयोजित एनडीए पासिंग आउट परेड-2026 के बाद 14 बेटियों को भी सेना में कमीशन मिला है। ज्ञात हो कि चार साल पहले उच्चत्तम न्यायालय के आदेश के बाद ही महिलाओं के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के रास्ते खुले थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अगस्त 2022 में एनडीए में महिला कैडेट्स के पहले बैच को प्रवेश मिला। 3 साल के बेहद कड़े प्रशिक्षण के बाद पिछले साल मई महीने में 18 महिला कैडेट्स ग्रेजुएट हुईं। इन्हीं में से 9 महिला कैडेट्स ने इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने का फैसला लिया और देहरादून के इंडियन मिलिट्री अकादमी में करीब 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग ली थी। वहीं हैदराबाद के डुंडीगल स्थित एयर फोर्स अकादमी से 5 महिला कैडेट्स ने कमीशन प्राप्त किया है। यह पहला अवसर है जब महिला कैडेट्स ने सीधे स्थायी कमीशन प्राप्त किया है। ज्ञात हो कि पहले महिलाओं को केवल 'शॉर्ट सर्विस कमीशन' के जरिए ही सेना में प्रवेश मिलता था। ऐसे में यह केवल नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। विचारणीय है कि लैंगिक समानता और सामाजिक बदलाव लाने से लेकर रोजगार के मोर्चे तक, यह महिलाओं के लिए नई आशाओं और हौसले को जगाने वाली बात है। साथ ही यह बेटियों को अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलने का परिवेश बनाने से जुड़ा बदलाव भी है। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड के 94 साल के इतिहास में पहली बार 9 महिला कैडेट्स ने पुरुष कैडेटों के साथ 'अंतिम पग' पार कर भारतीय सेना में सैन्य अधिकारी बनना हर मोर्चे पर महिलाओं की सबलता का परिचायक है। हालांकि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में महिलाओं की पहले से ही भागीदारी है, पर भारतीय सैन्य अकादमी के एक लंबे सैन्य इतिहास में पुशु कैडेट्स संग साझी कदमताल का यह पल थोड़ा विशेष है। कुछ समय पहले भारतीय नौसेना ने भी पहली बार महिला नाविकों को सेवा में शामिल किया था। सुखद है कि हालिया बरसों में गणतन्त्र दिवस की परेड को कमांड करने से लेकर मुश्किल मिलिट्री ऑपरेशन्स तक, बेटियां अब आर्म्ड फोर्सेस में अहम भूमिका में दिखने लगी हैं। इतना ही नहीं, सेना की तीनों ही यूनिट्स में स्त्री शक्ति का खुले मन से स्वागत भी किया जा रहा है। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर महिलाएं सैन्य संसार में लीडिंग रोल में आ रही हैं। पिछले कुछ बरसों में सैन्य बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़े अहम बदलाव भी हुए हैं।इन्हीं बदलावों के अंतर्गत सरकार ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को मंजूरी दी थी। यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री से मिली ऑफिशियल मंजूरी के बाद भारतीय सेना के सभी दस हिस्सों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला है। इन डिपार्टमेंट्स में आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स व मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स आदि शामिल हैं। यह सैन्य बलों में नारी शक्ति की बढ़ती भागीदारी की ही बानगी है कि कर्तव्य पथ पर महिला दस्ते की अगुआई में परेड होना भी एक अहम शुरुआत रही। 72वें रिपब्लिक डे के अवसर पर पहली बार थल सेना, नौसेना और वायु सेना के महिला सैन्य दल भी परेड में शामिल हुए थे। दरअसल, वर्ष 1992 तक महिलाओं को केवल सशस्त्र सेना मेडिकल कोर में शामिल किया जाता था। नौसेना में भी महिलाओं को कुछ चुनी हुई शाखाओं में अल्पकालिक कमीशन अफ़सर के रूप में भर्ती किया जाता था। यहां तक कि लड़कियों के लिए सैनिक स्कूलों में पढ़ने के रास्ते भी हाल ही में खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में देश के सभी सैनिक स्कूलों में छात्राओं के नामांकन को खोलने की ऐतिहासिक घोषणा की थी। यही वजह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा कि 9 महिला ऑफिसर कैडेट्स के पास आउट होने का मतलब है कि भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही हक दिया जाता है और महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की तरक्की और इस देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभा रही है।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

सतर्कता

सतीश सिंह

लापरवाही से बढ़ती धोखाधड़ी की वारदातें

भारत में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान व्यवस्था जितनी तेज़ी से विस्तृत हुई है, उतनी ही तेज़ी से धोखाधड़ी के तौर-तरीके भी बदलते गए हैं। पहले धोखाधड़ी का बड़ा हिस्सा कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़े छोटे-छोटे मामलों में दिखाई देता था। अब तस्वीर बदल रही है। धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घट रही है, लेकिन उनमें शामिल रकम तेजी से बढ़ रही है। यह संकेत केवल बैंकिंग तंत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में बैंकों ने 48,021 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी दर्ज की। यह रकम एक वर्ष पहले के 32,803 करोड़ रुपये की तुलना में 46.4 प्रतिशत अधिक है।

भारत में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान व्यवस्था जितनी तेजी से विस्तृत हुई है, उतनी ही तेज़ी से धोखाधड़ी के तौर-तरीके भी बदलते गए हैं। पहले धोखाधड़ी का बड़ा हिस्सा कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़े छोटे-छोटे मामलों में दिखाई देता था। अब तस्वीर बदल रही है। धोखाधड़ी के मामलों की संख्या घट रही है, लेकिन उनमें शामिल रकम तेजी से बढ़ रही है। यह संकेत केवल बैंकिंग तंत्र के लिए नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। भारतीय रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में बैंकों ने 48,021 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी दर्ज की। यह रकम एक वर्ष पहले के 32,803 करोड़ रुपये की तुलना में 46.4 प्रतिशत अधिक है।

वित्त वर्ष 2023-24 में दर्ज 11,013 करोड़ रुपये की तुलना में यह चार गुना से भी ज्यादा है। दूसरी ओर, धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में बड़ी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2025-26 में 10,114 मामले दर्ज हुए, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 23,722 थी। यानी मामलों की संख्या लगभग 57 प्रतिशत घटी। वित्त वर्ष 2023-24 के 35,800 मामलों की तुलना में यह गिरावट करीब 72 प्रतिशत है। आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकिंग व्यवस्था में धोखाधड़ी की प्रकृति बदल रही है। अब छोटे और बिखरे हुए डिजिटल फ्रॉड की तुलना में बड़े कर्ज और एडवांस से जुड़े धोखाधड़ी मामले अधिक गंभीर चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता कर्ज और एडवांस से जुड़े मामलों को लेकर है। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल धोखाधड़ी राशि में इनकी हिस्सेदारी 85.5 प्रतिशत रही। कर्ज और एडवांस से जुड़े धोखाधड़ी मामलों की रकम बढ़कर 40,774 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 357 प्रतिशत अधिक है। ऐसे मामलों की संख्या भी बढ़कर 8,640 हो गई, जो पिछले वर्ष 7,924 थी। यह स्थिति बताती है कि बैंकिंग प्रणाली के भीतर ऋण स्वीकृति, निगरानी, मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन से जुड़े तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। सरकारी बैंकों पर इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी बैंकों को धोखाधड़ी के कारण 35,709 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो पिछले वर्ष के 23,617 करोड़ रुपये की तुलना में 51 प्रतिशत अधिक है। कुल धोखाधड़ी राशि में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी बढ़कर 74.5 प्रतिशत हो गई। हालांकि, सरकारी बैंकों में दर्ज मामलों की संख्या घटकर 5,418 रह गई, जो एक वर्ष पहले 6,916 थी। यह स्थिति बताती है कि सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, वे अधिक बड़े और गंभीर हैं। निजी बैंक भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं। निजी बैंकों में धोखाधड़ी की रकम बढ़कर 11,399 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष के 8,927 करोड़ रुपये से 27.7 प्रतिशत अधिक है। कुल धोखाधड़ी राशि में निजी बैंकों की हिस्सेदारी 23.7 प्रतिशत रही, जबकि कुल मामलों में उनका हिस्सा 39.1 प्रतिशत था। इसका अर्थ है कि निजी बैंकों में मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन राशि के लिहाज से सरकारी बैंकों पर दबाव कहीं अधिक गंभीर है। इसके उलट, डिजिटल भुगतान से जुड़े

धोखाधड़ी मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से जुड़े मामलों की संख्या घटकर 293 रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 13,332 थी और वित्त वर्ष 2023-24 में 28,836 थी। इन मामलों में शामिल रकम भी घटकर 29 करोड़ रुपये रह गई, जबकि पिछले वर्ष यह 517 करोड़ रुपये थी। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था में तकनीकी सुरक्षा, शिकायत निवारण, निगरानी और जन-जागरूकता के स्तर पर सुधार हुआ है। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि आम नागरिकों के लिए खतरा समाप्त हो गया है। यूपीआई ने भारत में भुगतान व्यवस्था को आम आदमी तक पहुंचाया है। यह सुविधा जितनी उपयोगी है, उतनी ही सावधानी भी मांगती है। वित्त वर्ष 2024 में यूपीआई धोखाधड़ी के 13.42 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें कुल 1,087 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई।

हाल के रुझानों में इन मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन यूपीआई से जुड़े खतरे पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। अधिकांश मामलों में ठग अज्ञात लिंक या क्यूआर कोड भेजते हैं, ओटीपी या पिन मांगते हैं या किसी लाभ, इनाम, कैशबैक अथवा आपात स्थिति का झांसा देकर खाते खाली कर देते हैं। साइबर ठगी की दुनिया में 'डिजिटल अरेस्ट' सबसे भयावह रूप में सामने आया है। इसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी, कस्टम या किसी अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वे वीडियो कॉल पर पीड़ित को डराते हैं कि उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स तस्करी, हवाला या किसी आपराधिक मामले से जुड़ गया है। इसके बाद उसे 'डिजिटल निगरानी' या 'वर्चुअल गिरफ्तारी' के नाम पर कमरे में बंद रहने, किसी से बात न करने और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लोग भय, सामाजिक बदनामी और कानूनी कार्रवाई के डर से लाखों-करोड़ों रुपये गंवा बैठते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मनोविज्ञान बेहद खतरनाक है। ठग तकनीक से ज्यादा डर और भ्रम का इस्तेमाल करते हैं। वे सरकारी प्रतीकों, नकली पहचान पत्रों, वीडियो कॉल, अदालत या जांच एजेंसी जैसे शब्दों और धमकी भरे लहजे से पीड़ित को मानसिक रूप से अस्थिर कर देते हैं। धोखाधड़ी से बचने का पहला उपाय है-लालच और लापरवाही से बचना। किसी भी अनजान कॉल, लिंक, क्यूआर कोड, निवेश प्रस्ताव, लॉटरी, कैशबैक, नौकरी, कर्ज या सरकारी योजना के नाम पर मिले संदेश पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी बैंक, सरकारी एजेंसी, पुलिस या रिजर्व बैंक कभी फोन पर ओटीपी, पिन, पासवर्ड, कार्ड नंबर, सीवीवी या नेट बैंकिंग विवरण नहीं मांगता। किसी भी लिंक पर क्लिक करने, स्क्रीन शेयर करने, ऐप डाउनलोड करने या खाते से पैसे भेजने से पहले उसकी प्रामाणिकता जांचना जरूरी है।

दूसरा उपाय है-समय पर शिकायत करना। डिजिटल धोखाधड़ी होने पर घबराने या चुप रहने के बजाय तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। संबंधित बैंक, यूपीआई ऐप या वॉलेट सेवा प्रदाता को भी तुरंत सूचना देनी चाहिए। बैंकिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की बड़ी शक्ति हैं। लेकिन यह शक्ति तभी सुरक्षित रह सकती है, जब भरोसे के साथ सावधानी भी जुड़ी रहे। धोखाधड़ी से बचाव का सबसे सरल मंत्र यही है-लालच से दूरी, लापरवाही से सावधानी और हर संदिग्ध स्थिति में तुरंत शिकायत। यही सतर्कता आम नागरिक की मेहनत की कमाई, बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता और देश की वित्तीय सुरक्षा- तीनों की रक्षा कर सकती है।

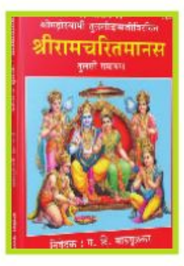

(लेखक आर्थिक स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

बड़े भाग मानुष तनु पावा

संकलित

दर्शन

संवाद का ऐसा सांगोपांग निर्वहन संसार के किसी स्मृति साहित्य में नहीं मिलेगा, जो श्रीरामचरितमानस में है। पूरा मानस भक्त काकभुशुंडि और ज्ञानी पक्षीराज गरुड़ के बीच का संवाद है। भक्त काकभुशुंडि वक्ता हैं और ज्ञानी गरुड़ श्रोता हैं। भक्त प्रतिपादन कर रहा है और ज्ञानी जिज्ञासा कर रहा है। भक्त के प्रतिपादन में भावना का वह समुद्र लहराता है, जिसमें तनिक भी खारापन नहीं होता है और ज्ञानी की जिज्ञासा में कुतर्क का अभाव होता है। भक्त और ज्ञानी दोनों का परम उद्देश्य रामराज्य है, जो आचरण के उपादान के बगैर संभव नहीं है। समग्र रामकथा श्रवण के पश्चात पक्षीराज गरुण काकभुशुंडि जी से सात प्रश्नों की जिज्ञासा करते हैं। पहला प्रश्न पूछते हुए वह कहते हैं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? काकभुशुंडि जी उत्तर देते हैं कि मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है, क्योंकि मैंने स्वयं भी इसी शरीर के रहते भगवान और उनकी भक्ति को पाया है। वह कहते हैं कि मनुष्य तन ही वह उपलब्धि है, जो मोक्ष सुख का अनुभव भी करा सकता है। स्वर्ग के सुख को लोग भले ही श्रेष्ठ मानते हों, पर अंत में वह भी अल्प है और दुख का कारण बनता है। भक्त के जीवन में जो प्राप्त शरीर है, वह भी आराध्य को पाने का उपादान होने के कारण पूज्य हो जाता है। संसार में भी किसी व्यक्ति के सहयोग से यदि हमें कुछ विशेष उपलब्धि हो गई हो तो हम जीवन भर उसके कृतज्ञ रहते हैं, उसी प्रकार काकभुशुंडि जी कह रहे हैं कि शरीर मिथ्या तो तब होगा, जब इसका उद्देश्य भोगों की प्राप्ति हो।

झूठे आरोप का सामना बुद्धिमानी व धैर्य के साथ करें

संकलित

प्रेरणा

उस समय द्वारका में सत्राजित नाम का व्यक्ति था, वह सूर्य भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। इस मणि की खास बात ये थी कि ये हर रोज बीस तोला सोना देती थी। मणि की वजह से सत्राजित बहुत धनवान हो गया था। एक दिन श्रीकृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में दे देंगे तो राज व्यवस्था के लिए हमें भी थोड़ा धन मिल जाएगा। श्रीकृष्ण की बात सुनकर सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया। सत्राजित की ना सुनकर श्रीकृष्ण वहां से अपने महल लौट आए। सत्राजित का एक भाई था प्रसेनजित। प्रसेनजित ने अपने भाई को बिना बताए उसकी स्यमंतक मणि ले ली और जंगल में शिकार खेलने चला गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। प्रसेनजित के पास से स्यमंतक मणि वही गिर गई। इधर सत्राजित को अपना भाई और मणि दिखाई नहीं दी तो उसने पूरी द्वारका में ये खबर फैला दी कि कृष्ण ने मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई प्रसेनजित की हत्या कर दी है। श्रीकृष्ण ने विचार किया कि इस कलंक को मिटाना होगा। जंगल में श्रीकृष्ण को शेर के पंजों के निशान दिखाई दिए। श्रीकृष्ण मणि खोजने लगे। वहीं पास में एक गुफा के बाहर कुछ बच्चे मणि से खेल रहे थे, श्रीकृष्ण ने मणि देख ली। उस गुफा में जामवंत रहते थे। श्रीकृष्ण गुफा में पहुंचे। गुफा में श्रीकृष्ण और जामवंत का युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीकृष्ण जीते तो जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती का विवाह श्रीकृष्ण से कर दिया और स्यमंतक मणि भी दे दी।

अंतर्मन

आज की पाती

भारत-बांग्लादेश संबंधों में बढ़ता अविश्वास

भारत और बांग्लादेश के संबंध दक्षिण एशिया की कूटनीति में विशेष महत्व रखते हैं। वर्ष 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के समय भारत ने जिस प्रकार राजनीतिक, सैन्य और मानवीय सहयोग प्रदान किया, उसने दोनों देशों के बीच मैत्री और विश्वास की मजबूत नींव रखी। पिछले पांच दशकों में व्यापार, सुरक्षा, ऊर्जा, संपर्क, जल संसाधन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति तथा बांग्लादेश की विकासोन्मुख विदेश नीति ने भी संबंधों को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। इसके बावजूद हाल के वर्षों में दोनों देशों के संबंधों में तनाव और अविश्वास के संकेत दिखाई दिए हैं। दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग दक्षिण एशिया की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है।

- प्रशांत त्यागी, जदगलपुर

ट्रेंड

हर संकल्प पूरा किया

प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि उसे करके भी दिखाते हैं। चाहे जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना हो, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है।
- **राजनाथ सिंह,** रक्षा मंत्री

विदेशी ताकतें

कमज़ोर प्रधानमंत्री के राज में, भारतीय होने का मतलब है पूरी तरह बर्बाद हो जाना। विदेशी ताकतें हमारे नागरिकों को मार देती हैं। हमारी सरकार एक आज्ञाकारी नौकर की तरह चुपचाप आदेश मानती है- और हमारे नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।
-**राहुल गांधी,** सांसद, कांग्रेस

विकसित भारत की दिशा

गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेसवे, नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट और कामाख्या कॉरिडोर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। ये लाखों लोगों की उम्मीदों में निवेश और विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। - **हिमंत बिस्वा सरमा,** सीएम, असम

बिहार की समृद्ध विरासत

नालंदा की बावन बूटी साड़ी और फैब्रिक, गया की पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट और भोजपुर की पिड़िया पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग मिला है। इससे देश और दुनिया में बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मान और बढ़ेगा।
- **नीतीश कुमार,** सांसद, राज्य सभा

करंट अफेयर

भारत नवाचार का देश है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने रविवार को कहा कि भारत नवाचार का देश है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के बीच सच्ची साझेदारी है। मैक्रों यहां आयोजित 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसका उद्घाटन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा, 'हम 'मेक-इन-इंडिया' पहल का सम्मान करते हैं। फ्रांस विभिन्न क्षेत्रों में इसका हिस्सा रहा है।' उन्होंने कहा, ' 'भारत नवाचार का देश है। एआई और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम क्षेत्रों में भारत-फ्रांस के बीच सच्ची साझेदारी है।' मैक्रों ने कहा, ' 'असैन्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की गुंजाइश है, जिसमें 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स' का क्षेत्र भी शामिल है। 'भारत इनोवेट्स 2026' भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसे देश के 'डीप-टेक स्टार्टअप' और अनुसंधान उपक्रमों को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद भारत, फ्रांस और अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड को साथ लाना है।

ऑफ बीट

नाक से सांस लेने पर आपकी दौड़ हो सकती है आसान

श्वास अवचेतन है। हमें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है - यह बस हो जाता है। कम और मध्यम तीव्रता वाले व्यायाम (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के दौरान, हममें से अधिकांश लोग अपनी नाक से सांस लेते हैं और अपने मुंह से सांस छोड़ते हैं। लेकिन व्यायाम जितना अधिक तीव्र होता जाता है, उतना ही हम पूरी तरह मुंह से सांस लेने लगते हैं। हममें से अधिकांश लोग यह मानेंगे कि गहन व्यायाम के दौरान मुंह से सांस लेना सबसे अच्छी तकनीक है, क्योंकि यह हमारी मांसपेशियों तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचने में मदद देता है। लेकिन सबूत इसके विपरीत दिखाते हैं - और यह कि आपकी नाक से सांस लेना वास्तव में गहन व्यायाम (जैसे दौड़ना) के दौरान उपयोग करने के लिए एक बेहतर तकनीक हो सकती है। व्यायाम करते समय, मुंह से सांस लेने की तुलना में नाक से सांस लेने पर कम ऑक्सीजन का उपयोग होता है। हालांकि यह कोई फ़ायदा नहीं लग सकता है, लेकिन मूल रूप से इसका मतलब यह है कि शरीर कम ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए भी उतनी ही मात्रा में व्यायाम कर सकता है। और गति को अधिक समय तक बनाए रखना ही सफलता का मूलमंत्र है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

संकल्प की शक्ति ही असंभव को संभव बनाती है

चढ़ावे की चोरी

अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। सदियों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद बना यह मंदिर विश्व भर के हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि दान की राशि में हेराफेरी की बात सामने आते ही उच्चस्तरीय जांच का निर्णय क्यों नहीं लिया गया? इस मामले में जिस प्रकार एफआइआर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई, उससे अनेक सवाल खड़े होते हैं। यह विचित्र है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की भनक सबसे पहले विपक्षी नेताओं को लगी और उनकी ओर से आवाज उठाने के बाद ही मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। इससे तो यही इंगित होता है कि दान में मिले धन के प्रबंधन की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। कम से कम अब तो ऐसा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यह समझना कठिन है कि चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इससे इन्कार क्यों किया कि इस तरह की कहीं कोई घटना हुई है? इसके उपरांत जब दान राशि की गिनती से जुड़े लोगों के ठिकानों से लाखों रुपये मिले, तब जाकर इस मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाई गई। इनमें से कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं, जिन्होंने महंगी संपत्ति खरीदी और अपने वैभव का सार्वजनिक प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। इस सबको देखते हुए यह कहना कठिन है कि दान की राशि में हेराफेरी का सिलसिला पिछले कितने समय से चला आ रहा था।

यह ठीक है कि अंततः ट्रस्ट के आग्रह पर एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है। यह जांच दल दानपात्रों के सुरक्षा प्रबंध के साथ राशि गिनने और उसे बैंक में जमा करने की प्रक्रिया जांचेगा, लेकिन उचित यह होगा कि यह दल उन कारणों की तह तक भी जाए, जिनके चलते आरंभ में ही चढ़ावे की राशि में हेराफेरी का पता नहीं चल सका। किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि इतने प्रतिष्ठित मंदिर में पहले दिन से ही ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि दान में मिली पाई-पाई का रखरखाव सही तरीके से हो? किसी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि प्रारंभ में ही उस कक्ष में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, जिसमें दानपात्रों को खोला जाता था और फिर राशि की गिनती होती थी। उचित यह होगा कि विशेष जांच दल अपनी छानबीन इस तरह करे कि सभी दोषी पकड़े जाएं और ट्रस्ट के जिन भी लोगों ने अपेक्षित जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया, उन्हें भी जवाबदेह बनाया जाए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्रद्धा का कोई भी केंद्र हो, वहां यदि भक्तों के दान की राशि के साथ किसी भी तरह की हेराफेरी होती है तो उनकी आस्था को गहरी चोट पहुंचती है।

समृद्धि पथ

केएमपी और केजीपी एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर प्रस्तावित "सेंट्रल एनसीआर" की अवधारणा हरियाणा के विकास मानचित्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। यह केवल क्षेत्रीय पुनर्गठन का प्रस्ताव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास संरचना को अधिक व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख बनाने का प्रयास है। पिछले दो दशकों में दिल्ली के आसपास आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है, लेकिन विकास का बड़ा हिस्सा कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही केंद्रित रहा। ऐसे में 135 किलोमीटर लंबे केएमपी कारिडोर को औद्योगिक, आवासीय और शहरी विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना दूरगामी महत्व रखती है। पंचग्राम परियोजना, नए ग्रीनफील्ड शहर, औद्योगिक नगर और मल्टीमाडल परिवहन केंद्र इस सोच को मजबूत आधार प्रदान करते हैं। इस प्रस्ताव की विशेषता केवल नए अवसर पैदा करना नहीं, बल्कि विकास और नियमन के बीच संतुलन स्थापित करना भी है। एक ओर दिल्ली से काफी दूर स्थित क्षेत्रों को एनसीआर की अनावश्यक बंदिशों से राहत देने का प्रयास है, वहीं दूसरी ओर प्रमुख आर्थिक गलियारों को नई पहचान देकर निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने की तैयारी दिखाई देती है।

> सड़कें केवल आवागमन नहीं, बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार की दिशा तय करने लगें, तब विकास का नया भूगोल आकार लेता है

सत्ता के विस्तार की भाजपाई रणनीति

राजकुमार सिंह

अपने लिए अनुकूल अन्य दलों के ऐसे संभावनाशील नेताओं की लंबी सूची है, जिन पर दांव लगा कर भाजपा तीन-चौथाई भारत की सत्ता तक पहुंच गई

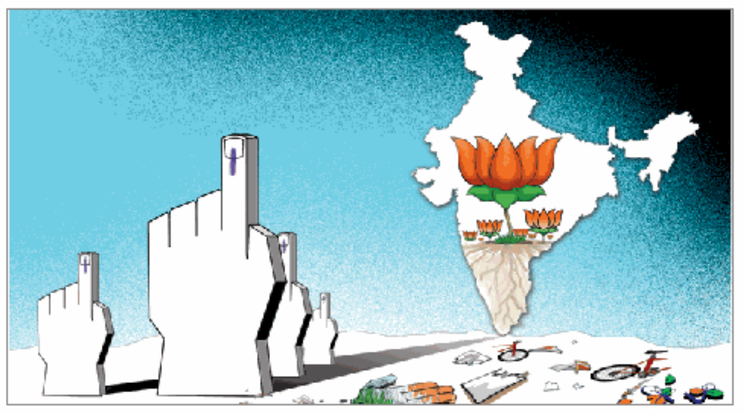

अवधेश राजपूत

सरकारों द्वारा अपने 100 दिन का भी जश्न जोर-शोर से मनाने के दौर में नरेन्द्र मोदी सरकार का 13वें वर्ष में प्रवेश बड़ी उपलब्धि है। लोकसभा में मात्र दो सीटों से शुरुआत करने वाली भाजपा के लिए यह ऐतिहासिक उपलब्धि भी है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार उसकी सरकार होने के साथ ही 22 राज्यों में भी उसकी या उसके नेतृत्व वाले राजग की सत्ता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में साढ़े चार दशक में सत्ता का ऐसा सफर किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रेरक हो सकता है और लक्ष्य भी। भाजपा के पूर्ववर्ती जनसंघ को सीमित सत्ता-सफलताएं गैर कांग्रेसी दलों से गठबंधन में ही मिलीं। हालांकि 1980 में जनसंघ ने भाजपा के रूप में अपनी पृथक वैचारिक पहचान की राह पर लौटने का फैसला किया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के लिए उपजी सहानुभूति लहर में हुए 1984 के अपने पहले ही चुनाव में भाजपा मात्र दो लोकसभा सीटों पर सिमट गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गजों के नेतृत्व में भी भाजपा को राजनीतिक स्वीकार्यता और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के आरोपों की पृष्ठभूमि में कांग्रेस विरोधी माहौल में हुए 1989 के लोकसभा चुनाव से केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार सत्तारूढ़ होने में वाम मोर्चा और भाजपा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रीय मोर्चा के मुख्य घटक जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह-देवीलाल और चंद्रशेखर के बीच सत्ता संघर्ष से ही मंडल-कमंडल के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ, जिससे कांग्रेस कमजोर होती गई और भाजपा मजबूत। कांग्रेस की कमजोरी उसकी संगठनात्मक निष्क्रियता का भी परिणाम रही, जबकि भाजपा ने लगातार कड़ी मेहनत से 'मंडल' को भी 'कमंडल' में समाहित करते हुए जनाधार का विस्तार किया। 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति की लहर से कांग्रेस पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में केंद्र में अल्पमत सरकार बनाने में तो सफल हो गई, लेकिन पहली बार 120 सीटों के साथ भाजपा मुख्य विपक्षी दल बन गई।

राव सरकार की विदाई के बाद 1996 में 161 सीटों के साथ लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी भाजपा पहली बार केंद्र में सरकार बनाने में सफल हुई, लेकिन विश्वासमत हासिल करने से पहले ही 13वें दिन वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़े दल के विरुद्ध राजनीतिक गोलबंदी से बनी कांग्रेस की कठपुतली गठबंधन सरकारों को मतदाताओं ने जनादेश का अपमान माना और 1998 में भाजपा को 182 सीटों के साथ फिर सबसे बड़ा दल बना दिया। इस बीच भाजपा ने अन्य दलों के साथ रिश्ते बनाते हुए राजग का भी विस्तार किया, लेकिन शह-मात के खेल में सरकार साल भर ही चल पाई। बहुचर्चित कारगिल प्रकरण के बावजूद 1999 में भाजपा की सीटें आश्चर्यजनक रूप से न बढ़ीं, न घटीं, लेकिन 'शाइनिंग इंडिया' की आत्ममुग्धता का शिकार होकर समय पूर्व लोकसभा चुनाव कराने से पहले वाजपेयी सरकार स्थिर ही नजर आ रही थी। वाजपेयी सरीखे विराट राजनेता को राजनीति में 'नौसिखिया' बताई जा रहीं सोनिया गांधी ने गठबंधन की बिसात से 2004 के लोकसभा चुनाव में मात दे कर देश-दुनिया को चौंका दिया। खुद प्रधानमंत्री बनने के बजाय सोनिया ने मनमोहन सिंह को चुना, जिनके नेतृत्व में 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1984 के बाद पहली बार 200 सीटों का आंकड़ा भी पार कर गई, जबकि भाजपा 138 से फिसलते हुए 116 पर जा पहुंची।

मनमोहन सरकार के पतन के बाद मोदी के नेतृत्व में चार दशक बाद पहली बार किसी दल को अपने दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और उसके बाद देश के राजनीतिक इतिहास ने एक नई करवट ली। भाजपा ने राजनीतिक रूप से अनुर्वर समझे जाने वाले राज्यों में भी अपनी सत्ता का जैसा विस्तार किया है, वह अप्रत्याशित ही कहा जाएगा। मोदी के 'कांग्रेसमुक्त भारत' के नारे की अब भी चर्चा हो ही जाती है, लेकिन भाजपा के अभूतपूर्व विस्तार में विपरीत विचारधारा वाले अन्य दलों से आए नेताओं की भी एक बड़ी भूमिका रही है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या कांग्रेसियों की ही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं का अक्सर उल्लेख करते हैं। बेशक भाजपा ने कांग्रेस, खासकर नेहरू परिवार की छवि को कमजोर कर सकने वाले हर कांग्रेसी के लिए अपने दरवाजे खोले, लेकिन खुद को मजबूत बनाने वाले कांग्रेसियों पर विशेष फोकस भी किया। परंपरागत भाजपाई एजेंडा से अप्रभावित रहे पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगर आज भाजपा या राजग सरकारें हैं, तो उसमें उस रणनीतिक जोड़तोड़ की बड़ी भूमिका है।

भाजपा की इस दोहरी राजनीतिक रणनीति का सबसे बड़ा उदाहरण हिमंत बिस्वा सरमा हैं, जिन्होंने असम गण परिषद से राजनीति शुरू की और फिर कांग्रेस सरकारों में भी मंत्री रहे। गोगोई परिवार के प्रति मोह के चलते राहुल गांधी द्वारा भाव न दिए जाने पर हिमंत ने 2015 में कांग्रेस छोड़ी। लगभग पूरे पूर्वोत्तर में भाजपाई सत्ता का विस्तार करवाने के बाद उन्हें 2021 में असम का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिनके नेतृत्व में इस बार भाजपा ने 126 में से मात्र 89 सीटों पर लड़कर 82 सीटों के साथ अकेले दम बहुमत हासिल करने का करिश्मा कर दिखाया। दरअसल अपने लिए अनुकूल अन्य दलों के ऐसे संभावनाशील नेताओं की लंबी सूची है, जिन पर दांव लगा कर भाजपा तीन-चौथाई भारत के सत्ता सिंहासन तक पहुंची है। 'कमल' थाम कर सत्ता सिंहासन तक पहुंचने वाले गैर-भाजपाई मूल के सबसे नए मुख्यमंत्री बंगाल में सुवेंदु अधिकारी हैं, जबकि बिहार के पहले भाजपाई मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि भी राजद और जदयू की है। जातीय हिंसा के चलते मणिपुर का मुख्यमंत्री का पद छोड़ने वाले एन. बीरेन सिंह, अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा भी इसी भाजपाई रणनीति के उदाहरण हैं। बेशक भाजपा दावा करती है कि वह विचारधारा से विचलित नहीं हुई, बल्कि अन्य दलों के नेताओं ने उसकी विचारधारा को अपनाया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

वैश्विक चिंताओं से निपटने की चुनौती

डा. जयंतीलाल भंडारी

वैश्विक चुनौतियों के बीच अभी भारत की आर्थिक रफ्तार नहीं थमी है, लेकिन ये चुनौतियां आगे राह बाधित कर सकती हैं

विषम स्थितियों में भी भारत का बेहतर प्रदर्शन। प्रतीकात्मक

हाल में विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में वैश्विक विकास दर घटकर 2.5 प्रतिशत रह जाएगी, वहीं भारत 6.6 प्रतिशत विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वस्तुतः वैश्विक आर्थिक झटकों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था डिजिटल विकास, जीएसटी-आयकर सुधार, परमाणु ऊर्जा, व्यापार समझौते, सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचा और मैन्यूफैक्चरिंग विकास से बेहतर स्थिति में है। सरकार तेजी से रिफार्म, परफार्म और ट्रांसफार्म के मंत्रों के साथ संरचनात्मक सुधारों को गति देते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। इसकी बदौलत वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.7 प्रतिशत की दर से वृद्धि की है। यह वित्त वर्ष 2024-25 की 7.1 प्रतिशत की विकास दर के मुकाबले बेहतर है। स्पष्ट है कि देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी बनी हुई है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और सब्सिडी के भारी बोझ के बावजूद आर्थिक रफ्तार नहीं थमी है, लेकिन चालू वित्त वर्ष 2026-27 में पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत के सामने भी आर्थिक चुनौतियां और बढ़ेंगी। अतः भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नए उपाय सुनिश्चित करने होंगे। इसके लिए सरकार को ईज आफ लिविंग (जीवन को आसान बनाने) और ईज आफ डूइंग बिजनेस (कारोबारी सुगमता) में सुधार के लिए प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ना होगा।

अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस दौरान लोगों के जीवन स्तर में सुधार, आपूर्ति शृंखलाओं में आने वाले व्यवधानों से निपटना, आर्थिक सुधारों को गति देना तथा उद्योग और व्यापार की सुगमता बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इन प्रयासों का उद्देश्य देश के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच उपलब्ध संभावनाओं का बेहतर उपयोग करते हुए विकास दर को बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना है। साथ ही रणनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ते हुए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आगामी 10 महीनों में नौ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) लागू करेगा। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता भी अगले माह के मध्य तक संभावित है। इससे देश निर्यात, विनिर्माण और निवेश का वैश्विक केंद्र बनने की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। यह कोई छोटी बात नहीं है कि जब इस समय वैश्विक निर्यात का ग्राफ तेजी से घट रहा है, वहीं अप्रैल-मई माह 2026 में भारत का निर्यात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 15 प्रतिशत बढ़ गया है। बीते वर्ष मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), आस्ट्रेलिया और चार यूरोपीय देशों-आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नार्वे और लिंकेस्टाइन के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन (एफ्टा) के साथ हुए एफटीए का लाभ मिलते दिख रहा है। हाल में भारत और ओमान के बीच भी वृहद आर्थिक एवं साझेदारी समझौता (सीईपीए) लागू हो गया है। इससे आगामी पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर 20 अरब डालर के पार पहुंचने का अनुमान है। इसके जरिये ओमान में भारत के कृषि, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा, फुटवियर और आटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को निर्यात विस्तार का अवसर मिलेगा। यह समझौता दक्षिण एशिया, खाड़ी क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीका को जोड़ने वाला एक रणनीतिक आर्थिक गलियारा स्थापित करेगा। इससे कारोबार बढ़ने के साथ रोजगार मौके भी बढ़ेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं कि भारत एफटीए की डगर पर तेजी से बढ़ रहा है। विगत दिनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी एक ऐतिहासिक एफटीए पर हस्ताक्षर हुआ और यह जल्द ही लागू होगा। भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए एफटीए तथा ब्रिटेन के साथ हुए एफटीए का भी क्रियान्वयन इसी वर्ष संभावित है। इनके साथ भारत कनाडा, इजरायल, रूस, पेरू, चिली, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने पर बात कर रहा है।

अब सरकार को अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली चुनौतियों, जैसे कमजोर मानसून, सूखे की आशंका, महंगाई, मांग में कमी तथा वित्तीय दबावों से निपटने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में विनिवेश से प्राप्त किए जाने वाले 80 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य को हासिल करने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) के प्रवाह को बढ़ाने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों पर तेजी से कार्य किया जाना चाहिए। साथ ही व्यापार से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाते हुए व्यापारिक समझौतों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन का प्रकाश

आज का युग सुविधाओं का युग है, किंतु साथ ही यह भय, असुरक्षा, तनाव और मूल्यहीनता का भी युग बनता जा रहा है। मनुष्य ने विज्ञान से बाहरी दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अपने भीतर के अंधकार को जीतने की साधना भूल गया। परिणाम यह हुआ कि संपन्नता बढ़ी, पर संतोष घटा। संपर्क बढ़े, पर संबंध टूटे। सूचना बढ़ी, परंतु आत्मबोध कम होता गया। अध्यात्म हमें सिखाता है कि संकट बाहर से नहीं, पहले भीतर से जन्म लेता है। जब विवेक सो जाता है, तब लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार मनुष्य के निर्णयों पर अधिकार कर लेते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति अपने ही बनाए जाल में उलझ जाता है। विवेक वह अंतर्दृष्टि है, जो हमें सही और गलत, शाश्वत और क्षणिक, आवश्यक और अनावश्यक के बीच भेद करना सिखाती है। आज समाज में अविश्वास, कटुता, प्रतिस्पर्धा और असहिष्णुता का माहौल बढ़ रहा है। मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है। इसका मूल कारण बाहरी अभाव नहीं, बल्कि आंतरिक रिक्तता है। अध्यात्म इस रिक्तता को भरता है। वह मनुष्य को बताता है कि जीवन केवल भोग नहीं, योग भी है। केवल उपलब्धि नहीं, अनुभूति भी है। केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। विवेक जागरण का अर्थ केवल बुद्धि का विकास नहीं, बल्कि चेतना का परिष्कार है। अध्यात्म का दीपक हमें यह समझाता है कि हर अंधकार का समाधान प्रकाश है और हर समस्या का समाधान जागरूकता।

आज आवश्यकता है कि हम घटनाओं के घटित होने की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अपने अंतर्मन को इतना जाग्रत करें कि गलत दिशा में पहला कदम उठने से पहले ही विवेक हमें सावधान कर दे। जब विवेक समय से पहले जागता है, तब व्यक्ति केवल सफल नहीं, बल्कि सार्थक बनता है। केवल जीवित नहीं रहता, बल्कि सचमुच जीवन जीता है।

ललित गर्ग

पुरुषों में स्वास्थ्य जागरूकता आवश्यक

डा. मोनिका शर्मा

स्वास्थ्य से जुड़ी देखभाल में अपनों को प्राथमिकता देने वाले पुरुष अपनी सेहत की अनदेखी करते हैं

पितृसत्तात्मक कहे जाने वाले भारतीय समाज में आज भी पुरुषों की भूमिका दायित्व उठाने के मोर्चे पर अधिक है। विशेषकर स्वास्थ्य से जुड़ी देखभाल में अपनों को प्राथमिकता देने वाले पुरुष अपनी सेहत की अनदेखी करते हैं। एक ओर जीवन की आपाधापी में शारीरिक स्वास्थ्य की उपेक्षा तो दूसरी ओर भावनात्मक उलझनों से जुड़े संवाद की कमी। बिगड़ती जीवनशैली और कामकाजी दबाव भी पुरुषों का स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। अपनों की संभाल जिम्मा उठाने वाले पिता, पति और बेटे खुद अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता नहीं लेते। अध्ययन बताते हैं कि पुरुषों की प्राथमिक जांच और देखभाल के लिए चिकित्सक के पास जाने की संभावना भी कम होती है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय पुरुष स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह घर के पुरुष सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने का संदेश देता है। इस अभियान का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पुरुषों को शारीरिक और मानसिक जांच के लिए प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य संबंधी वर्जनाओं को दूर करना है।

अंतरराष्ट्रीय पुरुष स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह, 2026 आज 15 से लेकर 21 जून तक मनाया जाएगा। विचारणीय है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में चिकित्सा सहायता लेने में जरा पीछे ही रहते हैं। वहीं स्वजन-परिजन भी पुरुषों की सेहत को लेकर सजग नहीं रहते, जिसके चलते पुरुषों में हृदय रोग, प्रोस्टेट, फेफड़ों के कैंसर और मधुमेह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हृदय रोग, कैंसर और दुर्घटना में लगी चोटें तो पुरुषों का जीवन छीनने के तीन प्रमुख कारणों में से हैं। आज की बदलती पारिवारिक व्यवस्था में प्रसवोत्तर अवसाद जैसी समस्या पिता भी झेलते हैं। उम्र के साथ हार्मोनल बदलावों की परेशानियां पुरुषों के भी हिस्से आती हैं। जीवन की जद्दोजहद मनःस्थिति को प्रभावित करती है। पारिवारिक, आर्थिक और कामकाजी परेशानियां अकेलेपन-अवसाद का भी घेरा कसती हैं। पुरुषों में बढ़ती भावनात्मक टूटन का ही परिणाम है कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट 'एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया-2024' में शादीशुदा पुरुषों की आत्महत्या के आंकड़े चिंतनीय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी वैश्विक स्तर पर पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है।

ऐसे में पुरुषों की सेहत संबंधी परेशानियों और परिस्थितियों पर चर्चा आवश्यक है। उनकी शारीरिक-मानसिक और भावनात्मक बेहतरी हेतु परिवार को भी सहयोगी बनना होगा। पुरुषों को भी न केवल अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक होने, बल्कि स्पष्ट संवाद करने की दरकार है, ताकि सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ उनकी स्वास्थ्य समस्याओं को संबोधित और प्रबंधित किया जा सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भारत की अगली उड़ान

पुनीत डालमिया का आलेख 'विकास के अगले चरण की आवश्यकता' भारत की विकास यात्रा के उस निर्णायक मोड़ की ओर संकेत करता है, जहां उपलब्धियों पर आत्ममुग्ध होने के बजाय भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार करना आवश्यक है। दुर्भाग्यवश आज भी हमारे यहां उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया कई स्तरों पर जटिल है। न्यायिक मामलों के निस्तारण में वर्षों लग जाते हैं। विश्वविद्यालयों से निकलने वाले लाखों युवाओं में बड़ी संख्या रोजगार योग्य कौशल से वंचित है। उद्योगों को कुशल जनशक्ति नहीं मिलती और युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं मिलता। यह विरोधाभास बताता है कि केवल आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। भारत को अब "लो-कास्ट इकोनमी" नहीं बल्कि "हाई-वैल्यू इकोनमी" बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। भारत के पास लोकतंत्र, जनसंख्या, नवाचार और तकनीकी क्षमता का अतिरिक्त लाभ है। यदि अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन, हरित ऊर्जा और उच्च तकनीकी विनिर्माण में आक्रामक निवेश किया जाए तो भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि विश्व का उत्पादन और नवाचार केंद्र बन सकता है। साथ ही, विकास का अगला चरण केवल उद्योग और निवेश तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक जवाबदेही, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, स्वच्छ शहर, सुरक्षित समाज और भ्रष्टाचार-मुक्त व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक हैं। भारत आज एक ऐतिहासिक अवसर के सामने खड़ा है। हमारे पास युवा शक्ति है, राजनीतिक स्थिरता है, वैश्विक विश्वास है और विकास का स्पष्ट विजन भी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अगले दशक को केवल आर्थिक विस्तार का दशक न बनाकर संस्थागत उत्कृष्टता, नवाचार, कौशल और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण का दशक बनाएं।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

मेलबाक्स

अधूरे निर्माण कार्य से परेशानी

कानपुर में इन दिनों हर तरफ विकास कार्यों का जाल बिछा हुआ है। कहीं मेट्रो निर्माण के लिए सड़कें खोदी जा रही हैं, कहीं गैस पाइपलाइन डाली जा रही है, तो कहीं बिजली और सीवर लाइनों के नाम पर रास्तों को उधेड़ा जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भविष्य को बेहतर बनाना है, लेकिन जब इन्हें बिना समुचित योजना और समय पर मरम्मत के अधूरा छोड़ दिया जाता है, तो बरसात में उनकी खामियां साफ नजर आने लगती हैं। इसी कारण हल्की सी बारिश होते ही शहर की सड़कें जलमग्न हो जा रही हैं, गड्ढे दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं।

निकिता जोशी, कानपुर

स्वच्छ भोजन, स्वस्थ भविष्य

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की नई रिपोर्ट "ग्लोबल बर्डन आफ फूडबोर्न डिजीजेज 2000-2021 में एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति सामने आई है। खेतों से लेकर घर की रसोई तक पहुंचने वाली खाद्य शृंखला में रासायनिक और जैविक प्रदूषण अब वैश्विक स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। दूषित भोजन के कारण दुनिया भर में प्रतिदिन औसतन 42 लाख से अधिक लोग बीमार पड़ रहे हैं, जबकि लगभग 4,100 लोगों की मृत्यु हो रही है। आमतौर पर फूड पाइजनिंग को केवल बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली समस्या माना जाता है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दूषित भोजन से हुई कुल मौतों में लगभग 73 प्रतिशत मौतों के लिए रासायनिक प्रदूषक जिम्मेदार थे। इनमें आर्सेनिक, सीसा (लेड) और कीटनाशकों के अवशेष प्रमुख हैं। इस रासायनिक प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव भारत और चीन पर पड़ रहा है। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के कारण भोजन में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं, एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण कई खतरनाक बैक्टीरिया इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बनते जा रहे हैं। इसलिए इस "स्लो पाइजन" की ओर समय रहते ध्यान देना और प्रभावी नियंत्रण उपाय अपनाना अत्यंत आवश्यक है।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

70 प्रतिशत तक थी भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी वर्ष 2011-2015 में, जबकि वर्ष 2016-2020 में यह 49 प्रतिशत और 2021-2025 में 40 प्रतिशत तक गिर गई, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा 36 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

आजकल

भारत की विदेश-रक्षा नीति में बदलाव

भारत की विदेश रक्षा नीति में पिछले दस वर्षों में काफी बड़े बदलाव देखने को मिला है जिसमें भारत ने अपने रक्षा आयात के क्षेत्र में काफी बदलाव किए हैं। स्टाकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 'ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स' रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 से 2025 के दौरान भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियारों को आयात करने वाला देश है जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 8.2 प्रतिशत है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि इस दौरान भारत का रक्षा आयात चार प्रतिशत तक कम हुआ है, जो इस दिशा में बढ़ती आत्मनिर्भरता का संकेतक है

राहुल पाण्डेय
रिसर्च एसोसिएट, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, दिल्ली

रक्षा क्षेत्र में भारत निरंतर मजबूती की ओर बढ़ते हुए अनेक रक्षा सामग्रियों का निर्यात भी कर रहा है। फाइल

पिछले पांच वर्षों में भारत का रक्षा आयात लगभग चार प्रतिशत तक कम हुआ है। यह देश के आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत भारत में ही सैनिक हथियारों की डिजाइन और उत्पादित करने की बढ़ती क्षमता के कारण हुआ है। भारत का कुल रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये है जो अब तक के हिसाब में सबसे अधिक है जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 62.66 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

भारत की सुरक्षा चुनौतियां चीन, पाकिस्तान और हाल के महीनों में बांग्लादेश में फैले कट्टरपंथ की वजह से काफी बढ़ चुकी हैं और इनसे निपटने के लिए भारत को काफी मात्रा में अपनी सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना होगा। चीन से 2020 हुए गलवन और पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में पिछले साल आतंकी हमला करने के बाद हुए सीमित हमलों ने देश की रक्षा नीति को मजबूत करने पर मजबूर कर दिया है और इसके अलावा वैश्विक स्तर पर फैले युद्ध की गूंज ने देश को खुद के ही रक्षा प्रणालियों को विकसित करने पर जोर देने का काम किया है। चीन का पाकिस्तान को सैन्य समर्थन एक अलग तरह का संकट पैदा करता है। इसके लिए भारतीय सेना को हर तरफ से मजबूत करने पर बल देना होगा। हालांकि, भारत अभी भी विदेशी निर्भरता से उबर नहीं पा रहा है।

रक्षा आयात में कमी : शीत युद्ध के समय से ही रूस भारतीय रक्षा ढांचे का आधार रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत की एक देश से निर्भरता हटा कर अन्य देशों की तरफ देखने की नीति ने रूस से आने वाले रक्षा आयात को कम कर दिया है। सिपरी के अनुसार, रूस से रक्षा आयात पिछले दस वर्षों में साल दर साल गिरावट दर्ज की है। रूस खुद भी यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल होने के कारण स्वयं के रक्षा व्यापार को नहीं बढ़ा पा रहा है। हालांकि भारत का रक्षा आयात रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले से ही कम होता जा रहा था।

आंकड़ों के अनुसार, भारत के हथियार आयात में रूस की हिस्सेदारी वर्ष 2011-2015 में 70 प्रतिशत से 2016-2020 में 49 प्रतिशत और 2021-2025 में 40 प्रतिशत तक गिर गई है और अभी यह आंकड़ा लगभग 36 प्रतिशत के आसपास है। वर्ष 2008-2012 में रूस से आयात 79 प्रतिशत से 2013-2017 में 62 प्रतिशत तक घट गया। भारत का वार्षिक हथियार आयात 2008 में 5.2 अरब डालर से 2014 में 7.6 अरब डालर तक बढ़ा, फिर 2019 में 8.7 अरब डालर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। घरेलू उत्पादन में आंशिक सुधार के साथ 2024 में आयात 7.5 अरब डालर पर पहुंच गया।

स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति शृंखला प्रभावित : इस बीच यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के रक्षा औद्योगिक आधार पर दबाव बढ़ गया है। उसे अपने कारखानों को घरेलू आवश्यकताओं के लिए मोड़ना पड़ा है, जिससे भारत के लिए क्षा प्रणालियों की डिलीवरी में देरी हुई और स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति शृंखला बाधित हुई।

इसी साल मार्च में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 25 अरब डालर के रक्षा पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें रूस से 6.1 अरब डालर मूल्य की पांच अतिरिक्त एक-400 ट्रायंफ हवाई रक्षा प्रणालियों का फालो-आन आर्डर और सेना के लिए तुंगुस्का मिसाइल प्रणालियों का अनुबंध शामिल है। यह निर्णय पिछले साल मई में पाकिस्तान के साथ हुए लड़ाई के दौरान रूसी एक-400 प्रणालियों ने जे-10 लड़ाकू विमानों को दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारतीय रणनीतिकारों ने इस 6.1 अरब डालर के आर्डर को मूल 2018 के 5.43 अरब डालर के अनुबंध की निरंतरता के रूप में तैयार किया है, यह भारत के पुराने सू-30 एमकेआई लड़ाकू विमानों (रूस से 2.48 अरब डालर), आइएनएस विक्रमादित्य (रूस से 2.35 अरब डालर), टी-90एस भीष्म टैंक (रूस से 1.2 अरब डालर), ब्रह्मोस संयुक्त उद्यम (रूस से 1.1 अरब डालर) और एके-203 राइफल सह-उत्पादन (रूस से 67 करोड़ डालर) जैसे पारंपरिक व्यवस्था के रखरखाव की आवश्यकता को दर्शाता है। इसका मुख्य लक्ष्य अपने पुराने रक्षा प्रणालियों को आज के दौर के लिए आधुनिक बनाने और नए पश्चिमी प्रणालियों के प्रवेश के बीच व्यावहारिक संतुलन बनाना है।

सैन्य सामग्री की बिक्री : भारत की रक्षा आयात अब रूस से कम होने के बाद अन्य देशों जैसे फ्रांस, इजरायल और अमेरिका से बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार, फ्रांस की हिस्सेदारी 2008-2012 में 0.8 प्रतिशत से बढ़कर 2013-2017 में 4.6 प्रतिशत, फिर 2015-2019 में 10 प्रतिशत और 2021-2025 के बीच 29 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से 36 राफेल जेट सौदे (8.7 अरब डालर) और आगामी 26 राफेल-एम नौसैनिक विमानन सौदे (6.2 अरब डालर) के कारण हुई है। इसके अलावा, इसी जून में भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस की सरकार को एक अनुरोध पत्र भेजकर औपचारिक रूप से इस खरीद प्रक्रिया की शुरुआत की है। इससे पहले, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फरवरी 2026 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। फ्रांस, रूस के बाद भारत को सैनिक सामग्री बेचने में अग्रणी देश बनकर उभरा है।

फ्रांस के बाद इजरायल की हिस्सेदारी भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। इजरायल की हिस्सेदारी 2008-2012 में 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 2013-2017 में 11-15 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इजरायल ने अभी तक भारत को विशिष्ट तकनीकों जैसे बराक-8 हवाई रक्षा संयुक्त विकास, ईएलएम/ एम-2084 रडार और बार्डर सर्विलांस सिस्टम, इलेक्ट्रानिक वारफेयर और स्पाइक एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलों का उपयोग किया है। इजरायल का साथ भारत के मेक इन इंडिया जैसे अभियानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा, अमेरिका की भी हिस्सेदारी भारत के सैन्य रक्षा प्रणाली के आयात में काफी बढ़ी है। अमेरिका ने 2008-2012 में अपनी बाजार हिस्सेदारी को 2.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 2013-2017 में 15 प्रतिशत कर ली थी, जो वर्तमान में 13 प्रतिशत पर बना हुआ है। अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार का दर्जा देकर परिवहन विमानों, समुद्री गश्ती, अपाचे हेलीकाप्टर, एम 777 तोपखाने और एमक्यू-9बी प्रीडेटर स्ट्राइक ड्रोन जैसी उच्च-स्तरीय नेटवर्क-केंद्रित और खुफिया प्रणालियों प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदार के रूप में देखता है।

मजबूत बने रक्षा क्षेत्र का विनिर्माण ढांचा

भारत की आधुनिक रक्षा नीति में एक बड़ा विरोधाभास है कि वह एक बड़ा वैश्विक खरीदार और तेजी से बढ़ता वैश्विक विक्रेता दोनों है। हालांकि, फ्रांस से 140 अतिरिक्त लड़ाकू विमानों और जर्मनी से छह अगली पीढ़ी की पारंपरिक पनडुब्बियों के सौदों से यह स्पष्ट होता है कि भारत अभी भी विदेशी प्राणियों पर निर्भर है। पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने ब्रह्मोस को खरीदने पर समझौते किए हैं, जिनमें फिलीपींस सबसे आगे हैं। वहीं आपरेशन सिंदूर के सफल प्रयोग के बाद ब्रह्मोस को खरीदने की मांग कई अन्य देशों से भी आई है जिसमें वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण-पूर्वी देश शामिल हैं।

हालांकि भारत को अपने सैन्य-उद्योग के आधार को अधिक विकसित करने की जरूरत है जिसमें निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अनुसंधान और विकास को कहीं अधिक मात्रा में बढ़ाने की जरूरत है। हाल के सिपरी के आंकड़ों के अनुसार, किसी कंपनी का कुल बाजार मूल्य (मार्केट कैपिटलाइजेशन) विश्व की सबसे बड़ी 100 रक्षा संबंधी कंपनियों में भारत की सिर्फ तीन, चीन की आठ, जापान की पांच, दक्षिण कोरिया की चार, फ्रांस की चार, यूनाइटेड किंगडम की सात और अमेरिका की 39 कंपनियां हैं। इसमें भारत की वैश्विक हिस्सेदारी सिर्फ 1.1 प्रतिशत है, वहीं चीन की 13 और अमेरिका की 49.2 प्रतिशत प्रतिशत है। सैन्य-उद्योग के आधार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की तर्ज पर डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट जैसे संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे सेना, सरकार और बाजार का समझौता हो और नौकरशाही के फंदे से बचाया जा सके।

रक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत घरेलू खरीद लक्ष्य को पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक आधारभूत ढांचा पहले से मजबूत होना चाहिए। अगर केवल घरेलू खरीद के लक्ष्य को हासिल करना जरूरत बना दी गई तो वो अभी इस दौर में जब दुनिया कई बड़े युद्धों के बीच में फंसी हुई है, घातक हो सकता है। भारत सह-विकास और सह-उत्पादन के माध्यम से विदेशी तकनीकों को शामिल करके अपनी ऐतिहासिक आयात निर्भरता को सहयोगात्मक और संप्रभु क्षमता में बदल रहा है, जो कि काफी जरूरी भी है। भारत की राष्ट्रीय हवाई सुरक्षा के आगामी ढांचे में बहुस्तरीय रणनीति सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

भारत की विदेश रक्षा नीति अब अपने शीत युद्ध के दायरे से बाहर आकर स्वयं को आत्मनिर्भर करने के साथ-साथ किसी एक देश पर ज्यादा निर्भरता न हो इस पर ध्यान देने की है। रूस के साथ पुराने रिश्ते को मजबूत करने के साथ-साथ, अपनी निर्भरता को पश्चिमी देशों के साथ साझा करने के अभियान के तहत स्वयं को मेक इन इंडिया के लक्ष्यों को पूरा करना भी है। वैश्विक अस्थिरता के दौर में यह अनुकूल परिस्थिति है कि भारत स्वयं को मजबूती के साथ अपने सैन्य ढांचे को मजबूत करें और आने वाले खतरे से लड़ने के लिए तैयार रहे, इसलिए आत्मनिर्भरता के साथ-साथ अपने आयात के सीमित विकल्पों से निकल अन्य रास्तों को देखने की जरूरत है।

(राहुल पाण्डेय)

खरी-खरी

दुश्मन न करे...

विनय कुमार पाठक

कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके रहते दुश्मन की कोई आवश्यकता नहीं होती। इंदीवर ने ऐसे ही दोस्तों के लिए कहा है, दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है...। ऐसे दोस्त गाना तो गाकर सुनाते हैं, ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से प्यारी है...। पर जो हरकत वे कर बैठते हैं अपने दोस्त के साथ, दोस्त को कहना पड़ता है, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया...।

बात हो रही है भारत के अभिन्न दोस्त अमेरिका और ईरान की। दोस्ती का दंभ भरते-भरते अमेरिका भारत पर ट्रैरिफ लगा देता है। भारत को 'हेलहोल' बता देता है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को मृतप्राय बता देता है। कभी भारत को ट्रैरिक किंग बताते हुए यह राग अलापने लगता है कि भारत वर्षों से अमेरिका से लाभ लेता रहा है और अमेरिकी आयात पर टैरिफ से नुकसान पहुंचाता रहा है।

जिन भारतीयों के दम पर उसकी कंपनियां ऊंचे मुकाम हासिल करती हैं, उन्हीं कंपनियों को भारतीय लोगों को जाब देने के खिलाफ विष वमन करने लगता है।

वैसे यह काम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा किया जाते हैं। पर वे भी हमारे मोदी जी के परम मित्र खुद को घोषित करते हैं और फिर अपने मित्र के देश के खिलाफ अनाप शनाप बकते रहते हैं।

अभी की बात करें तो आए दिन होर्मुज से गुजर रहे भारतीय जहाजों पर मैत्रीपूर्ण तरीके से बम बरसवा देते हैं। इसके की भारतीय काल के ग्रास बन जाते हैं। ईरान भी हमारा दोस्त होने का दम भरता है। पर अभी होर्मुज में भारतीय जहाज पर आक्रमण करने से परहेज नहीं करता। अभी हमारे जहाज पर आक्रमण जहाज को तो नुकसान हुआ ही, हमारे तीन साथी की मौत हुई है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ये दोनों दोस्त एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं।

दरअसल अमेरिका किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता है। जहां तेल देखता है वहां खेल शुरू कर देता है। कानपुर की मशहूर मिठाई की दुकान ठग्गू के लड्डू के लोकप्रिय स्लोगन, 'ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं' की तर्ज पर इसका अघोषित स्लोगन है 'ऐसा कोई दोस्त नहीं, निकालें जिसका गोश्त नहीं' है।

पोस्ट

एक तरफ संख्या बढ़ाने की जिद और दूसरी तरफ अपना घर बचाने का संघर्ष। दिल्ली में तृणमूल सांसदों के साथ शुभेंदु अधिकारी बैठक कर रहे हैं तो मुंबई में मातोश्री में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के सांसदों की मीटिंग बुलाई है। उनके नौ सांसद हैं। आपरेशन लोटस का रुख अब उधर की ओर बताया जा रहा है। पंकज झा@pankajjha_

तमाम कांग्रेस समर्थक और उससे सहानुभूति रखने वाले सोचते हैं कि बंगाल में ममता या किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दलों के पतन का अर्थ कांग्रेस का स्वत: उत्थान है। वे मानते हैं कि अंतत: मुस्लिम वोट बैंक उन्हीं के पास रहेगा और इस बहाने वे फिर से पार्टी खड़ी कर सकते हैं। यही राजनीतिक आलस्य की पराकाष्ठा है। सुशांत झा@jhasushant

नेताओं के वे बच्चे जिनका राजनीति से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, उनके बारे में इंटरनेट मीडिया पर गंदी टिप्पणियां करना और उन पर निशाना साधना बेहद गिरी हुई हरकत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार के सदस्यों पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

अजय जायसवाल
उप राजनीतिक संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

चुनावी रण से पहले संदेशों की सियासत

नई दिल्ली में संजय निषाद समेत राजग के तमाम नेताओं से भेंट करते नरेन्द्र मोदी। फाइल

राजनीति में कभी-कभी एक तस्वीर, एक मुलाकात या फिर एक सार्वजनिक बयान भी आने वाले समीकरणों का संकेत बन जाता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और उसके सहयोगी दलों के रिश्ते भी कुछ इसी दौर में हैं। एक ओर सहयोगी दलों के नेता समय-समय पर सरकार और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन की एकजुटता का प्रदर्शन करने में जुटा है।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ सहयोगी दलों के नेताओं की झालमुड़ी खाते हुए तस्वीरें सामने आईं तो इसे गठबंधन राजनीति के बड़े संकेत के रूप में देखा गया। इसकी वजह भी थी, क्योंकि आयोजन से ऐन पहले यूपी में राजग के सहयोगी संजय निषाद ने गाजीपुर मुठभेड़ पर अपनी ही सरकार से अलग लाइन लेकर कयासों को हवा दे दी थी। पहले भी वह कई बार इस तरह के संकेत देते रहे हैं, वहीं पिछले वर्ष अपना दल सोनेलाल के नेतृत्व ने भी परोक्ष रूप से प्रदेश में भाजपा की नीयत और नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि, माना जा रहा है कि कभी खट्टे तो कभी तीखे इन सियासी संदेश के बीच नरेन्द्र मोदी द्वारा परोसी गई झालमुड़ी गठबंधन के चुनावी स्वाद को मीठा बनाए रखेगी। वहीं विपक्षी दल, राजग की इस खटपट पर पूरे कान लगाए हुए हैं।

हाल ही में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने कमलेश बिंद हत्याकांड को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने यह तक कह दिया था कि हम अपने समाज के हित के लिए सरकार के साथ खड़े हैं, यदि ऐसा नहीं होगा तो हम इस पर विचार करेंगे। इससे पहले अपना दल (सोनेलाल) के नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने पिछले वर्ष किसी का नाम लिए बिना अपनी पार्टी के विरुद्ध साजिश रचे जाने का आरोप लगाया था। हालांकि, तब और अब दोनों सहयोगी दलों के नेताओं के बयानों को चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक हैसियत दर्ज कराने की कोशिश माना गया था। दरअसल, उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगातार चुनावी सफलता का बड़ा आधार केवल पार्टी संगठन या मोदी-योगी की लोकप्रियता ही नहीं है। वर्ष 2017 के बाद से भाजपा ने गैर-यादव पिछड़े, अति पिछड़े और कुछ दलित समुदायों को साथ जोड़कर व्यापक सामाजिक गठबंधन खड़ा किया। इस सामाजिक गठबंधन को मजबूत बनाने में निषाद पार्टी, अपना दल (एस), राष्ट्रीय लोकदल और समय-समय पर सुभासपा जैसे दलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस आवश्यकता को कहीं और बढ़ाया ही है। वर्ष 2019 के नतीजों के मुकाबले भाजपा पिछले चुनाव में सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, जबकि सपा 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई। भाजपा को पता है कि चुनावी बढ़त के लिए सहयोगी दलों के सामाजिक आधार को और मजबूती से साथ रखने की जरूरत है। एक तरफ तो भाजपा चाहती है कि सहयोगी दल उसके साथ मजबूती से जुड़े रहें, लेकिन इतना भी मजबूत न हो जाएं कि सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अत्यधिक दबाव बना सकें। वहीं, सहयोगी दल चाहते हैं कि उनका स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व भी बना रहे और गठबंधन का लाभ भी मिलता रहे। ऐसे में दोनों के बीच संतुलन साधने के लिए चुनाव से पहले भाजपा अब संवाद से सब ठीक रखने की रणनीति पर चल रही है। दिल्ली में राजग सम्मेलन भी इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। सहयोगी दल भी इस हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं। संजय का बयान हो या आशीष की तल्ख टिप्पणियां, दोनों को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रमुख मुद्दों के साथ सीट बंटवारे आदि पर सहयोगी दलों की आवाज और मुखर हो सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी की झालमुड़ी वाली तस्वीरों का महत्व भी यहीं से समझ आता है। राजनीतिक रूप से संदेश तो यही था कि राजग में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं हैं। भाजपा नेतृत्व यह संकेत देने में सफल रहा कि गठबंधन के सभी सहयोगी सम्मानित भागीदार हैं। विशेष रूप से ऐसे समय में जब विपक्ष लगातार यह आरोप लगा रहा है कि भाजपा सहयोगी दलों को केवल चुनावी उपयोगिता के नजरिये से देखती है। राजग के सहयोगी छोटे दलों के अलावा यूपी में दूसरे छोटे दलों का भी एक ध्रुव और खड़ा हो रहा है। इसमें सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व वाली आजाद समाज पार्टी कांशीराम, असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम शामिल है। बसपा के कमजोर होने से बनी जगह में चंद्रशेखर खुद को दलित नेतृत्व के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो ओवैसी मुस्लिमों में अपनी पैठ बढ़ाने के लक्ष्य पर केंद्रित है। इन दोनों के साथ कुछ और अत्यंत छोटे दलों के साथ की भी चर्चाएं हैं, ऐसे में खुद जीतें न जीतें, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बड़े दलों को हराने में वे जरूर अहम भूमिका निभा सकते हैं।

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या वनडे टीम में इशान किशन को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी दिए जाने का फैसला सही है?

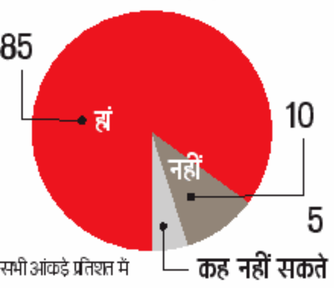

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या भारत वैश्विक झटकों को सहन करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

लुटा खजाना राम का सोए पहरेदार,
कर देंगे ये लोग फिर पूरा बंटाधार।
पूरा बंटाधार हार फिर गले पड़ेगी,
बीजेपी यह जंग अगर इस भांति लड़ेगी!
गए अयोध्या हार रोग फिर भी ना जाना,
हैं बेसुध सब लोग राम का लुटा खजाना!!
-ओम प्रकाश तिवारी

छत्तीसगढ़ डायरी

नदियों का संरक्षण और लोकभवन की चिंता

डा. सुनील गुप्ता
संपादकीय प्रभारी, बिलासपुर

मौसम के बदलते स्वरूप ने विज्ञानियों को तो अचरज में डाला, किसान से लेकर आम आदमी भी हैरान और परेशान हैं। भीषण गर्मी का दौर अब भी जारी है, छत्तीसगढ़ में मानसून के आने में थोड़ा विलंब है, हालांकि बस्तर में वर्षा प्रारंभ हो गई है। बस्तर के अलावा मैदानी इलाका और उत्तर छत्तीसगढ़ अभी भी गर्म है।

इस बीच उत्तरी छत्तीसगढ़ में जिस तरह मौसम का स्वरूप निरंतर बदल रहा है, यह विज्ञानियों के लिए चुनौती और चेतावनी से कम नहीं है। बस्तर में वर्षा की शुरुआत हो गई है तो वहीं उत्तर बस्तर और मैदानी इलाके को अब भी बारिश का इंतजार है।

छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के चलते नदियों का स्वरूप तेजी के साथ बिगड़ने लगा है। पर्यावरण संरक्षण मंडल और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मानदंडों का न तो किसी को ख्याल है और न ही इस अनुरूप रेत घाटों में रेत की खोदाई भी नहीं हो पा रही है। रेत घाटों को तो छोड़ दीजिए, माफिया ने वैध से ज्यादा अवैध रेत घाट बना लिया है। उत्खनन और परिवहन की रफ्तार देखकर हर कोई चौंक जा रहा है।

छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी माने जाने वाली अरपा, शिवनाथ, महानदी, खारुन, पैरी से लेकर बस्तर में बहने वाली नदियों के अस्तित्व को लेकर खतरा मंडराने लगा है। रेत माफिया की दबंगई कहें या फिर दबदबा, नियम कानून इनकी जेब है। न पर्यावरण संरक्षण मंडल के मानदंडों की परवाह और न ही एनजीटी की शर्तों की चिंता। नदियों में भारी भरकम मशीनों के जरिये दिन और रात रेत की बेतहाशा खोदाई हो रही है और उसी अंदाज में परिवहन भी। जिस रास्ते से भारी वाहन गुजरते हैं वहां का तो हाल और भी बेहाल है।

प्रदेश की नदियों में बेखौफ होकर नदियों में खनन करते माफिया। फाइल

माफिया की दबंगई से आसपास के लोग खौफजदा हैं। भारी भरकम मशीनों के जरिए हो रही खोदाई के कारण नदियों के अस्तित्व को लेकर खतरा पैदा हो गया है। नदियों का स्वरूप तेजी के साथ बिगड़ रहा है कहें या बदल रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में आने वाले दिनों में भयावह दृश्य उभरकर सामने आना ही है।

नदियों का स्वरूप बिगड़ने का मतलब है, जल संरक्षण और संवर्धन के नजरिये से यह बहुत ही घातक और भयावह होगा। भूजल स्तर कहां जाएगा, यह सोचकर ही मन कांप जाता है। यह बड़ा सवाल यह है कि भावी पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं। या फिर उनको क्या संदेश दे रहे हैं। भावी पीढ़ी की भविष्य की चिंता करना और उनके लिए धरोहर के रूप में बेहतर वातावरण, बहती नदियां, स्वच्छ जल, ये सब बचाकर रखने की जिम्मेदारी हमारी ही तो है। हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कहां तक कर पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो जो कल होगा, उसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते, तब भावी पीढ़ी भी हमें माफ नहीं करेगी। हम तो जाने अनजाने अपराध ही कर रहे हैं।

लोकभवन की चिंता और सतर्क हो रही सरकार : नदियों के बिगड़ते स्वरूप, जल संरक्षण और रेत के नाम पर नदियों की हो रही बेतरतीब खोदाई को लेकर लोकभवन की चिंता सामने आई है। राज्यपाल रामेन डेका ने आला अफसरों की मीटिंग बुलाई और रेत उत्खनन के नाम पर जो कुछ चल रहा है उस पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के निर्देश भी दिए। लोकभवन की चिंता सामने आते ही सरकार भी सतर्क और सजग नजर आने लगी है। बेहतर कल के लिए नदियों का संरक्षण और संवर्धन बेहद जरूरी है। लोकभवन की तर्ज पर बिलासपुर हाई कोर्ट की चिंता भी समय-समय पर सामने आ ही जाती है। हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। प्रदेशभर की नदियों के संरक्षण के लिए कमेटी बनाने और कमेटी के सुझाव पर अमल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। रेत की खोदाई पर तय मापदंडों का पालन करने की हिदायत भी अदालत ने दी है।

ड्रोन के जरिये निगरानी : नदियों में हो रही बेतरतीब खोदाई और अवैध उत्खनन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेशभर के कलेक्टर और एसपी को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गड़बड़ी पर रोक नहीं लगने की स्थिति में संबंधित जिले के कलेक्टर और एसपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। मतलब साफ है कि कार्रवाई भी होगी और कड़ाई भी बरती जाएगी। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश और खनिज सचिव की निगरानी के बाद अब अवैध उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी ढंग से रोक लगाने के लिए ड्रोन के जरिये निगरानी की जा रही है।

दो नए यूरिया संयंत्रों में जल्द शुरू होगा उत्पादन

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रविवार को बताया कि जल्द ही दो नए यूरिया संयंत्रों में उत्पादन शुरू होगा। इन संयंत्रों की कुल सालाना क्षमता 25.4 लाख टन होगी। इससे देश की आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 100 लाख टन से ज्यादा यूरिया का आयात किया है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि 2014 से अब तक छह नए मेगा यूरिया संयंत्रों की स्थापना हुई है, जिनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 76.2 लाख टन है। (प्रेट्र)

एलआइसी अपनी बढ़ती डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए रणनीतिक निवेश या आर्गेनिक तरीके से एक फिनटेक सब्सिडियरी स्थापित करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

-आर दोराईस्वामी, सीईओ, एलआइसी

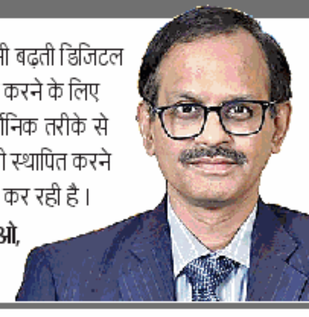

आखिर क्यों क्रेडिट कार्ड की लिमिट अचानक घटा देते हैं बैंक

नोएडा निवासी सुनील कुमार को एक दिन अचानक उनके बैंक से नोटिफिकेशन मिला, जिसमें उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटाए जाने की सूचना थी। बिना चेतावनी इस प्रकार के बदलाव से सुनील कुमार असमंजस में पड़ गए। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटाने जैसा फैसला किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई वित्तीय संकेतों के आधार पर लेते हैं। आइए जानते हैं इसके कारण...

ग्राहकों के लिए संकेत

क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटना एक प्रकार का संकेत है कि बैंक आपके वित्तीय व्यवहार की समीक्षा कर रहे हैं। इसे चेतावनी की तरह लेते हुए अपनी वित्तीय आदतों को सुधारें। यही सबसे बेहतर कदम है।

हर महीने पूरा बिल नहीं भरना

कई बार क्रेडिट कार्ड धारक लंबे समय तक पूरा बिल नहीं भरते हैं और सिर्फ न्यूनतम राशि जमा करते रहते हैं। इससे बैंक ऐसे ग्राहकों को वित्तीय स्थिति को जोखिम भरा मान सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की लिमिट को घटा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट को घटाना बैंक के लिए संभावित नुकसान से बचने का तरीका होता है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बरकरार रखने के लिए समय पर और पूरा भुगतान करें।

क्रेडिट स्कोर में गिरावट

क्रेडिट कार्ड या किसी अन्य प्रकार के लोन की किस्त समय पर जमा नहीं करने से ग्राहक के क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता है। यह भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटने का एक कारण हो सकता है। जब किसी व्यक्ति के सिबिल स्कोर में कमी आती है तो माना जाता है कि उसकी वित्तीय स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही है। ऐसे में बैंक उसकी उधार (क्रेडिट) लेने की क्षमता में कमी कर देते हैं।

बिजनेस डेस्क

क्रेडिट क्षमता का उपयोग

कई बार ग्राहक अपनी उपलब्ध क्रेडिट क्षमता का बड़ा हिस्सा लगातार खर्च करते हैं। इसका भी क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर होता है। इस प्रकार के लगातार खर्च को बैंक वित्तीय दबाव का संकेत मानते हैं और संभावित जोखिम से बचने के लिए ग्राहक की क्रेडिट क्षमता को घटा देते हैं। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना भी उसकी लिमिट घटने का कारण हो सकता है। इसका कारण यह है कि बैंकों को निष्क्रिय खातों से कम फायदा होता है।

बैंक के आंतरिक कारण

कई बार बैंक अपने आंतरिक कारणों से भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट घटा देते हैं। ऐसा आर्थिक अनिश्चितता या जोखिम प्रबंधन के चलते किया जाता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम होने का ग्राहक के क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है। लिमिट कम होने और खर्च समान रहने से कार्ड का उपयोग अनुपात बढ़ जाता है, जिससे क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

क्या करें ग्राहक

- लिमिट घटने पर ग्राहक घबराने के बजाए अपने बैंक से संपर्क कर इसका कारण समझें
- समय पर भुगतान करें और क्रेडिट उपयोग को 30 प्रतिशत से कम रखें
- अपनी आय से जुड़े दस्तावेजों को समय-समय पर अपडेट करते रहें

नोट: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। पाठक किसी भी समस्या के लिए अपने बैंक से संपर्क करें।

इस सप्ताह आइपीओ दस्तावेज जमा कर सकता है एनएसई

नई दिल्ली, प्रेट्र: नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) एक कदम और आगे बढ़ने वाले है। सूत्रों के मुताबिक, देश का सबसे बड़ा स्टाक एक्सचेंज इस सप्ताह सेबी के पास आइपीओ के लिए मसौदा दस्तावेज जमा कर सकता है।

एनएसई बोर्ड ने छह फरवरी को प्रस्तावित आइपीओ को मंजूरी दी थी, जिसे सेबी से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल गया है। यह पूरा आइपीओ आफर फार सेल यानी मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी बिक्री पर आधारित होगा और इसमें नए शेयर बिक्री के लिए पेश नहीं किए जाएंगे। एक्सचेंज के शेयरधारकों में घरेलू वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, विदेशी निवेशक और व्यक्तिगत निवेशक शामिल हैं।

एफपीआइ ने पहले पखवाड़े में 62,853 करोड़ निकाले

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की भारतीय शेयर बाजारों से निकासी जारी है और जून के पहले पखवाड़े (1-13 जून) में एफपीआइ 62,853 करोड़ रुपये से अधिक के शेयरों की बिक्री कर चुके हैं। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक विकास को लेकर चिंताओं, भू-राजनीतिक तनावों और रुपये की लगातार कमजोरी के कारण एफपीआइ बिकवाली कर रहे हैं।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, इस ताजा बिकवाली के साथ कैलेंडर वर्ष 2026 में अब तक एफपीआइ भारतीय शेयरों से 2.87 लाख करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं। यह पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 की कुल निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। बजाज ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च पवित्र मुखर्जी ने कहा कि आने वाले सप्ताह में एफपीआइ प्रवाह अमेरिका-ईरान शांति वार्ता, अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के नीति निर्णय, बैंक आफ जापान के ब्याज को लेकर किए जाने वाले निर्णय और प्रमुख केंद्रीय बैंकों की टिप्पणियों पर निर्भर करेगा।

एनएसडीएल के अनुसार, 2026 में अब तक एफपीआइ फरवरी को छोड़कर शेष सभी महीनों में शुद्ध विक्रेता रहे हैं। इस वर्ष जनवरी में एफपीआइ ने 35,962 करोड़ रुपये निकाले थे। इसके बाद फरवरी में 22,615 करोड़ रुपये का निवेश किया, जो 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक निवेश था। हालांकि, मार्च में विदेशी निवेशकों ने रिकार्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये निकाले। अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपये और मई में 32,963 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी के साथ बिकवाली का दबाव जारी रहा।

रुपये में निरंतर गिरावट भी एफपीआइ की निकासी का एक प्रमुख कारण है। 2026 में अब तक रुपया करीब छह प्रतिशत तक लुढ़क चुका है और डालर के मुकाबले 95 के स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि, आरबीआइ ने रुपये को स्थिर करने के प्रयास किए हैं।

2.87 लाख करोड़ रुपये पर पहुंची एफपीआइ की कुल निकासी वर्ष 2026 में

सरकारी प्रयासों का डेट श्रेणी में दिख रहा असर

विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआइ ने कई उपायों की घोषणा की है और इनका असर भी दिखने लगा है। जून के पहले पखवाड़े में एफपीआइ ने फुली एक्सेसेबल रूट (एफएआर) वाले डेट या बांड में 13,200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुके हैं। इसके साथ एफएआर के जरिये कुल निवेश करीब 28 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

आठ कंपनियों की पूंजी 1.90 लाख करोड़ बढ़ी

नई दिल्ली, प्रेट्र: बीते सप्ताह शेयर बाजारों में रही तेजी की बदौलत शीर्ष-10 में से आठ कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1.90 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान आइसीआइसीआइ बैंक के पूंजीकरण में सबसे ज्यादा 56,223 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एसबीआइ, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूंजीकरण भी बढ़ा। दूसरी ओर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एलआइसी के पूंजीकरण में गिरावट रही।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

किराना स्टोर की मदद करेगी डिजिदुकान

एक ही प्लेटफार्म पर लाए जा रहे छोटे दुकानदार और एफएमसीजी कंपनियां

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: ई-कामर्स एवं क्विक कामर्स से मुकाबले में पीछे छूट रहे किराना स्टोर की मदद के लिए सरकार अब डिजिदुकान का नेटवर्क तैयार कर रही है। छोटे व किराना दुकानदारों को ई-कामर्स में लाने के लिए सरकार की तरफ से विकसित ओपन नेटवर्क फार डिजिटल कामर्स (ओएनडीसी) के प्लेटफार्म पर डिजिदुकान को विकसित किया जा रहा है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) किराना दुकानदारों और एफएमसीजी कंपनियों को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास कर रहा है।

ओएनडीसी पर प्रत्येक शहर के लिए अलग-अलग डिजिदुकान प्लेटफार्म बनाया जाएगा, जिससे एफएमसीजी कंपनियां और छोटे दुकानदार जुड़े होंगे। इसके जरिये किराना व्यापारी सीधे कंपनियों से माल खरीद सकेंगे। कंपनियों को भी सीधे फीडबैक मिलेगा। पायलट के तौर पर हैदराबाद के

- प्रत्येक शहर के लिए बनाया जाएगा अलग प्लेटफार्म
- हैदराबाद से हो चुकी है पायलट प्लेटफार्म की शुरुआत

किराना व्यापारियों के लिए पहला डिजिदुकान प्लेटफार्म विकसित किया गया है। अब जयपुर, एनसीआर व मुंबई जैसे स्थानों के लिए डिजिदुकान लाई जा रही हैं। हैदराबाद की डिजिदुकान से 10,000 खुदरा व्यापारी और 35 ब्रांड जुड़ चुके हैं। हाल ही में देशव्यापी स्तर पर डिजिदुकान लांच करने को लेकर हिन्दुस्तान लीवर से लेकर कोका कोला जैसी कंपनियों के साथ डीपीआइआइटी के अधिकारियों की बैठक भी हुई।

डीपीआइआइटी के मुताबिक, डिजिदुकान से किराना व्यापारियों का लाभ बढ़ेगा और उन्हें ई-कामर्स प्लेटफार्म से जुड़ने में मदद मिलेगी। अभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियां अपना माल डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूटर छोटे दुकानदारों को सप्लाई करता है। दूसरी तरफ, ई-कामर्स पर कई बार किराना स्टोर से कम दाम में उपभोक्ता उत्पाद उपलब्ध होते हैं। ऐसे में ग्राहक किराना स्टोर से सामान खरीदना बंद कर देता है या फिर किराना व्यापारी को काफी कम मार्जिन पर माल बेचना पड़ता है। देश में 1.4 करोड़ किराना व्यापारी है।

कन्फेडरेशन आफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) का दावा है कि ई-कामर्स कंपनियों के आने के बाद से गली-मोहल्ले में चलने वाली लाखों छोटी दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि वे इन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रही हैं। ई-कामर्स के बाद क्विक कामर्स कंपनियों के आने से दूध-अंडा, ब्रेड जैसे रोजमर्रा के उत्पाद भी ग्राहक उनसे ही खरीद रहे हैं। ओएनडीसी के माध्यम से छोटे दुकानदार ई-कामर्स से जुड़कर ग्राहकों को जोड़ सकते हैं। जानकारों का कहना है कि ई-कामर्स कंपनियों ने बाजार में एक नए प्रकार की प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। इनमें कई चलन व्यापार नियम के खिलाफ है, लेकिन ग्राहकों को फायदा होता देख इसे नियंत्रित करने के लिए अब तक देश में ई-कामर्स नीति नहीं लाई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटे दुकानदारों को अब अपनी दुकानों में एक ही सामान की कई वेरायटी रखनी होगी। ई-कामर्स प्लेटफार्म पर ग्राहकों को यह सुविधा मिलती है। इस कारण भी ग्राहक ई-कामर्स की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं।

एफटीए से फर्नीचर निर्यात और घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

नई दिल्ली, प्रेट्र: हाल ही में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से भारत के फर्नीचर क्षेत्र को निर्यात और घरेलू उत्पादन को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इन व्यापार समझौतों के तहत शुल्क छूट न केवल घरेलू कंपनियों को विदेशी बाजारों में प्राथमिकता प्रदान मिलेगी, बल्कि भारत में क्षमता विस्तार और नए निवेश को भी प्रोत्साहित करेगी।

उद्योग विशेषज्ञों ने कहा, एफटीए में शुल्क छूट से घरेलू कंपनियों को विदेशी बाजारों में प्राथमिकता प्रदान मिलेगी

भारत ने मारीशस, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), आस्ट्रेलिया, ईएफटीए ब्लाक और ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किए हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के साथ ऐसे समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और यूरोपीय संघ के साथ वार्ता के समापन की घोषणा की है। इसके अलावा कई अन्य देशों के साथ भी समान व्यापार समझौतों पर बातचीत जारी है जिनमें इजरायल, कनाडा, पेरू, चिली, गल्फ कोआपरेशन काउंसिल (बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब) और यूरेशियन इकोनामिक यूनियन (आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस) शामिल हैं।

गुजरात स्थित निप्पोनप्लाई इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक केतन ठक्कर ने कहा कि ये समझौते हमें विशाल निर्यात अवसर प्रदान करेंगे। हमने पहले ही अपने निर्यात शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि फर्नीचर क्षेत्र के भारतीय उत्पाद वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इनकी अच्छी मांग है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के उपकुलपति राकेश मोहन जोशी ने कहा कि एफटीए ने भारतीय फर्नीचर क्षेत्र के लिए विशाल निर्यात अवसर खोले हैं। उद्योग को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

राष्ट्रीय फलक

साफ्टवेयर और एमबीए का दौर ढलान पर, ट्रेड स्किल सीखें युवा: नागेश्वरन

नई दिल्ली, एएनआइ : मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने युवाओं को बदलते रोजगार परिदृश्य के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि साफ्टवेयर नौकरियों और एमबीए डिग्री के दम पर करियर बनाने का दौर अब ढलान पर है। युवाओं को ट्रेड स्किल और ऐसे मानव-केंद्रित पेशों की ओर बढ़ना चाहिए, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता।

एएनआइ को दिए साक्षात्कार में नागेश्वरन ने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में भारत को साफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस और एमबीए शिक्षा का बड़ा लाभ मिला, लेकिन दुनिया अब अधिक खंडित और संरक्षणवादी होती जा रही है। ऐसे में भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाना और रोजगार योग्य कौशल विकसित करना जरूरी हो गया है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि तकनीकी प्रगति ट्रेड स्किल आधारित

सीईए बोले, एआइ के दौर में मानव केंद्रित पेशों की मांग बढ़ेगी

वी. अनंत नागेश्वरन। फाइल

रोजगार को खत्म नहीं कर सकती। इसलिए युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण और साफ्ट स्किल विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। बुजुर्गों की देखभाल, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की काउंसलिंग, अस्पताल सेवाएं, खेल शिक्षा, पाक-कला और अन्य मानव-केंद्रित क्षेत्रों में प्रशिक्षित लोगों की मांग बढ़ रही है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर एआइ का प्रभाव सीमित रहेगा।

नतीजों नहीं, जरूरी कदमों पर होता है पीएम मोदी से संवाद

सीईए नागेश्वरन ने कहा बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ उनकी बातचीत उपलब्धियों या आंकड़ों पर नहीं, बल्कि उन कदमों पर केंद्रित होती है जो देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जरूरी हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का ध्यान इस बात पर रहता है कि हमें क्या करना है। बातचीत का केंद्र परिणाम नहीं, बल्कि आवश्यक कार्रवाई होती है। नागेश्वरन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकातें आमतौर पर प्रत्येक तिमाही में होती हैं। सरकार की प्राथमिकताओं का उल्लेख करते हुए नागेश्वरन ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, परमाणु ऊर्जा, कोयला गैसीकरण, सेमीकंडक्टर विनिर्माण तथा व्यापक डी-रेगुलेशन जैसे क्षेत्रों को प्रमुख बताया।

इस वर्ष दान पर दो हजार करोड़ रुपये तक खर्च करेगा टाटा ट्रस्ट्स

नई दिल्ली, प्रेट्र : टाटा ट्रस्ट्स के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में ट्रस्ट अपने दान खर्च को लगभग 2,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। उन्होंने केवल टाटा संस में 'अराजकता' पर ध्यान केंद्रित करने वालों की आलोचना भी की। टाटा संस करीब 180 अरब डालर से अधिक के टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है।

शर्मा ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट में कहा, टाटा ट्रस्ट्स का उद्देश्य समाज के किनारे पर रहने वालों की मदद करना है। बीते वित्त वर्ष 2025-26 में ट्रस्ट्स का दान खर्च लगभग 1,600 करोड़ रुपये रहा है। इस खर्च के माध्यम से असम, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुणवत्ता के साथ सस्ती कैंसर देखभाल प्रदान की जा रही है। टाटा ट्रस्ट्स एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के साथ सहयोग कर रहा है ताकि स्नातक अध्ययन के लिए एक विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सके।

विज्ञान भारती तैयार करेगी भारत केंद्रित विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति

जागरण संवाददाता, वाराणसी

विज्ञान भारती विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नई भारत केंद्रित विज्ञान-प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति तैयार करेगी। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में आयोजित सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को देशभर से जुटे विज्ञानियों समेत विद्वानों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया। तय किया गया कि अधिवेशन में विशिष्टजन के विचारों व निष्कर्षों के आधार पर समकालीन चुनौतियों के समाधान के लिए भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित व्यावहारिक कार्ययोजना विकसित की जाए।

अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह-सरकार्यवाह डा. कृष्ण गोपाल ने कहा, भारतीय ज्ञान परंपरा में विज्ञान और अध्यात्म एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। भारतीय चिंतन में विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं, बल्कि संगीत, नृत्य, व्याकरण, आयुर्वेद, गणित और दर्शन सहित सभी ज्ञान-विधा

बीएचयू में विज्ञान भारती की ओर से आयोजित सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन के सत्र में वक्तव्य देते नीति आयोग के सदस्य डा. अभय करंदीकर व मंचासीन विशिष्टजन। जागरण

विज्ञान के व्यापक स्वरूप का हिस्सा हैं। भारतीय ज्ञान सार्वभौम है, इसका उद्देश्य सिर्फ धनोपार्जन नहीं। विज्ञान मानवता के कल्याण का साधन बने, इसके लिए उसे भारतीय ज्ञान, नैतिक मूल्यों और लोकहित की भावना से जोड़ना आवश्यक है।

समापन सत्र में मुख्य अतिथि नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर ने कहा कि विकसित भारत निर्माण के लिए वैज्ञानिक नवाचार पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत को अपनी प्राचीन वैज्ञानिक परंपराओं का अध्ययन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ करते हुए चुनौतियों के अनुरूप समाधान निकालने चाहिए।

अस्पताल में तीन साल की बच्ची को मां के सामने से उठा ले गए कुत्ते

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। रविवार देर रात बिजली गुल होने के बाद गर्मी से परेशान होकर बच्चा वार्ड के बाहर मां के साथ बैठी तीन वर्षीय बच्ची पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुत्ते बच्ची को मुंह में दबाकर कुछ दूर तक घसीटते ले गए और उसे बुरी तरह नोच डाला। मां और आसपास के तीमारदारों के शोर मचाने पर बच्ची को बमुश्किल कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया गया। गंभीर हालत में बच्ची को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया।

इरम की तीन साल की बच्ची महरबा को उल्टी-दस्त की परेशानी थी। स्वजन उसे शनिवार सुबह जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर आए थे। यहां से उपचार के बाद बच्चा वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रविवार रात लगभग साढ़े आठ बजे अस्पताल की बिजली चली गई, जिस कारण कूलर-पंखे बंद हो गए। गर्मी महसूस होने पर मां अपनी बेटी को लेकर बच्चा वार्ड के बाहर बैठ गई थी।

गाजियाबाद में ग्रीन बेल्ट में बनी अवैध मजार ध्वस्त

गाजियाबाद में अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। सौ. प्रशासन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध मजार को शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करा दिया। एसडीएम ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद भी मजार को हटाया नहीं गया था।

यूपीसीडा अधिकारियों ने ग्रीन बेल्ट पर बनाई गई मजार पर जनवरी में नोटिस चस्पा किया था। वरिष्ठ प्रबंधक सिविल एनके जैन ने बताया कि ट्रोनिका सिटी अंसल कालोनी के पास सेक्टर सी-1 की ग्रीन बेल्ट में करीब 10 साल पहले मजार अवैध तरीके से बनाई गई थी। बताया कि राजस्व अभिलेखों की जांच के बाद संबंधित निर्माण सरकारी संपत्ति में पाया गया। फिर जनवरी में मजार पर नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस का जवाब न देने पर प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता से शनिवार को मजार की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

नवाचार से वैश्विक एआइ ईकोसिस्टम में अहम रोल अदा करेगा भारत: अरुंधति

नई दिल्ली, आइएएनएस : सेल्सफोर्स साउथ एशिया की प्रेसीडेंट और सीईओ अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि अगर भारत अपनी प्रतिभा को शोध और बेहतर कौशल के साथ जोड़ ले, तो देश वैश्विक एआइ ईकोसिस्टम में बहुत अहम योगदान दे सकता है। भारत के पास एआइ में नेतृत्व करने के लिए टैलेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योरशिप वाली ऊर्जा है।

भट्टाचार्य ने बताया, भारत की खास जरूरतों से बहुत सारे नवाचार सामने आएंगे, चाहे वह मल्टीलिंगुअल एआइ हो, कम लागत वाले माडल हों या ऐसे उपाय जो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर सकें। साथ ही, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) पर और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ प्रतिभा काफी नहीं है। अगर मैंने अपने अलग-अलग पड़ावों वाले सफर से कुछ सीखा है, तो वह यह है कि बदलाव के लिए तैयार रहना, सीखते रहना और जिज्ञासु बने रहना।

कोलकाता में देश का पहला मालवाहक सड़क सुरंग बनाने की तैयारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

हुगली नदी के नीचे मेट्रो रेल चलाने के बाद अब कोलकाता में देश की पहली मालवाहक सड़क सुरंग बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से सीधे और तेज़ी से जोड़ना है। हाल में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रस्तावित परियोजना को कोलकाता पोर्ट अथारिटी और एनएचएआइ संयुक्त रूप से विकसित करेंगे। योजना के अनुसार, कुल सड़क मार्ग की लंबाई लगभग 15.7 किलोमीटर होगी, जिसमें हुगली नदी के नीचे करीब साढ़े आठ किलोमीटर लंबी जुड़वां ट्यूब सुरंग

हुगली नदी के नीचे दौड़ेंगे मालवाहक ट्रक, बनेगा 15.7 किमी लंबा कारिडोर

बनाई जाएगी। यह सुरंग नदी तल से लगभग 38 मीटर नीचे होगी।

सुरंग के लिए दो रैंप बनाए जाने की योजना : परियोजना का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह आने-जाने वाले मालवाहक ट्रकों की आवाजाही को आसान बनाना है। वर्तमान में बंदरगाह क्षेत्र में ट्रकों को अक्सर लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन सुरंग बनने के बाद चौबीसों घंटे निर्बाध आवागमन संभव हो सकेगा। कोलकाता की ओर सुरंग के लिए दो रैंप बनाए जाने की योजना है। एक रैंप एनएसडी के गेट संख्या-8 और गार्डेनरीच शिपबिल्डर्स क्षेत्र के पास होगा, जबकि दूसरा तारातला रोड के जिंजिरा बाजार इलाके से जुड़ेगा। दूसरी ओर, सुरंग हावड़ा के सांकराइल स्टेशन के निकट जमीन के ऊपर आएगी। यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग-16 तक सीधा संपर्क स्थापित किया जाएगा।

पाकिस्तानी सेना रच रही नियंत्रण रेखा पर माहौल बिगाड़ने की साजिश

जागरण संवाददाता, राजौरी : गुलाम जम्मू-कश्मीर के हालात से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान अब नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार शाम पुंछ के बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलियां बरसाईं। हमारे जवानों की ओर से त्वरित जवाबी कार्रवाई किए जाने के बाद पाकिस्तानी सैनिक बिल में दुबक गए। घटना के बाद सीमा पर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। हालांकि भारतीय सेना ने गोलीबारी की पुष्टि नहीं की है।

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान सेना ने बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। दुश्मन की ओर से 10 से 15 राउंड फायरिंग की गई। गोलीबारी शुरू होते ही भारतीय सेना के जवान सतर्क हो गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी चौकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

वीरांगनाओं को सलाम

देश की आधी आबादी के लिए यह सचमुच जश्न का समय है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) ने पहली बार 17 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया है। इनमें से नौ को सेना, पांच को वायु सेना और तीन को नौसेना में स्थायी नियुक्ति मिली है। आजादी के बाद हमारे सार्वजनिक जीवन के कुछ ऐसे कोने थे, जो आधी आबादी की पहुंच से काफी देर तक दूर रहे और यह बात लोकतांत्रिक हिन्दुस्तान के मानस को लगातार उद्वेलित करती रही। इनमें से एक कोना रक्षा का था। धर्म और रक्षा क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव साफ-साफ दिखता रहा है। धर्म जहां कई मंदिरों, दरगाहों में उनके साथ भेदभाव करता रहा, तो रक्षा क्षेत्र के दरवाजे भी दशकों तक उनके लिए बंद रहे। आखिरकार उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। जाहिर है, संविधान की कसौटी पर उनके साथ इंसाफ होना ही था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में एनडीए को महिलाओं के लिए खोलने का आदेश दिया था। अपने फैसले में आला अदालत ने साफ-साफ कहा कि सामाजिक धारणाओं के आधार पर महिलाओं को समान मौके न देना अस्वीकार्य है।

पहले महिला अधिकारियों की नियुक्ति शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिये होती थी और वर्षों की सेवा के बाद ही वे स्थायी कमीशन की योग्यता हासिल कर पाती थीं। इसी भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आला अदालत का दरवाजा खटखटाया था। बहरहाल, ये 17 वीरांगनाएं अगस्त 2022 में एनडीए का हिस्सा बनी थीं और स्थायी नियुक्ति पाने से पहले उन्होंने सेना के कठोर प्रशिक्षण की कसौटियों पर खुद को खरा साबित किया है। अब वे नेतृत्व की भूमिका में होंगी। यह क्षण भारतीय लोकतंत्र के लिए इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है, क्योंकि देश के सर्वोच्च कमांडर के ओहदे पर द्रौपदी मुर्मु पदासीन हैं, जो स्वयं एक महिला हैं। निस्संदेह, देश की आधी आबादी के लिए ये 17 बेटियां मिसाल हैं और उम्मीद है कि यहां से लड़कियों की संख्या बढ़ती जाएगी। इनकी स्थायी नियुक्ति से भारतीय सेना का यह दावा अधिक पुख्ता होगा कि वह लिंग-भेद से परे योग्यता, अनुशासन और उत्कृष्टता को महत्व देती है।

पहली बार 17 महिला अधिकारियों की स्थायी नियुक्ति से भारतीय सेना का यह दावा पुख्ता होगा कि वह लिंग-भेद से परे सिर्फ योग्यता, अनुशासन व उत्कृष्टता को महत्व देती है।

हालांकि, इन कुछ बड़ी उपलब्धियों के बावजूद हमारे सामाजिक-सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी के लिए महिलाओं को अभी लंबा सफर तय करना होगा। गौर कीजिए, आज भी पुरुष और महिला साक्षरता के बीच लगभग 13 फीसदी का फासला है। भारतीय महिलाओं ने नागरिक जिम्मेदारी निभाने में पुरुषों की बराबरी कर ली है, बल्कि उन्हें पीछे छोड़ दिया है, मगर विधायी संस्थाओं में सम्मानजनक प्रतिनिधित्व के लिए वे अब भी राह देख रही हैं। निस्संदेह, संसद और विधानसभाओं में उनके लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का कानून बन चुका है, मगर उसे अमली जामा पहनाने की कोई ठोस पहल नहीं दिखाई दे रही और सरकार व विपक्ष के बीच यह विषय झूल रहा है। इसी तरह, धार्मिक संस्थानों में भेदभाव के खिलाफ भी उन्हें अदालत से संरक्षण मांगना पड़ रहा है। सबरीमाला मामला इसका बड़ा उदाहरण है। सही मायने में औरतों को बराबरी का दर्जा देने के लिए सिर्फ सरकार को ही नहीं, बल्कि समाज को भी उदार बनने की आवश्यकता है। विडंबना यह है कि लोग तंत्र के खिलाफ अदालत में कानूनी लड़ाई लड़कर तो अधिकार हासिल कर लेते हैं, मगर समाज की रूढ़ियों से टकराने से कतराते हैं। ऐसे में, ये सफलताएं प्रतीकात्मक न रह जाएं, इसके लिए हमें महिलाओं को वास्तविक बराबरी देनी ही होगी।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले

15 जून, 1951

अहिंसक साम्यवाद

आचार्य विनोबा की तेलंगाना-यात्रा 8 जून को समाप्त हो गई और 9 जून को वह पवनार के लिए रवाना हो गये।

महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रही की यह महान यात्रा अहिंसा और प्रेम को क्रियात्मक शक्ति मानने वालों के लिए गौरव का विषय है। जो लोग इन सिद्धान्तों का परिहास करते हैं, वे भी इस यात्रा से आखें खोलकर देख सकेंगे कि सशस्त्र आतताई के घर में भुजाएं फैलाकर जाने वाला यह कोपीनधारी सत्याग्रही क्या चमत्कार करके लौटा है। उसकी वाणी पास के कानों में भी कठिनता से सुनाई पड़ती है, किन्तु उसकी आध्यात्मिक शक्ति बंगाल के अज्ञात स्थलों में छिपे हुए साम्यवादियों के हृदयों तक पहुंचाकर उन्हें हिला देने में समर्थ है। उसका सत्याग्रही व्यक्तित्व-मात्र प्रतिपक्षी को कंपित कर देने के लिए पर्याप्त है।

बीहड़ वनों को पार करता हुआ जब यह डेढ़ पसली का लंगोटिया संत तेलंगाने के साम्यवादी-त्रस्त गांवों में पहुंचता था, उस समय वहां के रक्त पिपासु साम्यवादी या तो भाग जाते थे, या उसका सिक्का मानकर उसके पदानुगामी बन जाते थे। बीसियों गांवों में यही हुआ।... आचार्य विनोबा की इस यात्रा को निर्भयता, आत्मनिर्भरता, सहकार एवं भूमि-यज्ञ के प्रचार की यात्रा कहा जा सकता है। इसमें उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

कुछ जिलों के प्रायः सभी गांवों से धनिक लोग भाग भागकर अधिक सुरक्षित शहरों में चले गये थे। उनके भय और स्वार्थ के कारण साम्यवादियों को गरीब ग्रामवासियों को भड़काने का और अवसर मिल गया था। विनोबा ने धनिकों को अपनी प्रार्थना सभाओं में बुलाया और उन्हें भय तथा स्वार्थ छोड़कर व ग्रामवासियों के सेवक, संरक्षक, मार्गदर्शक और सहायक बनकर उन्हीं ग्रामों में रहने की प्रेरणा दी। अब बहुत से धनिक अपने ग्रामों को लौट गये हैं और उन्होंने विनोबा की शिक्षा मानकर भूखे तथा नंगे ग्रामवासियों के लिए भूमिदान किया है। इस प्रकार विनोबा को लगभग 10,000 एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। विनोबा का आग्रह था कि 'भूमि-यज्ञ' प्रेम का यज्ञ है, अतएव वही दान स्वीकार होगा, जिससे दाता के प्रेम की झलक मिलेगी। भूमिदान करने वालों की संख्या लगभग 500 है। यदि इन सबने प्रेम के साथ दान किया है, तो विनोबा को नैतिक तल पर भी एक स्मरणीय सफलता प्राप्त हुई है।

सियासत में शिक्षा का मुद्दा बन जाना

शिक्षा से जुड़ा कोई भी विवाद युवाओं में अपने भविष्य को लेकर भय पैदा कर सकता है। दुनिया के कई बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि भय व संशय के इर्द-गिर्द गोलबंदी प्रभावी होती है।

बद्री नारायण | कुलपति, टीआईएसएस, मुंबई

भारत में शिक्षा का क्षेत्र दिन-ब-दिन राजनीतिक होता जा रहा है। शिक्षा से जुड़ा अब कोई भी मुद्दा या विवाद सोशल मीडिया से होते हुए विपक्ष की गोलबंदी की राजनीति से जुड़ जाता है। पिछले दिनों यूजीसी रेगुलेशन, नीट पेपर लीक और अब सीबीएसई परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जैसे मुद्दे राजनीतिक गोलबंदी का रूप ले चुके हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

अगर गहराई से देखें, तो यह परिघटना भारतीय राजनीति के लोक में हो रहे दूरगामी परिवर्तनों का सूचक है। पहले प्रायः विकास के मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत संरचनाएं या रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे विषय केंद्रीय विपक्ष की राजनीतिक गोलबंदी के मुद्दे बनते थे। अब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय सत्ता-विरोधी राजनीति के स्रोत के रूप में उभर रहे हैं। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, वस्तुतः पिछले दशकों में सरकारों ने आधारभूत संरचनाओं, जैसे राजमार्ग, ग्रामीण सड़क, बिजली, पानी से जुड़े विकास के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। फलतः इन मामलों में जनता की शकायतें कम हुई हैं। ऐसे में, ये मुद्दे अब विपक्ष को अपनी राजनीति के लिहाज से शायद ज्यादा कारगर नहीं महसूस हो रहे हैं।

दूसरा कारण यह है कि विकास की अवधारणा अब काफी व्यापक हो गई है। यह अब सर्वांगीण मानव विकास के रूप में हमारे समक्ष आई है। इस सर्वांगीण विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे धीरे-धीरे महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इसीलिए शायद विपक्ष अब महंगाई और गरीबी जैसे मुद्दों को उछालने के साथ ही मानव विकास के अन्य मानकों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के विषय में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता भविष्य तलाश रहा है।

इसका एक अहम पहलू यह भी है कि देश में युवा आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का देश माना जाने लगा है।

जाहिर है, यहां बड़ी संख्या में युवा मतदाता बन रहे हैं। अतः युवा और महिला राजनीतिक गोलबंदी के केंद्रबिंदु बनते जा रहे हैं। वैसे तो छात्र व युवा हमेशा से राजनीति में गोलबंद किए जाते रहे हैं। पिछली सदी के 1970 से 80 के बीच उभरे अनेक छात्र आंदोलन सत्ता-विरोध की धुरी के रूप में विकसित किए गए थे, किंतु तब गोलबंदी के मुद्दे मात्र शिक्षा जगत से जुड़े नहीं होते थे, उनके साथ समाज के हरेक वर्ग को जोड़ने वाले मुद्दे भी राजनीतिक दल सामने लेकर आते थे।

अब 'साइबर स्पेस' में जी रहे 'जेन-जी' को शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हरेक छोटे-बड़े मुद्दे पर गोलबंद करना विपक्ष को ज्यादा आसान लग रहा है। इसमें सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों और इन्फ्लूएंसर्स की एक बड़ी व सक्रिय सेना उपलब्ध है। दरअसल, आभासी दुनिया में आत्मरक्षा से ज्यादा आरोप और आक्रामकता की भाषा लोकप्रिय होती है।

इन दो बड़े कारणों के साथ कुछ ऐसे तात्कालिक कारण हैं, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस को वर्तमान शिक्षा मंत्री और सरकार को लक्षित करने के लिए प्रेरित कर रहे होंगे। कांग्रेस इस वक्त अपने राजनीतिक संगठन, प्रभाव और उस 'ज्ञान यूनिवर्स' को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, जो आजादी से अब तक स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रभावी रहकर शिक्षकों व छात्रों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी स्थानांतरित होता रहा है।

कांग्रेस-अनुप्राणित भारत की रूपरेखा और अर्थ, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की नेहरूवादी व्याख्या, बहुलता की कांग्रेसी सोच और अन्य अवधारणाएं भारतीय शिक्षा का मूलाधार रही हैं। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति-2020 ने भारतीय शिक्षा के ज्ञान यूनिवर्स में भारत के उस अर्थ को विस्थापित कर परंपरा एवं आधुनिकता के संतुलित समन्वय, विविधता में एकता की जगह एकत्व में विविधता के ज्ञान लोक को अनेक अनुशासनों के शिक्षण-प्रशिक्षण व विमर्शों में पिरोना प्रारंभ कर दिया है। शिक्षा मंत्री स्वाभाविक ही इस रूपांतरण का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इस बदलाव के परिणामों को शायद भांप रहे हैं। इसीलिए वह लगातार उच्च शिक्षण संस्थानों के नए बदलावों पर हमलावर रहते हैं। एक गौर करने वाला दिलचस्प पहलू यह भी है कि इधर अनेक राज्यों में विपक्ष को जो चुनावी पराजय मिली है, उनमें से कई में शिक्षा मंत्री की अहम भूमिका देखी गई है।

भारतीय युवाओं में असंतोष को आज विपक्ष अपनी गोलबंदी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देख रहा है। छात्र इस युवा संवर्ग का एक महत्वपूर्ण भाग है। शिक्षा से जुड़ा कोई भी विवाद उसमें अपने भविष्य को लेकर भय पैदा कर सकता है। दुनिया के अनेक बड़े अर्थशास्त्रियों ने भी माना है कि भय और संशय के इर्द-गिर्द गोलबंदी सत्ता की लड़ाई में अत्यंत प्रभावी होती हैं। सरकार शायद इसीलिए शिक्षा संबंधी हरेक विवाद में त्वरित करवाई कर छात्रों और युवाओं में सत्ता व विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में विश्वास सृजित करने की कोशिश कर रही है।

शिक्षा मंत्रालय नीट पेपर लीक और सीबीएसई उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में गड़बड़ी से समस्याग्रस्त हुई छवि को सुधारने के लिए छात्रों व युवाओं में विश्वास बहाली की योजना पर कार्यरत है। इसीलिए वह आगामी नीट परीक्षा को अचूक तरीके से संपन्न कराने व सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए जरूरी व्यवस्था करने और उसकी सूचना ठीक से छात्रों व अभिभावकों तक पहुंचाने में लगा है। नीट की पुनर्परीक्षा में पेपर लीक होने की किसी भी आशंका को निर्मूल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने वायु सेना का सहयोग मांगा है। निस्संदेह, इसके पीछे छात्रों की किसी भी आशंका को मिटाने की मंशा है। इससे तंत्र के प्रति विश्वास की पुनर्बहाली होगी।

भारतीय राजनीति की मौजूदा दशा-दिशा को देखते हुए यह कहने में कोई हिचक नहीं कि आने वाले दिनों में शिक्षा का क्षेत्र और ज्यादा राजनीतिक होता जाएगा। विपक्षी पार्टियां हर ऐसे अवसर के दोहन के लिए उत्सुक होंगी, जो उनको छात्रों और युवाओं को अपनी ओर खींचने में मदद कर सके। दूसरी तरफ, सरकारें हर क्षण छात्रों और नौजवानों में संस्थानों के प्रति विश्वास मजबूत करने के अपने मिशन को तेज करेंगी। भारतीय जनतांत्रिक राजनीति में आने वाले दिनों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिन पर संसद व विधानसभाओं से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष में टकराव बढ़ सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

क्या फिर लौट रहा पोलियो वायरस का खतरा

चंद्रकांत लहारिया | वरिष्ठ चिकित्सक और महामारी विशेषज्ञ

पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नमूने में वैक्सीन-डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप-1, यानी वीडीपीवी-1 मिलने की बात कही। भारत 13 जनवरी, 2011 से ही जंगली पोलियो वायरस से मुक्त है और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र ने भारत को पोलियो-मुक्त भी प्रमाणित कर दिया था। इसलिए यह खबर सुनने में बेचैन करने वाली लग सकती है, पर इसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। यह जंगली पोलियो वायरस नहीं है।

दरअसल, जंगली पोलियो वायरस प्राकृतिक रूप से फैलने वाला वायरस है, जिसने कभी भारत में हर साल हजारों बच्चों को पोलियो का शिकार बनाया। वैक्सीन-डिराइव्ड पोलियो वायरस का अलग अर्थ है। यह तब उभर सकता है, जब ओरल पोलियो वैक्सीन में इस्तेमाल कमजोर जीवित वायरस कम टीकाकरण वाले समुदायों में लंबे समय तक फैलता रहे और बीमारी पैदा करने की क्षमता फिर से हासिल कर ले। जहां आबादी में पर्याप्त टीकाकरण होता है, वहां वैक्सीन वायरस को ऐसा मौका नहीं मिलता, क्योंकि संक्रमण की श्रृंखला जल्दी टूट जाती है। इसलिए सीवेज में वीडीपीवी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि भारत जंगली पोलियो के आसन्न प्रकोप का सामना कर रहा है। इसका अधिक स्पष्ट अर्थ है कि संबंधित क्षेत्र के कुछ बच्चे बिना टीकाकरण के या अधूरे टीकाकरण वाले हो सकते हैं।

गाजियाबाद में सीवेज में वीडीपीवी मिलने का अर्थ यह नहीं है कि भारत जंगली पोलियो के आसन्न प्रकोप का सामना कर रहा है।

गाजियाबाद की घटना को हमारी निगरानी प्रणाली की सफलता के रूप में भी देखा जाना चाहिए। पोलियो वायरस मल के माध्यम से निकलता है, इसलिए किसी बच्चे में लकवे का मामला सामने आने से पहले ही उसे अपशिष्ट जल में पकड़ा जा सकता है। भारत ने जून 2001 में मुंबई और मई 2010 में दिल्ली में पोलियो वायरस के लिए व्यवस्थित अपशिष्ट जल निगरानी शुरू की थी। इस तरह भारत एशिया में ऐसी निगरानी अपनाने वाले शुरुआती देशों में रहा है और यह व्यवस्था पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की रीढ़ मानी जाती रही है।

भारतीय सीवेज में जंगली पोलियो वायरस आखिरी बार नवंबर 2010 में मुंबई और अगस्त 2010 में दिल्ली में मिला था। इसके कुछ ही समय बाद जनवरी 2011 में हावड़ा में भारत का आखिरी जंगली पोलियो मामला दर्ज हुआ। तब से भारत ने अपना पोलियो-मुक्त दर्जा बनाए रखा है, पर निगरानी प्रणाली वक्त-बेवक्त ऐसे संकेत पकड़ती रही है, जिन पर कार्रवाई जरूरी होती है। वैक्सीन-डिराइव्ड पोलियो वायरस पहले भी सीवेज में मिला है, जैसे अप्रैल 2022 में कोलकाता में और उससे पहले हैदराबाद में। ऐसी स्थिति में टीकाकरण और जांच अभियान तेज किए गए। पोलियो उन्मूलन के अंतिम चरण में ऐसी पहचानें सामान्य हैं।

जंगली पोलियो वायरस टाइप-1 अब बस पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है। भारत के इस क्षेत्र से ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्रवासी संबंध हैं। देश के भीतर आंतरिक प्रवास, श्रमिकों की आवाजाही, धार्मिक यात्राएं और घनी बस्तियां ऐसी परिस्थितियां बनाती हैं, जहां टीकाकरण में कोई भी चूक गंभीर हो सकती है। इस तरह के मामलों पर जवाबी रणनीति स्पष्ट है। पहला कार्य प्रभावित क्षेत्रों में घर-घर जाकर टीकाकरण को तेज करना है, खासकर पांच वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों पर ध्यान देते हुए, जिनका टीकाकरण अधूरा या अनिश्चित है। स्वास्थ्यकर्मियों को रिकॉर्ड जांचने होंगे, छूटे हुए बच्चों की पहचान करनी होगी और जरूरत के अनुसार टीका लगाना होगा। बार-बार सीवेज नमूने लेना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि वायरस समाप्त हो गया है या अब भी फैल रहा है।

भारत को पोलियो-मुक्त दर्जा कोई सौभाग्य से नहीं, बल्कि लगातार, महंगे व प्रशासनिक रूप से कठिन जन-स्वास्थ्य प्रयासों से मिला है। गाजियाबाद का सबक यह नहीं है कि पोलियो लौट आया है, या उन्मूलन कार्यक्रम किसी बड़े खतरे में है। सबक यह है कि उन्मूलन दीवार पर टंगा प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि रोज निभाया जाने वाला अनुशासन है। यह याद दिलाने वाला संदेश कि भारत की पोलियो उपलब्धि तभी सुरक्षित रहेगी, जब हर कमजोर बच्चे तक टीका पहुंचेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

महाभारत तो जारी रहेगा

आजकल लोग युद्ध को लेकर बड़े परेशान हैं, लेकिन मनुष्य जाति के लिए युद्ध कोई नई बात नहीं है। सच तो यह है कि जब से आदमी इस धरती पर रहा है, तभी से विश्व में दो तरह की स्थितियां रही हैं- युद्ध या युद्ध की तैयारी; शांति कभी रही ही नहीं। जिसे हम शांति कहते हैं, वह सिर्फ अगले युद्ध की तैयारी होती है। जरा एक नजर विश्व के इतिहास पर डालें, तो पूरा खून से लथपथ दिखाई देगा। इतिहास के नाम पर हम क्या पढ़ाते हैं? यही कि किस राजा ने किस राजा से युद्ध किया और कितने लोग मारे। मानव सभ्यता का पूरा विकास इन युद्धों के बीच और युद्धों के संग-संग हुआ है।

ओशो ने बिल्कुल सटीक कहा है कि महाभारत न तो कभी शुरू होता है और न कभी अंत; वह मनुष्य के अज्ञान के साथ चलता ही रहता है। वस्तुतः अज्ञान ही महाभारत है। कभी शीत युद्ध, कभी गर्म; कभी प्रकट, कभी छद्म, लेकिन मूर्च्छा में आप लड़ते ही रहेंगे। आध्यात्मिक रूप से बेहोश आदमी के लिए लड़ना ही जीवन मालूम होता है। युद्ध के लिए कोई आकाश से बमवर्षा आवश्यक नहीं है। वह तो आखिरी परिणति है। इसकी तैयारी तो घर-घर में चलती है; हृदय-हृदय में चलती है। युद्ध मैदानों में नहीं लड़े जाते, मनुष्य के अंधकार में लड़े जाते हैं। घर में लड़ने वाले लोग जब नेता बन जाते हैं, तो वे बड़े पैमाने पर लड़ते हैं। उनके पास ज्यादा ताकत होती है।

जरा गहराई से सोचें, लड़ाई कितने तालों पर होती है! हम सब भीतर से बंटे हुए हैं और खुद से लड़ रहे हैं। किसी दूसरे से तो बाद में लड़ेंगे, पहले हम अपने से और अपनों से लड़ रहे हैं। जीवन का एक भी ऐसा पल नहीं है, जब किसी न किसी अर्थ में संघर्ष न चल रहा हो। जहां संघर्ष है, वहां कैसे शांति होगी? फिर यही संघर्ष, हम जिनसे जुड़े हैं, उनमें भी फैल जाता है, बेहद क्षुद्र बातों पर! कितनी छोटी-छोटी बातों पर लड़ते हैं। जैसे बातें तो बहाना हैं, लड़ना तुम चाहते हो, इसलिए कोई भी बहाना काम दे देता है।

प्रायः लड़ने के क्षण में दिखाई भी नहीं पड़ता कि किस क्षुद्रता के लिए आपने आग्रह खड़ा कर लिया है। जब तक अज्ञान गहन है, अंधकार गहन है, अहंकार सघन है, तब तक आप देख भी नहीं पाएंगे कि आपका पूरा जीवन एक कलह है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम जीते नहीं, सिर्फ लड़ते हैं।

युद्ध बंद करने का एक ही उपाय है, एक-एक आदमी अपनी चित्त-दशा को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करे। अंदर के कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बनाए, तभी बाहरी युद्ध बंद हो सकते हैं।

अतः असली सवाल युद्ध नहीं है; असली सवाल मनुष्य की युद्ध से भरी चित्त-दशा का है। तमाम युद्धों को बंद करने का एक ही उपाय है, एक-एक आदमी अपनी चित्त-दशा को पूरी गहराई से समझने की कोशिश करे। अपने अंदर के कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र बनाए, तभी बाहरी युद्ध बंद हो सकते हैं।

अमृत साधना

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

नफरती बोल शांति और सुरक्षा के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। यह समुदायों को न सिर्फ बांटता है, बल्कि उनमें खून-खराबे का माहौल बनाता है। हमें शिक्षा, सरकारों और प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप के जरिये इस बुरे चक्र को तोड़ना होगा।

बुनियादी चीजों के लिए भी तरसते लोग

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक लंबे समय से एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग करते आ रहे हैं, किंतु पाकिस्तान सरकार यहां के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बजाय उनका दमन करती आई है। इसके लिए वह रह-रहकर फौज की मदद लेती है और पीओके में बेगुनाह नागरिकों की हत्या करके खौफ का राज कायम करना चाहती है।

पाकिस्तानी हुकूमत और सेना द्वारा दशकों से पीओके के मुखर नेताओं को जेलों में बंद करके प्रताड़ित किया जाता रहा है। उनके घरों की महिलाओं और बच्चियों की अस्मिता लूटी जाती है या विरोध के बदले में मौत दे दी जाती है। अभी हाल में पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों द्वारा मुजफ्फराबाद में जीवनोपयोगी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस्लामाबाद में बैठी हुकूमत से मांग की जा रही थी। पाकिस्तानी सेना को हर बार की तरह इस बार भी कश्मीरियों की मांगें नागवार गुजरीं और सेना प्रमुख मुनीर के इशारे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी लोगों पर अंधाधुंध गोलाबारी कर दी गई, जिसमें सौ से भी अधिक लोगों की मौत होने की आशंका है।

विडंबना यह है कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार भारतीय कश्मीर का मुद्दा उठाकर दुनिया की सहानुभूति पाने के प्रयास करता है, पर उसके कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की वास्तविक हालत वैश्विक विमर्श का कभी हिस्सा नहीं बन पाती। वहां के नागरिकों को आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह स्थिति पाकिस्तान के दावों और जमीनी हकीकत के अंतर को उजागर करती है।

दुनिया में मानवता की दुहाई देने वाले संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में मुसलमानों की वकालत करने वाले मौलानाओं और मानवाधिकार संगठनों को पाक अधिकृत कश्मीरियों के साथ हो रही बर्बरता क्यों नहीं नजर आती है? क्यों हर बार अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार आयोग के लोग और मौलाना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की मौत पर चुप्पी साध लेते हैं? अंतरराष्ट्रीय समुदाय और दुनिया भर के मुसलमानों के कथित ठेकेदारों द्वारा मुजफ्फराबाद में दर्जनों बेकसूर औरतों और बच्चों की हत्या की निंदा करते हुए पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग क्यों नहीं की जा रही है? उनकी इंसानियत क्या देश और इलाका देखकर जागती है?

अरविंद रावल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

पीओके में बर्बरता

जरूरी सुविधाओं से कहीं बड़ी हैं मांगें

पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों लोगों का जो आंदोलन चल रहा है, वह सिर्फ बुनियादी सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि उनकी मांगों का दायरा कहीं बड़ा है। दरअसल, वहां के लोग यह देख रहे हैं कि भारतीय हिस्से में किस तरह कश्मीरियों की भलाई के काम हो रहे हैं। वे यह भी जानते हैं कि भारत पूरे कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है और अगर वे लोग भारतीय निजाम के तहत होते, तो उन्हें भी आधुनिक विकास का सुख भोगने को मिलता। इस्लामाबाद की हुकूमत तो सिर्फ लूटना चाहती है। वहां के संसाधनों का इस्तेमाल इस्लामाबाद को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है।

साफ है, पाकिस्तान की सरकार कश्मीर को अपना नहीं मानती। वह माने भी क्यों, आखिर उसने इस पर जबरन कब्जा कर रखा है, ताकि भारत को परेशान कर सके। मगर वह भूल रही है कि भारत का रुख स्पष्ट है। वह उस हिस्से को भी अपना मानता है। वहां के लोगों के दुख-दर्द को नई दिल्ली समझती है, इसलिए हमारी सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पीओके में जो कुछ हो रहा है, उस पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देना चाहिए। दरअसल, पाकिस्तान पीओके को आतंकियों का ठिकाना बनाकर रखना चाहती है। उसकी मंशा यही जान पड़ती है कि दुनिया भर के मुल्क पीओके को एक आतंकवादी क्षेत्र के रूप में जानें, इसलिए उसने तमाम आतंकी संगठनों को अपने-अपने ठिकाने यहां बनाने की अघोषित अनुमति दे रखी है। भारत ने जो एयरस्ट्राइक की थी, उसकी वजह यही थी। पीओके के लोग जानते हैं कि उनके बीच में आतंकियों को पनाह देने की पाकिस्तान की मंशा उनको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार से परोक्ष रूप से अपनी 'आजादी' मांग रहे हैं।

बहरहाल, यह आंदोलन जिस भी दिशा में आगे बढ़े, लेकिन हमें सजग रहना होगा। पाकिस्तान ऐसी अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। उसे इस बात से मतलब ही नहीं कि पीओके के लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए भारतीय एजेंसियों को वहां के हालात पर नजर बनाकर रखनी होगी। हमारी सरकार पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार-बार बेपरदा करती रही है। उसे यह काम लगातार करना होगा। इसमें कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा, जब कश्मीर के इस हिस्से पर दावा करने का पाकिस्तान में साहस नहीं बचेगा। वह दिन वाकई पीओके के लिए आजादी का होगा। वहां के लोग मूलतः यही चाहते हैं।

निलेश मिश्र 'गोपी', टिप्पणीकार

अपने जीवन का पल-पल जिएं

हम सब अपनी जिंदगी की एक कहानी लिख रहे हैं। इस कहानी में कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ऐसे फैसले हैं, जिन्हें हम बार-बार आगे के लिए टालते रहते हैं। ऐसे में अपनों को खोने का दर्द, समय के तेजी से फिसलते जाने का एहसास और उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचकर खुद से पूछे गए चंद सवाल... हमें झकझोर देते हैं। सवाल यह नहीं कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि यह है कि जो समय हमारा है, उसे हम कैसे जी रहे हैं?

■ टमारा

'सबसे बड़ा साहसिक कार्य जो आप कर सकते हैं, वह है अपने सपनों का जीवन जीना।'
-ओपेरा विनफ्रे

जब मेरे पिता का निधन हुआ, तब वह केवल 49 वर्ष के थे। तब मैं बहुत छोटी थी, उस उम्र में दुख इंसान को अंदर से बहुत कोमल बना देता है। मैं उस नुकसान के दुख में बुरी तरह डूबी हुई थी। यह समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे पिता को अपने मनचाहे काम करने के लिए बस इतने ही साल मिले थे।

आप भले ही जीवन के गणित को न समझ पाएं, लेकिन जिंदगी आपको समझा ही देती है। भले ही आप इसके लिए तैयार होना चाहें या नहीं। कुछ सालों बाद, मेरे एक बेहद करीबी इंसान को कैंसर हो गया, वह भी आखिरी स्टेज पर पता चला। इस खबर ने उस व्यक्ति को ही नहीं, उससे जुड़े हर शख्स को बदल दिया। अचानक, आम जिंदगी का छोटापन असहनीय लगने लगा और यह साफ दिखने लगा कि हम कितना समय उन चीजों पर बर्बाद कर रहे थे, जो मायने ही नहीं रखतीं। फिर पिछले साल, मेरी दादी भी अचानक हमेशा के लिए चली गईं।

तीन मौतें। तीन याद दिलाने वाले सबक। सबसे जोरदार जगाने वाली आवाज मेरे भीतर से आई- मैं चालीस वर्ष की हो गई।

चालीस की उम्र के लिए कोई भी आपको तैयार नहीं करता। यह उम्र एक धीमे और स्थिर सवाल की तरह आती है- हम किस समय का इंतजार कर रहे हैं? इस उम्र में आप बूढ़े नहीं हो जाते, लेकिन इतने युवा भी नहीं रह जाते कि आप यह भरोसा रख पाएं कि अभी बहुत समय है। मैंने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को खो दिया, जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी और वे साठ की उम्र तक भी नहीं पहुंच पाए। और मैं क्या कर रही हूं? मैं यहां बैठी हूं- स्वस्थ, सक्षम, विचारों और सपनों से भरी हुई, जो अपनी पसंद के कामों को 'बाद के लिए' टाल रही है, मानो बाद का कोई टिकट मेरे पास पक्का है, लेकिन ऐसा नहीं है।

> जो काम आपने चाहकर भी नहीं किए, वे आपके साथ कसक बनकर देर तक साथ रहते हैं। कुछ न करना काम में असफल हो जाने से ज्यादा दुख देता है।

किसी ने जीना नहीं सिखाया

हमें इंतजार करना सिखाया गया है, इसलिए हम यही करते हैं। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, टालते रहते हैं और कभी सही तैयारी, अच्छे हालात और सही समय का इंतजार करते है। हालांकि, जिंदगी आपकी तैयारी के लिए अपनी रफ्तार धीमी नहीं करती। मौत कभी आपका कैलेंडर देखकर नहीं आती।

मैं यह इसलिए जानती हूं, क्योंकि मैंने अपने लेखन को दुनिया के सामने लाने के लिए बहुत लंबा इंतजार कर दिया था। मेरे पास विचार थे। मेरे पास ऐसे अनुभव थे, जो दूसरों के काम भी आ सकते है, लेकिन मैं डरी हुई थी। लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर। आलोचना का डर और अपनी कहानियों को दुनिया के सामने रखने की उस कमजोरी का डर, जहां मुझे नहीं पता था कि लोग उन्हें पसंद करेंगे भी या नहीं।

तब मैंने अपने पिता के छोटे से जीवन के बारे में सोचा और खुद से पूछा, अगर अभी नहीं, तो कब? मैंने शुरुआत की। डरी हुई, आधी-अधूरी तैयारी के साथ, लेकिन मैंने शुरुआत की। उस एक कदम ने, डर के खत्म होने का इंतजार न करने के उस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। डर कभी खत्म नहीं होता। आप बस यह तय कर लेते हैं कि डर के साए में जीना, वास्तव में जीना नहीं है।

इंतजार करना बंद कीजिए

अभी। इस सांस में। इस धड़कन में। जीना शुरू कीजिए। इसे डरते हुए ही करिए, कमियों के साथ ही करिए और आपके पास जितना भी सामर्थ्य है, उसी के साथ कदम बढ़ाएं। वर्तमान पल ही वह समय है, जिसकी आपको गारंटी मिली हुई है। कुछ न करने का पछतावा, प्रयास करने की असहजता से कहीं ज्यादा भारी होता है। वह जीवन, जिसे आपने पूरी तरह, कमियों के साथ, बहादुरी से और अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश की, वही मुड़कर देखने लायक है।

शुरुआत करने के लिए आपको किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। आपको बस चुपचाप और दृढ़ता से यह तय करना है कि आपकी जिंदगी 'अभी' जिए जाने के लायक है। सिद्धांतों में नहीं। किसी अन्य दिन नहीं। आपके जीवन की सूची में ऐसे कौन से काम हैं, जिन्हें आप इसी हफ्ते कर सकते हैं? अपने जीवन की सूची जरूर बनाएं।

जिएं इरादों के साथ

अपनी जिंदगी को भरपूर जीना, किसी बड़े दिखावे या जिंदगी को अचानक पूरी तरह बदल देना नहीं है। यह जिंदगी को जागरूकता और इरादे के साथ जीना है।

1 आत्म-निरीक्षण

हर महीने मैं खुद से पूछती हूं- यह महीना कैसा रहा? क्या मैंने मनचाही किताब पढ़ी, सैर की, बिना ग्लानि के आराम किया और अपनों को समय दिया? यह खुद को कोसना नहीं है। यह स्वयं को परखना है कि हम अपनी जिंदगी को ढंग से जी रहे हैं या फिर यों ही समय बिता रहे हैं।

2 अपनों की सुध लेना

मैं खुद से पूछती हूं कि मैंने पिछले कुछ समय से किन लोगों से बात नहीं की है? कौन लोग हैं, जिनसे सोशल मीडिया या मैसेज के जरिये नहीं, मिलकर ढंग से बात की जानी चाहिए? रिश्ते भी जीवन की सूची का हिस्सा हैं। जो लोग मायने रखते हैं, उन्हें आगे के लिए टाला नहीं जाता।

3 एक छोटा सा साहसी कदम

मैं हर मौसम में कम से कम एक ऐसी चीज चुनती हूं, जो महत्वपूर्ण है पर मुझे थोड़ा डराती है। यह कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं होती। कभी-कभी यह किसी कोर्स में दाखिला लेना होता है। कभी-कभी बरसों की खामोशी के बाद किसी से संपर्क करना होता है और कभी-कभी बस 'हां' कहना होता है। काम कितना बड़ा है, यह मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण आपकी कोशिश है।

4 खुद के प्रति प्यार भरी जवाबदेही

ईमानदार रहना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हम फिर उसी जाल में गिर जाते हैं कि 'बाद में करेंगे।' तब मैं खुद पर चिल्लाने के बजाय प्यार से पूछती हूं- अगर यह मेरा आखिरी मौका है, तो क्या मैं तब भी इंतजार करूंगी? यह सवाल हर बहाने को काट देता है। यह खुद को डराना नहीं, बल्कि खुद से इतना प्यार करना है कि आप जिंदगी को टालना बंद कर दें। जब अंतिम समय आएगा, तो आप मुड़कर क्या देखेंगे? क्या मैं कह पाऊंगी कि मैंने खुलकर जिंदगी जी? बेझिझक प्यार किया और जोखिम उठाए? या मैं सिर्फ उन ख्वाहिशों की सूची लेकर बैठी रहूंगी जो 'सही समय' के इंतजार में धरी रह गईं? सही समय कभी नहीं आता, बल्कि जो है, वही सही है। हम अमर नहीं हैं। यह कोई डरावना विचार नहीं है, बल्कि जिंदगी को खुलकर जीने का नजरिया है। सही समय कभी नहीं आता, बल्कि हर समय सही है।

tinybuddha.com

विविध

याददाश्त बनाएं दस गुणा तेज

हमारा दिमाग एक फरारी कार जैसा है, लेकिन किसी ने हमें इसे चलाना नहीं सिखाया। बहुत सारे लोगों को तो यह भी नहीं पता कि वे अच्छी याददाश्त के धनी हैं। सबसे पहले, रटना बंद करें। यह दिमाग का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि एक कौशल है, जिसे सीखा जा सकता है।

सबसे बड़ी गलती और सच

गलती: लोग मानते हैं कि उनकी याददाश्त ही खराब है। वह पढ़ते हैं और भूल जाते हैं
सच: याददाश्त दिमाग का कोई स्थायी हिस्सा नहीं है। यह कौशल है। जिस तरह बिना सीखे कार चलाने पर दुर्घटना हो सकती है, वैसे ही बिना अभ्यास और सही तकनीक अपनाए, आप चीजों को जल्दी ही भूल जाएंगे। परफेक्ट मेमोरी एक मिथक है, आप पढ़े हुए हर शब्द को याद नहीं कर सकते। इसकी जगह आप विचार और सार को याद रखें।

याद रखने के 3 स्तंभ

इसे अच्छी याददाश्त के तीन आर भी कहते हैं-
रिकॉर्ड: दर्ज करना। जानकारी को समझते हुए दिमाग में बैठाना।
रिटेन : बनाए रखना। जानकारी को दिमाग में सुरक्षित स्टोर करना। इसके लिए दोहराना और सूचनाओं के साथ एक संबंध बनाना जरूरी है।
रिट्रीव: दोबारा पा लेना। जरूरत पड़ने पर उसे उपयोग करना। अधिकांश लोग सिर्फ दोहराने पर जोर देते हैं, जिससे दिमाग थक जाता है।

ये 5 सिद्धांत जरूरी

1. **अर्थपूर्णता:** सूचना को समझें, साथ ही अगर इसे तुरंत किसी चीज पर लागू कर सकते हैं, तो करें।
2. **व्यवस्थित:** जैसे लाइब्रेरी में किताबें व्यवस्थित होती हैं, वैसे ही दिमाग में सूचनाएं व्यवस्थित करें।
3. **मेल :** नई जानकारी को किसी ऐसी पुरानी जानकारी से जोड़ें, उससे तुलना करें।
4. **छवियां:** दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरें याद रखता है।
5. **ध्यान :** हम अक्सर वही चीजें भूलते हैं, जिन पर हम पहले ध्यान नहीं देते।

तीन जरूरी तकनीक

क. लिंक और स्टोरी मेथड : अलग-अलग शब्दों या चीजों की दिमाग में अजीब व मजेदार कहानी बना लें। जितनी अजीब कहानी होगी, उतनी वह याद रहेगी।
ख. मेमोरी पैलेस मेथड : अपने घर की कल्पना करें। उस रास्ते के अलग-अलग जाने-पहचाने कोनों पर उन जानकारियों को चित्रों के तौर पर रख दें, जिन्हें याद करना है। वहां से आते-जाते उन पर सोचते रहें।
ग. सब्स्टीट्यूशन मेथड: कठिन शब्दों को एक मिलती-जुलती तस्वीर में बदलें।

दोहराने का सही तरीका 'द फॉरगेटिंग कर्व'

हम जो सीखते हैं, वो समय के साथ धुंधला होने लगता है। हर समय या हर रोज चीजों को दोहराने के बजाय एक पैटर्न बनाए, जैसे 1, 3, 5 और 7 दिन बाद चीज को दोहराना। इसमें मेहनत कम लगेगी और जानकारी लंबे समय तक याद रहेगी।

सांस लेने के ये तीन तरीके बढ़ाएंगे सुकून

तनाव के क्षणों में सांसें तेज चलने लगती हैं। जब हम अपनी सांसों की गति धीमी करते हैं, तब दिमाग को यह संकेत भेजते हैं कि हम सुरक्षित हैं। अपनी सांसों को महसूस करना, मन को शांत कर देता है। अगली बार तनाव बढ़े तो इन्हें आजमाएं-

1. बॉक्स ब्रीदिंग : तन और मन को शांत करने वाली यह सबसे आसान और असरदार तकनीकों में से एक है। दबाव की स्थिति में खुद को केंद्रित रखने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल खिलाड़ी, वक्ता, लेखक और यहां तक कि सैन्यकर्मी भी करते हैं।
विधि : 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लें, 4 सेकंड तक सांस को रोककर रखें और फिर 4 सेकंड तक मुंह से सांस बाहर छोड़ें। इसके बाद फिर से 4 सेकंड तक सांस रोके रखें। इस चक्र को कई बार दोहराएं। जैसे ही आप इसे लगातार करेंगे, तो महसूस करेंगे कि धड़कनें धीमी हो रही हैं। विचार शांत हो रहे हैं।

2. लंबी आह भरना : कभी-कभी तनाव बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसे में खुद को काबू में रखने के लिए तुरंत 'फिजियोलॉजिकल साइ' यानी लंबी आह भरना राहत देता है।
विधि : नाक से एक गहरी सांस अंदर लें। फेफड़ों को पूरी तरह फैलाने के लिए नाक से ही एक और छोटी व तेज सांस अंदर लें।
अब मुंह से एक लंबी आह भरते हुए धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें। यह तकनीक शरीर में जमे हुए तनाव को बाहर निकालने में मदद करती है। कई बार एक या दो बार ऐसा करने पर ही राहत महसूस होने लगती है।

3. फाइव-फिंगर ब्रीदिंग : इसमें सांसों की प्रक्रिया के साथ हाथों की हल्की हलचल भी शामिल होती है। इसे तब करें, जब दिमाग बहुत भटका हुआ या बेचैन महसूस हो।
विधि : एक हाथ को सामने सीधा खोलकर रखें। दूसरे हाथ की तर्जनी का उपयोग करके खुली हुई हथेली की सीमा के चारों ओर घुमाएं।
जैसे ही आप किसी उंगली पर ऊपर की ओर बढ़ें, धीरे-धीरे सांस अंदर लें और जब आप उंगली से नीचे की ओर आएं, धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें। इसी तरह सभी पांचों उंगलियों पर उंगली घुमाते रहें।
यह तकनीक एक साथ कई इंद्रियों को सक्रिय करती है। आप अपनी सांस, हाथों की हलचल और स्पर्श के एहसास पर ध्यान लगाते हैं। फालतू विचारों से दिमाग को आराम मिलता है और आप वर्तमान में लौट आते हैं।

नाराजगी सेहत के लिए अच्छी नहीं

हम अक्सर किसी पुरानी कड़वाहट या धोखे को मन में दबाकर रखते हैं। हालिया शोध बताते हैं कि यह मानसिक बोझ शरीर को अंदर ही अंदर बीमार कर देता है। अगाखानी व उनकी टीम के हालिया अध्ययन के अनुसार, मन में लंबे समय तक नाराजगी पाले रखने से शरीर में तनाव और सूजन बढ़ती है, जिससे गंभीर रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

जब हम पुरानी कड़वाहट को याद करते हैं, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मस्तिष्क का अलार्म सेंटर यानी एमिग्डाला शरीर को लगातार 'सर्वाइवल मोड' में रखता है, जिससे रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर होने लगती है। लंबे समय यह स्थिति शरीर को बीमार कर देता है।

क्षमा करें, आगे बढ़ें

स्टैनफोर्ड फॉरगिवनेस प्रोजेक्ट के निदेशक डॉ. फ्रेड लुस्किन के अनुसार, क्षमा करने का मतलब किसी के गलत काम को सही ठहराना या उससे दोबारा रिश्ता जोड़ना नहीं है, बल्कि यह खुद की भलाई के लिए उठाया गया कदम है। शोध के अनुसार, क्षमा की प्रक्रिया के चार चरण हैं-
माइंडफुलनेस : अपनी दबी हुई नाराजगी व दर्द को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना।
आत्म-सहानुभूति : खुद को दोष देने के बजाय एक दोस्त की तरह खुद की देखभाल करना।
बात साझा करना : थेरेपिस्ट या भरोसेमंद दोस्त से बातें शेयर करें।
कर्म और व्यक्ति अलग-अलग : गलत काम का विरोध करें, पर सामने वाले के प्रति नफरत की भावना मन से निकालें। दलाई लामा और नेल्सन मंडेला जैसे तमाम महापुरुषों ने माना है कि न्याय की लड़ाई लड़ते हुए भी मन को नफरत से मुक्त रखा जा सकता है।

एकदा

प्रयास

एक गांव में एक मेहनती युवक रहता था। उसके खेत के किनारे एक विशाल पत्थर पड़ा हुआ था। पत्थर इतना बड़ा था कि कुछ लोगों के द्वारा मिलकर भी उसे हिलाना संभव नहीं था। तब युवक ने उस पत्थर को तोड़ने का निश्चय किया। लोगों का मानना था कि उसे तोड़ना लगभग असंभव है।

युवक हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, हथौड़ा उठाता और पत्थर पर प्रहार करना शुरू कर देता। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गांव वाले उसे देखते और हंसते। किसी ने कहा, 'इतनी मेहनत बेकार है।' किसी ने सलाह दी, 'समय बर्बाद मत करो, यह पत्थर नहीं टूटेगा।'

लेकिन युवक ने हार नहीं मानी। वह रोज प्रहार करता रहा।

बीस दिन बाद भी कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। पचासवीं चोट, साठवीं चोट, आदमी चोट पर चोट कर रहा था। पत्थर पर दरार तक नहीं थी।

एक दिन उसने 101वीं बार हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से चोट की। इस बार पत्थर टूट गया।

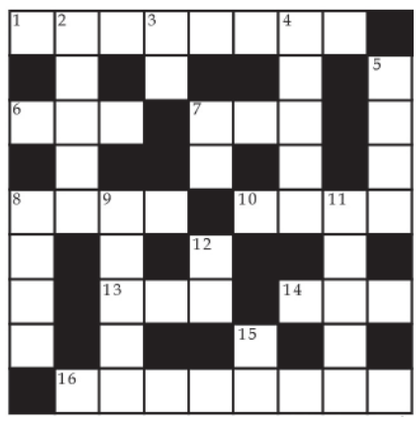

गांव वाले दौड़े आए। सबने कहा, 'वाह! इस चोट ने कमाल कर दिया।'

युवक मुस्कुराया और बोला, 'नहीं, पत्थर केवल आखिरी चोट से नहीं टूटा। अगर उससे पहले की सौ चोटें न होतीं, तो यह प्रहार बेअसर रहता।'

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित हो सकता है। यात्रा से लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा।

वृष : जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। माता-पिता का साथ मिलेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में व्यवस्तता बढ़ेगी। आय में वृद्धि के साधन बनेंगे।

मिथुन : नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। अफसरों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा।

कर्क : मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा व साक्षात्कारादि कार्यों में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी।

सिंह : घर-परिवार में धार्मिक व मांगलिक कार्य हो सकते हैं। भवन के रख-रखाव तथा साज-सज्जा के कार्यों पर खर्च बढ़ेंगे। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : शैक्षिक व शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से आय के साधन बन सकते हैं। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं। परिश्रम अधिक रहेगा।

तुला : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में वृद्धि होगी। माता-पिता से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

वृश्चिक : मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक व शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। कारोबार में भागदौड़ अधिक रहेगी।

धनु : आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। शैक्षिक कार्यों के प्रति सचेत रहें। बाधा आ सकती हैं। कारोबार के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है। खर्च बढ़ेंगे।

मकर : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। किसी संपत्ति से आय के साधन भी बन सकते हैं। मित्र का सहयोग मिलेगा।

कुंभ : संतान सुख में वृद्धि होगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

मीन : शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों से आय बढ़ सकती है। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद हो सकती है। किसी मित्र का सहयोग भी मिल सकता है।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

15 जून, सोमवार, **शक संवत्** : 25 ज्येष्ठ (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 01 आषाढ़ मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 28 जिल्हिजा, 1447, **विक्रमी संवत्** : द्वितीय (अधिक) ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि प्रातः 08.24 बजे तक पश्चात प्रतिपदा रात्रि 04.31 मिनट तक, नाग करण। चंद्रमा वृष राशि में प्रातः 08.41 बजे तक उपरांत मिथुन राशि में।

सूर्य उत्तरायण। प्रातः 07.30 बजे से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। सोमवती अमावस। ज्येष्ठ अधिक (पुरुषोत्तम) मास समाप्त। श्री गंगा स्नान प्रारंभ।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया कुछ ऐसे उपाय बताएं, जो हमें जीवन में सफलता दें।
-अनंत शर्मा, मेरठ

- शनिवार को पक्षियों के चुगने के लिए उड़द की दाल या सतनाजा डालें।
- शनिवार की शाम पितरों के नाम का दीया जलाएं।
- शनिवार को अपने घर या स्थान के जाले अवश्य साफ करें। इससे आपके रास्ते की बाधा हटती है। शनिवार को काले कपड़े पहनकर न निकलें।
- शनिवार को घर के मंदिर में चढ़ाए हुए सूखे फल किसी पीपल के नीचे चढ़ा दें या प्रवाहित कर दें। शनिवार को किसी को अपशब्द न बोलें।

वर्ग पहेली : 8360

1	2		3			4		■
■		■		■	■		■	5
6			■	7			■	
■		■	■		■		■	
8		9		■	10		11	
	■		■	12	■	■		■
	■	13			■	14		
	■		■	■	15	■		■
■	16							

बाएं से दाएं
1. दिल खराब करना; नाराज होना; मन उदास होना; मन फेरना; परेशान होना (2,3,3)
6. सिलसिला; अवसर; मौका; बात; विषय; प्रकरण; संदर्भ (3)
7. एक कड़वा फल जिसकी सब्जी बनती है (3)
8. अचरज में डालने वाला काम; करामात; जादू; लीला; कौशल (4)
10. आदर का अभाव; अप्रतिष्ठा; अपमान; तिरस्कार; निरादर (4)
13. निकला हुआ कोना; छोर; नोक; नाका; मोड़ (3)
14. गोल और चिपटा छोटा टुकड़ा; गोलाकार वस्तु; गोली; बट्टी (3)
16. छीन लेना; हर लेना (5,3)

ऊपर से नीचे
2. कत्ले आम; भारी मार काट (5)
3. मत; विचार; सलाह (2)
4. माधुर्यपूर्ण होना; रसयुक्त होना; स्वादिष्ट होना; रोचक होना (3,2)
5. निज की संपत्ति; ठौर; रहने का स्थान; परिवार; गृहस्थी (4)
7. पुर्जा; मशीन; यंत्र; युक्ति; बीता हुआ दिन (2)
8. जिस पर कोई कलंक लगाया गया हो; दोषयुक्त; बदनाम; लांछित; जिस पर जंग लगा हो; जिस पर मैल जमा हुआ हो (4)
9. के अनुसार; उसी तरह से (5)
11. अलग; अलहदा; दूर; परे (5)
12. गले से नीचे कमर तक का भाग; शरीर का मध्य भाग; पेड़ का तना (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8359

1 सा	■	2 च	■	3 सि	द्ध	4 क	र	5 ना
6 ह	व	ल	दा	र	■	ठि	■	म
सी	■	ब	■	प	■	7 न	र्त	की
■	■	8 स	दा	र	त	■	■	र्त
9 वा	र	ना	■	मि	■	10 का	ली	न
र	■	■	11 छु	ट्टी	पा	ना	■	■
12 क	थ	13 न	■	डा	■	क	■	14 धा
र	■	र	■	15 ल	ह	र	दा	र
16 ना	म	क	र	ना	■	ना	■	क

सुडोकू : 8342

* आसान

	1	6		9		5	3	
	9						1	
			3		7			
5			2		1			4
		4	5		9	3		
8			7		3			6
			1		4			
	8						4	
	6	3		5		1	7	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8341

5	9	8	2	1	7	4	6	3
1	6	7	4	3	5	8	2	9
3	2	4	8	6	9	7	5	1
8	7	5	6	4	3	9	1	2
6	1	3	9	7	2	5	4	8
9	4	2	1	5	8	3	7	6
2	5	9	7	8	6	1	3	4
7	8	1	3	2	4	6	9	5
4	3	6	5	9	1	2	8	7

खुशखबरी : बैंक में जमा रकम की बीमा राशि 7.5 लाख करने की तैयारी

■ हर्ष कुमार

नई दिल्ली। बैंकों में जमा धन की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार बैंक जमा बीमा की सीमा को मौजूदा पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह फरवरी 2020 के बाद पहली बार होगा, जब जमा बीमा की सीमा में बदलाव किया जाएगा। वर्ष 2020 में सरकार ने इस सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया था। उस समय पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक और यस बैंक जैसे मामलों के बाद जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ गई थीं।

क्या होता है जमा बीमा? भारत में बैंकों में जमा राशि की सुरक्षा का जिम्मा रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के पास है। यह संस्था बैंक के डूबने या लाइसेंस रद्द होने पर जमाकर्ताओं को निर्धारित सीमा तक भुगतान सुनिश्चित करती है।

मौजूदा नियमों के तहत किसी एक बैंक में किसी व्यक्ति की कुल जमा राशि, जिसमें बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट शामिल हैं, पर अधिकतम पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं।

● फाइल फोटो

प्रस्तावित बदलाव के बाद यह सीमा बढ़कर 7.5 लाख रुपये हो सकती है।

क्यों बढ़ाई जा रही है सीमा? सरकार और नियामकों का मानना है कि छोटे जमाकर्ताओं का भरोसा बनाए रखना वित्तीय स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। हाल के वर्षों में कई सहकारी बैंकों पर नियामकीय कार्रवाई हुई है। रिजर्व बैंक ने कुछ सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए, जिसके बाद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को जमाकर्ताओं को भुगतान करना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि बैंकिंग प्रणाली की रीढ़ खुदरा जमा हैं। ऐसे में अधिक बीमा कवर मिलने से लोगों का बैंकिंग व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा और वे अपनी बचत को लेकर अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।

mint

कॉरपोरेशन के पास कितना है जमा बीमा कोष?

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने 1,988 करोड़ के दावों का निपटान किया। ये भुगतान मुख्य रूप से उन 72 शहरी सहकारी बैंकों से जुड़े थे, जिन्हें बंद किया गया था या उन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। 31 मार्च 2026 तक जमा बीमा कोष का आकार 2.61 लाख करोड़ से अधिक हो चुका था, जो पिछले साल की तुलना में 14.4% अधिक है। संस्था के पास दावों के भुगतान के लिए मजबूत वित्तीय आधार मौजूद है।

बीमा प्रीमियम की व्यवस्था में भी हुआ बड़ा बदलाव

इस बीच रिजर्व बैंक ने जमा बीमा प्रीमियम के लिए जोखिम-आधारित व्यवस्था भी लागू की है। अब सभी बैंकों से समान प्रीमियम लेने के बजाय उनकी वित्तीय स्थिति और जोखिम के आधार पर अलग-अलग दरें तय की जाएंगी। मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर जोखिम प्रबंधन वाले बैंकों को कम प्रीमियम देना होगा, जबकि अपेक्षाकृत कमजोर बैंकों पर अधिक प्रीमियम लागू होगा। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर अनुशासन और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

बैंक जमाकर्ताओं के लिए क्या होगा फायदा?

यदि नई सीमा लागू होती है तो बैंक विफल होने की स्थिति में जमाकर्ताओं को पहले की तुलना में 2.5 लाख रुपये अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। इससे मध्यम वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने वाले लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि, यह प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। यदि इसे हरी झंडी मिलती है तो यह करोड़ों खाताधारकों के लिए सकारात्मक बदलाव साबित होगा।

बाजार 30 S

एनएसई आईपीओ दस्तावेज पेश करेगा

नई दिल्ली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 15 या 16 जून को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास आईपीओ के लिए शुरुआती दस्तावेज दाखिल कर सकता है। एनएसई के निदेशक मंडल ने छह फरवरी को प्रस्तावित आईपीओ को मंजूरी दी थी।

बीते सप्ताह बाजार पूंजीकरण बढ़ा

नई दिल्ली। सेंसेक्स की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से आठ के बाजार पूंजीकरण में बीते सप्ताह करीब 1.90 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। आईसीआईसीआई बैंक को सबसे अधिक लाभ हुआ। वहीं, टीसीएस और एलआईसी के बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज की गई।

एफटीए से घरेलू विनिर्माण बढ़ेगा

नई दिल्ली। भारत की ओर से हाल के वर्षों में किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) से देश के फर्नीचर उद्योग के निर्यात और घरेलू विनिर्माण को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों से मिलने वाली शुल्क रियायतें भारतीय कंपनियों को के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

साल्टस्टेज 22 संपत्तियां जोड़ेगी

मुंबई। आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी साल्टस्टेज ने चालू वित्त वर्ष में 22 से अधिक संपत्तियों को जोड़ने की योजना बनाई है, जिसके साथ उसका कुल पोर्टफोलियो 55 पर पहुंच जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कंपनी देश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

मैजिकपिन 'वेरा' के जरिये विस्तार करेगी

नई दिल्ली। भोजन पहुंचाने वाली एवं ई-कॉमर्स कंपनी मैजिकपिन ने अपने एआई आधारित सहायक 'वेरा' से जुड़े व्यापारियों की संख्या वर्ष 2026 के अंत तक 10 लाख से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी ने कहा, तीन महीने में पांच लाख से विक्रेता जुड़ चुके हैं।

गृह मंत्रालय का एमआरएम पोर्टल शुरू, रकम वापसी के लिए घर बैठे कर सकेंगे आवेदन

ऑनलाइन ठगी में डूबी हुई रकम सरकारी पोर्टल से मिल सकेगी

सुविधा

नई दिल्ली, एजेंसी। साइबर ठगी का शिकार हुए लोगों के लिए राहत की खबर है। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने एमआरएम (मोबाइल रिस्टोरेशन मॉड्यूल) पोर्टल की शुरुआत की है। इसके जरिए डिजिटल अरेस्ट, ओटीपी से जुड़ी धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों के पीड़ित घर बैठे धन वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि, यह पोर्टल केवल तभी धन वापसी की प्रक्रिया पूरी करेगा, जब ठगी करने वाले के बैंक खाते में रकम पहले ही फ्रीज कर दी गई हो।

सरकार ने ठगी की रकम वापस लेने का दावा करने के लिए कुछ मानक तय किए हैं। अगर ठग के खाते में फ्रीज की गई कुल रकम 50 हजार से कम है तो आपको किसी एफआईआर के दस्तावेज या अदालत के आदेश की जरूरत नहीं है। पुलिस शिकायत के आधार पर ही रकम को आपके खाते में भेज दिया जाएगा। वहीं, अगर फ्रीज की गई कुल रकम 50 हजार से अधिक है, लेकिन वह अलग-अलग खातों में बंटी हुई है और किसी एक खाते में 50 हजार से ज्यादा नहीं है तो भी यहां पहली श्रेणी वाले नियम ही लागू होंगे। आपको रिपोर्ट दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी एक बैंक खाते में फ्रीज हुई रकम 50 हजार रुपये से अधिक है तो पोर्टल पर धन वापसी के लिए आवेदन से पहले रिपोर्ट दर्ज करानी जरूरी है। आवेदन के बाद पुलिस पोर्टल पर नोटिस अपलोड करेगी। फिर रकम वापस ट्रांसफर होगी।

आवेदन करने की प्रक्रिया

1. सबसे पहले बैंक खाता नंबर, पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी, 14 अंकों की शिकायत आईडी और अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर पास रखें।
2. इसके बाद एमआरएम पोर्टल (https://mrm-ncrp.mha.gov.in/public-info) पर जाएं। यहां दिए गए सिटिजेन लॉगिन बटन दबाएं।
3. इसके बाद पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए अपना पंजीकृत फोन नंबर डालें।
4. आपके नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके पोर्टल पर लॉगइन करें।
5. रेज रिफंड रिक्वेस्ट सेक्शन में जाएं और अपनी 14-अंकों वाली शिकायत आईडी (जो आपको एनसीआरपी पोर्टल से मिली थी) दर्ज करें।
6. अपने पैन कार्ड की डिजिटल कॉपी अपलोड करें। इसके बाद अपना बैंक खाता संख्या और अपनी ब्रांच का आईएफएससी कोड डालें।
7. अगर आपके पास अदालत के आदेश के दस्तावेज हैं तो आप कोर्ट ऑर्डर के विकल्प को चुनें और अपलोड कर सकते हैं।
8. डिक्लेरेशन के बगल में दिए गए चेकबॉक्स पर टिक करें और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें।
9. इसके बाद एमआरएम पोर्टल एक यूनिक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट करेगा। इसकी मदद से आप अपने रिफंड रिक्वेस्ट का स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे।

50 हजार से कम हो ठग के खाते में फ्रीज की गई रकम

50 हजार से ज्यादा रकम होने पर एफआईआर जरूरी

तुरंत दें जानकारी

किसी भी प्रकार की ठगी के बाद तुरंत घटना की जानकारी 1930 हेल्पलाइन नंबर पर या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। इसके बाद टीम जांच करके ठग के बैंक खाते में रकम को फ्रीज कर देगी। इसके बाद धन वापसी की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा।

भ्रामक दावों पर कंपनियों को नोटिस

सख्ती

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के आरोप में भ्रामक ब्रांड नाम, ट्रेड नाम और उत्पाद दावों का इस्तेमाल करने वाली आठ खाद्य कंपनियों को नोटिस जारी किया है।

नोटिस पाने वाली कंपनियों में इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, हेल्थ एड, ट्रूवी, द हेल्दी फैक्टरी, हेल्दी मास्टर, हेल्दी चॉइस, प्लान बी और न्यूहर्ब्स शामिल हैं। नियामक ने सोशल मीडिया मंच के माध्यम से इस कार्रवाई की जानकारी दी। एफएसएसएआई के अनुसार, इमामी हेल्दी एंड टेस्टी का 'ट्रेड' नाम उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है और यह लागू नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है। यह कंपनी कोलकाता स्थित इमामी समूह की खाद्य तेल इकाई है। न्यूहर्ब्स की 'ट्रू विटामिन' उत्पाद श्रृंखला को भी नोटिस मिला है।

स्नैक उत्पादों पर 'हेल्दी' होने के दावे को लेकर सवाल

ट्रूवी के 'हेल्दी मिक्स वेजी चिप्स', 'हेल्दी रागी चिप्स' और 'हेल्दी मूंग दाल चिप्स' जैसे स्नैक उत्पादों पर 'हेल्दी' होने के दावे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। नियामक का कहना है कि इनमें कई अन्य सामग्री भी शामिल हैं, ऐसे में इन उत्पादों को 'हेल्दी' बताना भ्रामक हो सकता है। एफएसएसएआई ने हेल्दी मास्टर की 'टैगलाइन' 'विजन टू सर्व हेल्दी',' हेल्दी चॉइस के ' 'हेल्दी फूड फॉर हेल्दी लाइफ पोहा'' और हेल्थ एड के ब्रांड नाम पर भी आपत्ति जताई है। प्राधिकरण का मानना है कि ये नाम और दावे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं।

एफपीआई ने 62 हजार करोड़ निकाले

नई दिल्ली, एजेंसी। बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जून के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजार से 62,853 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की है।

नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक एफपीआई भारतीय बाजार से लगभग 2.87 लाख करोड़ निकाल चुके हैं। यह राशि पूरे वर्ष 2025 में हुई 1.66 लाख करोड़ की निकासी से अधिक है। हालांकि, एफपीआई ने बॉन्ड प्रतिभूतियों में 13,200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।

वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में शीर्ष-20 में पहुंची जियो

मुंबई, एजेंसी। जियो प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन की ताजा पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग में जियो प्लेटफॉर्म्स शीर्ष-20 में पहुंच गई है। कंपनी 2025 की सूची में 320 पायदान चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंची है।

जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेक्नोलॉजी इकाई है। कंपनी अब हुआवेई, सैमसंग, क्वालकॉम, एलजी, पैनासोनिक, नोकिया, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी वैश्विक टेक कंपनियों के समूह में शामिल हो गई है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के एमडी आकाश एम. अंबानी ने कहा, 31 मार्च 2026 तक जियो प्लेटफॉर्म्स ने कुल 6,817 पेटेंट फाइल किए हैं। इनमें 2,393 पेटेंट भारत में और 4,424 पेटेंट विदेशी बाजारों में फाइल किए गए हैं।

- जियो प्लेटफॉर्म्स ने कुल 6,817 पेटेंट फाइल किए
- कंपनी 2025 की सूची में 320 पायदान चढ़ी

मेमोरी चिप निर्माण में बढ़ सकता है निवेश : वैष्णव

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में मेमोरी चिप के विनिर्माण के लिए नई कंपनियों की ओर से निवेश किए जाने की संभावना है, जबकि मौजूदा निवेशक भी इस क्षेत्र में आपूर्ति-मांग के अंतर को कम करने के लिए उत्पादन को और बढ़ाएंगे।

वैष्णव ने कहा कि मेमोरी कार्ड और उन्नत चिप की मजबूत मांग के कारण वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है और पिछले कुछ तिमाहियों में कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है। इसके चलते विनिर्माता वैश्विक स्तर पर जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत में डेटा सेंटर निवेश जल्द ही 200 अरब डॉलर को पार कर सकता है।

मजबूत मांग के कारण वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बढ़ा

छोटे कारोबारियों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं

रिपोर्ट

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश में छोटे और असंगठित यानी गैर-कृषि उद्यमों को ऋण प्राप्त करने के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्ययन में पाया गया है कि देश के 36.16 प्रतिशत असंगठित उद्यमियों को व्यवसाय लोन न मिलने या ऊंची ब्याज दरों के कारण सबसे अधिक परेशानी होती है। एनआईपीएफसी से जुड़े शोधकर्ता शिवानी बडोला और प्रोफेसर सचिदानंद मुखर्जी ने एनएसएसओ के वर्ष 2022-23 के वार्षिक सर्वेक्षण आंकड़ों का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि पर्याप्त ऋण न मिलने से छोटे और असंगठित क्षेत्र के उद्यमों को नई तकनीक लाने में परेशानी हो रही है। इससे इन उद्योगों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। विश्लेषण से पता चला कि 35% से अधिक उद्योग लोन न मिलने से व्यापक रूप से प्रभावित हैं, जबकि 28.80% आंशिक रूप से ऋण बाधित की श्रेणी में हैं। यानी 65% उद्यमों को वित्तीय संसाधनों तक पहुंच बनाने में कठिनाई हो रही है।

सात वर्षों में थोड़ा सुधार भी हुआ

शोध में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में सिर्फ 43.24 फीसदी छोटे उद्योगों के पास बैंकों या सरकारी संस्थाओं का लोन था, जबकि 50.32 फीसदी उद्योग साहूकारों या जान-पहचान वालों के कर्ज पर निर्भर थे, लेकिन साल 2022-23 में स्थिति थोड़ी सुधरी है। वर्ष 2023-24 में 52.95 छोटे उद्योगों के पास बैंकों का लोन है और अनौपचारिक स्रोतों से कर्ज लेने वालों का आंकड़ा घटकर 43.97 फीसदी रह गया है।

सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत

अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि सरकार की विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के बावजूद महिला, एससी, एसटी और ओबीसी उद्यमियों तक ऋण सुविधाओं की प्रभावी पहुंच के लिए जागरूकता बढ़ाने और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है, जिससे असंगठित क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता आसानी से मिल सके।

मई महीने में रूस से कच्चे तेल के आयात में बढ़ोतरी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत मई 2026 में रूसी जीवाश्म ईंधन का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा है। यूरोपीय शोध संस्थान सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में रूस से कुल कच्चे तेल और अन्य ईंधन का आयात बढ़कर अनुमानित 5.8 अरब यूरो (करीब 6.7 अरब डॉलर) पर पहुंच गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, मई में रूस से भारत के कुल आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी लगभग 83 प्रतिशत रही, जिसका मूल्य 4.8 अरब यूरो था। इसके अलावा तेल उत्पादों और कोयले का आयात क्रमशः 55 करोड़ यूरो और 42.9 करोड़ यूरो रहा। सीआरईए ने कहा कि रूस के कच्चे तेल के निर्यात में मई में चीन की हिस्सेदारी 50% रही, जबकि भारत 36% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

- चीन 50 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर रहा
- भारत 36% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर

'रुपये में उतार-चढ़ाव के कई कारण'

बेंगलुरु, एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में होने वाले उतार-चढ़ाव कई वैश्विक और घरेलू कारकों से प्रेरित होते हैं। इनमें भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, विदेशी पूंजी की आवाजाही और कच्चे तेल, उर्वरक तथा सोने पर भारत की आयात निर्भरता शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक रुपये की विनिमय दर को किसी निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए ही हस्तक्षेप करता है। सीतारमण ने कहा कि विनिमय दरें विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों और बाजार की परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं।

सीतारमण ने कहा, जब भी रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव या अस्थिरता आती है, तब भारतीय रिजर्व बैंक बाजार में हस्तक्षेप करता है। उसका उद्देश्य विनिमय दर को निश्चित स्तर पर बनाए रखना नहीं, बल्कि उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना होता है। आरबीआई बाजार में आकर स्थिति को स्थिर करता है और फिर बाहर हो जाता है।

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था

वित्त मंत्री ने कहा कि आधिकारिक आंकड़े और वैश्विक संस्थाएं लगातार भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बता रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच-छह वर्षों से भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इस वर्ष जारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों में कारखाना, कृषि, सेवा, लॉजिस्टिक और परिवहन सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

अमेरिका-ईरान वार्ता तय करेगी सोने-चांदी की चाल

नई दिल्ली, एजेंसी। दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति संबंधी बैठकों, अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच अगले सप्ताह सोने की कीमतें सीमित दायरे में रह सकती हैं।

विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक ब्याज दर परिदृश्य के संकेतों के लिए बैंक ऑफ जापान, अमेरिकी फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड की बैठकों के साथ-साथ ब्रिटेन, यूरो क्षेत्र, जर्मनी और जापान के मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर बारीक नजर रखी जाएगी। घरेलू बाजार में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अगस्त डिलिवरी वाला सोना वायदा भाव सप्ताह के दौरान 5,066 रुपये अथवा 3.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ लगभग 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जुलाई अनुबंध वाली चांदी 2,351 रुपये अथवा करीब एक प्रतिशत की गिरावट के साथ 2.46 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

क्यूएस आई-गॉज यूनिवर्सिटी रेटिंग: आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने प्रतिष्ठित ओवरऑल डायमंड रेटिंग प्राप्त की

आईआईएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिष्ठित क्यूएस आई-गॉज यूनिवर्सिटी रेटिंग में अपने प्रथम मूल्यांकन के दौरान ओवरऑल डायमंड रेटिंग प्राप्त की है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नवाचार, अनुसंधान, सुशासन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करती है। क्यूएस आई-गॉज भारत की अग्रणी विश्वविद्यालय मूल्यांकन एवं रेटिंग प्रणाली है, जो उच्च शिक्षण संस्थानों का विभिन्न गुणवत्ता मानकों के आधार पर व्यापक मूल्यांकन करती है। प्रथम ही मूल्यांकन में ओवरऑल डायमंड रेटिंग प्राप्त करना आईआईएमटी विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति, दूरदर्शी नेतृत्व और संस्थागत उत्कृष्टता का प्रमाण है। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की सुदृढ़ शैक्षणिक व्यवस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों, उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रम, उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड, आधुनिक अधोसंरचना, समावेशी वातावरण तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाती है।

योजना | वाहनों से होने वाले प्रदूषण को और कम करना प्राथमिकता, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए मानक तय करने पर भी विचार किया जाएगा

भारत स्टेज-7 उत्सर्जन मानक 2030 से लागू होगा

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में नए भारत स्टेज-7 उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित करने की तैयारी में है। इन नियमों को वर्ष 2030 से लागू किए जाने की योजना है। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को और कम करना तथा भारत को वैश्विक उत्सर्जन मानकों के करीब लाना है।

भारत स्टेज-7 के तहत वाहनों के लिए मौजूदा भारत स्टेज-6 की तुलना में अधिक कड़े उत्सर्जन मानक लागू होंगे। इसमें केवल लैब टेस्ट ही नहीं, बल्कि सड़क पर वास्तविक परिस्थितियों में होने वाले उत्सर्जन की निगरानी भी शामिल होगी। उन्नत ऑन-बोर्ड डायग्नोस्टिक्स और वाहन की उत्सर्जन क्षमता की लंबी अवधि तक जांच जैसी व्यवस्थाएं भी अनिवार्य की जा सकती हैं।

नए मानकों को पूरा करने के लिए वाहन कंपनियों को इंजन, एग्जॉस्ट सिस्टम और उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकों में अतिरिक्त निवेश करना होगा। इससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है और असर ग्राहकों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत स्टेज-7 लागू होने के बाद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी संभव है।

सीएनएजी वाहनों पर भी होगी सख्ती

प्रस्तावित नियमों में पहली बार सीएनएजी से चलने वाले वाहनों के उत्सर्जन पर भी अधिक कड़ी निगरानी की जाएगी। अमोनिया जैसे प्रदूषकों को भी नियमों के दायरे में लाने की योजना है, जो शहरी धुंध (स्मॉग) का प्रमुख कारण माने जाते हैं।

भारत स्टेज-4 से भारत स्टेज-6 तक का सफर

भारत ने वर्ष 2020 में सीधे भारत स्टेज-4 से भारत स्टेज-6 मानकों पर छलांग लगाई थी और भारत स्टेज-5 चरण को छोड़ दिया था। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे प्रदूषकों में उल्लेखनीय कमी आई। भारत स्टेज-7 को बड़ा कदम माना जा रहा है।

बैटरी नियमों पर भी नजर

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के लिए न्यूनतम टिकाऊपन और प्रदर्शन मानक तय करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य बैटरी की गुणवत्ता, सुरक्षा और लंबी उम्र सुनिश्चित करना है।

आम लोगों के लिए क्या हैं मायने?

- नई कारें और दोपहिया वाहन महंगे हो सकते हैं
- प्रदूषण नियंत्रण तकनीक पहले से बेहतर होगी
- पुरानी प्रदूषणकारी तकनीकों वाले मॉडल बाजार से हटेंगे
- देश में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा

वीजीयू जयपुर जॉब फेस्ट-2026 में 1564 विद्यार्थियों का चयन

युवाओं को रोजगार के उत्कृष्ट अवसर उपलब्ध कराने तथा उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय (वीजीयू), जयपुर द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) में आयोजित वीजीयू जयपुर जॉब फेस्ट-2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस रोजगार महोत्सव में वीजीयू सहित प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के हजारों विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण एवं नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित इस जॉब फेस्ट के लिए 4556 से अधिक अभ्यर्थियों ने पूर्व पंजीकरण कराया था, जबकि 552 विद्यार्थियों ने आयोजन स्थल पर ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण करवाया। इस प्रकार कुल 5108 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस रोजगार महोत्सव में भागीदारी की। जॉब फेस्ट में 100 से अधिक राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने सहभागिता की और 1564 विद्यार्थियों का चयन हुआ।

कल्पमेधा

प्रत्येक इंसान बुद्धिमान है। अगर आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से आंकने की कोशिश करेंगे, तो वह अपनी पूरी जिंदगी यह सोच कर जिएगी कि वह मूर्ख है।
– अल्बर्ट आइंस्टीन

हादसों का सिलसिला

देश में हवाई सफर को सुलभ एवं किफायती बनाने के लिए विमान सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। नए-नए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। मगर यात्रियों की सुरक्षा के मोर्चे पर माकूल व्यवस्था का अभाव आज भी साफ नजर आता है। तकनीकी खराबी, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी, मौसम की अप्रत्याशित चुनौतियां और सतर्कता की गंभीरता को नजरअंदाज किए जाने से होने वाली मानवीय चूक का ही नतीजा है कि विमान हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। असम के जोरहाट में शनिवार को एएन-32 परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें वायुसेना के पांच कर्मियों की जान चली गई। सवाल है कि देश भर में अब तक हुए विमान हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता है? कोई एक ही तरह की खामी बार-बार हादसों का कारण कैसे बन रही है? क्या दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद मुहैया करा देने भर से विमानन कंपनियों और संबंधित नियामक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है! भविष्य में इस तरह के हादसों पर रोक लगाने और विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व आखिर किसका है?

इसमें दोराय नहीं कि हाल के वर्षों में हवाई यात्रा की सुविधा को विस्तार देने के लिए उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। मगर इसी अनुपात में पायलटों और अन्य प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती नहीं हो पाई है। इस कारण मौजूदा संचालन तंत्र पर दबाव बढ़ा है, जिससे मानवीय चूक की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार, लगभग पैंसठ फीसद विमान दुर्घटनाओं के पीछे मानवीय चूक एक प्रमुख कारक होती है। विमान के उड़ान भरने और जमीन पर उतरते समय जब स्थिति बिगड़ती है, तो काकपिट में होने वाला भ्रम भी हादसों का कारण बनता है। खबरों के मुताबिक, एएन-32 परिवहन विमान के साथ भी यही हुआ, हवाईअड्डे पर उतरते समय विमान का नियंत्रण बिगड़ गया और वह रनवे से फिसल कर दो हिस्सों में टूट गया, जिससे उसमें आग लग गई। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्रों में मौसम और भौगोलिक बनावट भी उड़ान संचालन के लिए बेहद जोखिम भरी होती है। कई बार मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी न होने से विमान हादसे का शिकार हो जाता है।

यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि क्या किसी विमान दुर्घटना के कारणों का गहराई से विश्लेषण कर संचालन व्यवस्था में सुरक्षात्मक उपायों को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है? हालांकि, हादसों की जांच और विश्लेषण की प्रक्रिया में समूचे तंत्र की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई विमान दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट तो सार्वजनिक ही नहीं की जाती है। अगर हादसा बड़ा हो, तो उसकी जांच पूरी होने में लंबा वक्त लग जाता है और फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। पिछले साल अहमदाबाद में हुआ एअर इंडिया का विमान हादसा इसका उदाहरण है, जिसकी अंतिम जांच रिपोर्ट एक साल बाद भी सामने नहीं आई है। इस दुर्घटना में कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के पीड़ित परिवार आज भी इस तथ्य के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उस दिन विमान में हुआ क्या था। अगर किसी विमान हादसे की जांच रिपोर्ट आने में ही एक साल से ज्यादा का वक्त लग जाए, तो यात्रियों के सुरक्षित सफर की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन करना मुश्किल नहीं है।

संदेह की लपटें

जिस चुनावी प्रक्रिया पर विपक्षी दलों की ओर से लगातार सवाल उठाए जाते रहे हों, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हों, उस पर कोई स्पष्टता आने के बजाय अगर चुनाव से जुड़े संसाधनों को लेकर घोर लापरवाही बरती जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उसमें उपयोग में लाई गई करीब चार हजार इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों का जल कर खाक हो जाने की घटना संदेह पैदा करती है। पिछले हफ्ते कोलकाता की सरकारी इमारत में ऊपरी मंजिलों पर रखी मशीनों में आग लग जाने के पीछे विपक्षी दलों ने साजिश की आशंका जताई है। सवाल है कि सभी ईवीएम अगर उच्च सुरक्षा क्षेत्र में रखी गई थीं, तो वहां आग कैसे लगी? खबरों के मुताबिक तीसरी मंजिल पर लगी आग सातवीं-आठवीं मंजिल तक पहुंच गई, जहां ईवीएम रखी गई थी। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएं, लेकिन जिन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से मतदान कराने को लेकर तमाम विपक्षी दलों की ओर से बार-बार सवाल उठाए जाते रहे हैं, उनकी सुरक्षा और निगरानी में ऐसी गंभीर लापरवाही कैसे बरती गई? इतनी बड़ी तादाद में ईवीएम जल जाने की घटना के बाद स्वाभाविक ही न सिर्फ राजनीतिक दलों का, बल्कि मतदाताओं का भी भरोसा एक बार फिर डगमगाएगा।

गौरतलब है कि बंगाल में चुनाव के पहले और उसके दौरान तृणमूल कांग्रेस ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। गंभीर आरोपों के बीच क्या यह चुनाव आयोग का दायित्व नहीं था कि वह ईवीएम की सुरक्षा और विश्वसनीयता को कायम रखने के पुख्ता इंतजाम करता? इससे जुड़े कई आरोपों पर स्पष्टता लाने के विपरीत हुआ यह कि पश्चिम बंगाल में ईवीएम के जल जाने की घटना ने संदेहों को और पुख्ता कर दिया है। ऐसे समय में जब वोटों की गिनती में गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर अदालतों से हस्तक्षेप की मांग की जा रही हो, यह घटना चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा करती है। ईवीएम जल जाने की घटना के बाद मतदाताओं का भरोसा एक बार फिर कसौटी पर है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि लोकतंत्र मतदाताओं के विश्वास से चलता है। इसके टूटने से उसकी बुनियाद हिल सकती है।

चीन को साधने की रणनीतिक पहल

भारत ने ग्रेटर निकोबार विकास परियोजना शुरू की है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की व्यापारिक और रणनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है।

नंदकिशोर सोमानी

भारत ने ग्रेटर निकोबार विकास परियोजना शुरू की है। इस पर लगभग एक लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च होने का अनुमान है। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम की देखरेख में शुरू की गई इस परियोजना के तहत एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर 'ट्रांस-शिपमेंट टर्मिनल', नागरिक एवं सैन्य हवाई अड्डा, गैस संचालित विद्युत संयंत्र और एक हरित शहर (ग्रीनफील्ड टाउनशिप) का निर्माण किया जाएगा। मलक्का जलडमरूमध्य के करीब होने के कारण भारत की यह पहल हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की व्यापारिक और रणनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कई मायनों में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है। चीन के कुल तेल आयात का लगभग अस्सी फीसद इसी मार्ग से होकर गुजरता है। भारत के इस फैसले को हिंद महासागर में शक्ति संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अंडमान सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप को आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए देश के नीति आयोग ने वर्ष 2021 में ग्रेटर निकोबार विकास परियोजना की संकल्पना की थी। इसका मुख्य लक्ष्य हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करना है। इस वृहद परियोजना को तीन चरणों में वर्ष 2047 तक पूरा किया जाना है। हालांकि परियोजना को शुरू करने के साथ ही विपक्षी दलों, पर्यावरणविदों और यहां के मूल निवासियों के अधिकारों का समर्थन करने वाले सामाजिक संगठनों की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। उनका आरोप है कि इस परियोजना से वन क्षेत्र को नुकसान होगा और पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाएगा। यह आशंका जताई जा रही है कि द्वीप को विकसित करने के नाम पर लगभग दस लाख पेड़ों को काटा जा सकता है, जिससे तकरीबन 130 वर्ग किलोमीटर का प्राचीन वन क्षेत्र नष्ट हो सकता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बीते फरवरी में राष्ट्र की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए इस परियोजना को जरूरी बताकर पर्यावरणीय एवं तटीय स्वीकृतियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। पीठ का कहना था कि परियोजना के दीर्घकालिक लाभ (समुद्री सुरक्षा में वृद्धि, विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता में कमी और मजबूत प्रतिरक्षा क्षमता) तात्कालिक नुकसान से अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। एनजीटी ने अपने फैसले में पर्यावरण सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया था। इसके बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि 97.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना बनाई गई है और इस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के हितों का पूरा खयाल रखा जाएगा।

दरअसल, कुछ दिनों पहले देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली दो बड़ी घटनाएं हुईं। पहली, इंडोनेशिया सरकार द्वारा मलक्का जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की कोशिश और दूसरी चीन द्वारा थाइलैंड पर 'क्रा नहर' (थाई नहर) के निर्माण के लिए दबाव डालना। खबरों के मुताबिक, होर्मुज जलमार्ग में ईरान की ओर से जहाजों से शुल्क वसूलने के प्रयासों से प्रेरित होकर इंडोनेशिया ने हाल में

सुझाव दिया था कि मलेशिया और सिंगापुर को उसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से मलक्का जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाना चाहिए और राजस्व को तीनों देशों के बीच बराबर-बराबर बांट लिया जाना चाहिए। हालांकि, वैश्विक स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया के बाद इंडोनेशिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि से बंधा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करती है। मगर इंडोनेशिया के इस सुझाव ने भविष्य में संभावित संकट की आशंका पैदा हर दी है। ऐसे में अगर यह जलमार्ग बाधित होता है, तो भारत के सामने ऊर्जा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। यही वजह है कि भारत निकोबार द्वीप पर 'ट्रांसशिपमेंट पोर्ट' बनाकर अपने हितों को सुरक्षित करना चाहता है।

> ग्रेट निकोबार द्वीप को आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए नीति आयोग ने वर्ष 2021 में ग्रेटर निकोबार विकास परियोजना की संकल्पना की थी। इसका मुख्य लक्ष्य हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करना है। वर्तमान में भारत के लगभग पच्चीस फीसद माल की विदेशी बंदरगाहों पर अदला-बदली होती है। मगर निकोबार में यह सुविधा उपलब्ध हो जाने से भारत को हर साल लगभग 1500 से 1800 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। साथ ही हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता को रोकने और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

चीन की नहर निर्माण योजना भी भारत के लिए सामरिक चुनौती पैदा कर सकती है। हालांकि, थाईलैंड ने अभी चीन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में भी थाईलैंड अपने इसी रुख पर कायम रहेगा। देरे-सवेर अगर चीन यहां नहर बनाने में कामयाब होता है, तो यह भारत की भू-रणनीतिक स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती होगा। नहर निर्माण के बाद दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बीच 1,200 किमी की दूरी कम हो जाएगी। नतीजतन, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा चीन की पहुंच में जाएगा। यही वजह है कि भारत, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप को विकसित कर अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करना चाहता है, ताकि देश की नौसेना हिंद महासागर से गुजरने वाले चीनी जहाजों पर नजर रख सके।

चीन अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग अस्सी फीसद और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा मलक्का जलमार्ग के रास्ते आयात करता है। ग्रेट निकोबार में भारत के इस नए सैन्य एवं वाणिज्यिक केंद्र के निर्माण से मलक्का जलमार्ग पर देश की स्थिति रणनीतिक रूप से काफी मजबूत हो जाएगी। विषम परिस्थितियों में जरूरत पड़ने पर भारत इस जलमार्ग के जरिए चीन की ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है और नाकाबंदी के जरिए स्थिति को नियंत्रित कर सकता है। इसके अलावा, भारत दक्षिण चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए वियतनाम, फिलिपींस और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ रक्षा और रणनीतिक संबंधों को गहरा करने की रणनीति पर भी काम कर रहा है। अभी तक मालवाहक जहाजों के परिवहन के लिए भारत सिंगापुर और कोलंबो जैसी विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर है। निकोबार द्वीप के विकास के बाद भारत के पास खुद का 'अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल' होगा, जिससे मुख्य मार्गों से गुजरने वाले बड़े जहाजों के लिए निकोबार में रुकना और माल की अदला-बदली का काम आसान हो जाएगा।

वर्तमान में भारत के लगभग पच्चीस फीसद माल की विदेशी बंदरगाहों पर अदला-बदली होती है। मगर निकोबार में यह सुविधा उपलब्ध हो जाने से समय और परिवहन खर्च दोनों की बचत होगी। परिणामस्वरूप भारत को हर साल लगभग 1500 से 1800 करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। साथ ही हिंद महासागर में चीन की आक्रामकता को रोकने और भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। दरअसल, पिछले कुछ दशकों से भारत की घेराबंदी के लिए चीन हिंद महासागर में पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हंबनटोटा, म्यांमा के क्योकप्यू और जिबूती में बंदरगाहों का बड़ा नेटवर्क तैयार कर चुका है। चीन के इस आक्रामक रवैये और विस्तारवादी नीतियों के प्रभाव को कम करने के लिए भारत जिस बहुआयामी रणनीति को धार देने की कोशिश कर रहा है, ग्रेटर निकोबार विकास परियोजना उसी रणनीति का हिस्सा है।

दृश्यता और अस्तित्व

विजय सिंह अधिकारी

हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां दृश्यता खुद एक मूल्य बन गई है, और अस्तित्व धीरे-धीरे 'होने' से हटकर 'दिखाई दे' की शर्त पर टिक गया है। अब केवल उपस्थित होना पर्याप्त नहीं। व्यक्ति, विचार और रचना- तीनों को निरंतर प्रमाणित होना पड़ता है। यह केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं, बल्कि आधुनिक चेतना की एक गहरी पुनर्रचना है, जहां 'होना' अब 'दृश्य होना' बनता जा रहा है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि गहराई में जाकर यह तय करता है कि मनुष्य खुद को कैसे समझे। पहले पहचान भीतर से बनती थी और धीरे-धीरे समाज में प्रकट होती थी। अब पहचान पहले दिखाई देती है और धीरे-धीरे भीतर बसने लगती है। उदाहरण के लिए, किसी विद्यार्थी की उपलब्धि अब केवल उसके ज्ञान का प्रमाण नहीं रहती, बल्कि उसके 'प्रोफाइल' की वृद्धि का माध्यम बन जाती है। इसी प्रकार किसी लेखक की रचना पहले पढ़ी नहीं जाती, बल्कि पहले 'शेयर' और 'रीच' के आंकड़ों में देखी जाती है।

इस परिवर्तन ने मनुष्य के आत्मबोध को भीतर से बाहर की ओर मोड़ दिया है। जीवन अब एक आंतरिक यात्रा नहीं, बल्कि एक सतत प्रस्तुति बन गया है, जहां व्यक्ति जीता है और उसी क्षण खुद को देखता भी है। यह स्थिति आधुनिक मनोविज्ञान में 'सेल्फ आब्जेक्टिफिकेशन' जैसी प्रवृत्ति से जुड़ती है, जहां व्यक्ति स्वयं को एक दर्शनीय वस्तु की तरह देखने लगता है।

सोशल मीडिया इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। एक साधारण अनुभव, जैसे किसी मित्र से मिलना, किसी स्थान की यात्रा, या किसी भोजन का स्वाद- अब अपने मूल रूप में नहीं रहता। उसका पहले एक ढांचा बनता है, फिर 'पोस्ट', फिर उसे देखने वालों का आंकड़ा। अनुभव का मौन पक्ष पीछे छूट जाता है। यहां एक सूक्ष्म विडंबना जन्म लेती है- जितना अधिक जीवन साझा होता है, उतना ही उसका मौन क्षीण होता जाता है। कभी चिंतन और आत्मनिर्माण की प्रयोगशाला रहा एकांत अब खालीपन या 'अनुत्पादक समय' लगने लगा है। परिणामस्वरूप मनुष्य के भीतर एक विभाजन गहरा होता है- एक अनुभव करने वाला स्व और दूसरा अनुभव को संपादित करने वाला स्व।

इसी प्रवृत्ति का विस्तार कला, साहित्य और विचार-जगत तक पहुंचता है, जहां रचना का मूल्य क्रमशः उसकी दृश्यता, पहुंच और ब्रांड-छवि से निर्धारित होने लगता है। आज यह असामान्य नहीं कि कोई कविता अपने अर्थ से पहले इंस्टाग्राम-स्वरूप में पहचानी जाए, या कोई चित्र अपनी कलात्मक गहराई से पहले 'वायरल शेयर' से जाना जाए। इस स्थिति में लेखक और कलाकार केवल सर्जक नहीं रहते, बल्कि अपनी ही दृश्यता के प्रबंधक बन जाते हैं। कई समकालीन लेखक अब अपनी लोक-छवि और डिजिटल उपस्थिति को ज्यादा महत्त्वपूर्ण मानने लगे हैं। इस बदलाव ने रचना और रचयिता के संबंध को उलट दिया है। जहां पहले रचना व्यक्ति को परिभाषित करती थी, अब व्यक्ति रचना की दृश्यता को परिभाषित करता है।

इसके समांतर, प्रकृति और श्रम एक भिन्न अस्तित्व-तर्क प्रस्तुत करते हैं। वृक्ष बिना किसी दर्शक के फल देता है। यहां उत्पादन और प्रदर्शन अलग हैं। नदी बिना किसी स्वीकृति के बहती है और मिट्टी बिना किसी प्रशंसा के जीवन को धारण करती है। हिमालय की बर्फ, जो किसी 'दृश्यता-तंत्र' का हिस्सा नहीं, फिर भी नदियों का स्रोत है- यह मौन उत्पादन का उदाहरण है। किसान का जीवन मौसम, बीज और मिट्टी के साथ एक गहरा संवाद करता है, पर उसका श्रम अंतिम रूप में केवल 'मंडी मूल्य' में दिखाई देता है। दिल्ली या मुंबई की मेज पर जो रोटी रखी है, वह दृश्य है, लेकिन उसके पीछे का श्रम अदृश्य है। इसी प्रकार, निर्माण स्थल पर काम करने वाला श्रमिक उस इमारत का निर्माता है, पर इमारत की पहचान में वह अनुपस्थित है। यह 'अदृश्य श्रम' आधुनिक सभ्यता की संरचना का आधार है।

महात्मा गांधी ने सार्वजनिक जीवन को आत्म-प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्य की साधना बनाया, जहां चरखा केवल प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का नैतिक संकेत था। भगत सिंह ने अपने लेखों में स्पष्ट किया कि व्यक्ति क्षणिक है, पर विचार स्थायी। इसलिए उन्होंने अपने जीवन को भी विचार के विस्तार में बदल दिया। इसी संदर्भ में आधुनिक गुमनाम कलाकार बैंक्सी, एलेना फेरांटे और थामस पिंचन एक अलग प्रकार की चुनौती प्रस्तुत करते हैं। बैंक्सी की कला इसलिए प्रभावशाली है, क्योंकि वह हस्ताक्षर से मुक्त है। उसका अर्थ व्यक्ति से नहीं, स्थान और संदर्भ से जन्म लेता है। एलेना फेरांटे का साहित्य यह प्रश्न उठाता है कि क्या लेखक का जीवन उसके लेखन से अधिक महत्त्वपूर्ण है। थामस पिंचन की चुप्पी साहित्य में इस तथ्य को उजागर करती है कि अनुपस्थिति भी एक संरचना बन सकती है। मगर यह प्रतिरोध भी स्थिर नहीं रहता। दृश्यता की संस्थाएं- मीडिया, बाजार और जन-जिज्ञासा गुमनामी को भी एक नई कथा में बदल देती हैं। उदाहरण के लिए, किसी अनाम कलाकार की कृति जितनी रहस्यमयी होती है, उतनी ही तेजी से वह मीडिया-चर्चा का विषय बन जाती है। इस प्रकार गुमनामी भी आखिर दृश्यता के तंत्र में फिर समाहित हो जाती है। अनुपस्थिति भी एक प्रकार की उपस्थिति बन जाती है।

प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य उस अदृश्य श्रम, मौन सृजन और बिना प्रत्याशा के दिए जाने वाले योगदान को देखने की दृष्टि विकसित कर पाया है, जिस पर उसका पूरा दृश्य संसार टिका हुआ है, या उसकी दृष्टि केवल उसी तक सीमित हो गई है, जो दिखता है, मापा जा सकता है और साझा किया जा सकता है। यही वह गहरा तनाव है जिसमें आधुनिक सभ्यता स्थित है- दृश्यता और मौन के बीच, प्रदर्शन और अस्तित्व के बीच, तथा पहचान और विसर्जन के बीच एक निरंतर खिंचा हुआ, लेकिन जीवित संतुलन।

दुनिया मेरे आगे

> दिल्ली या मुंबई की मेज पर जो रोटी रखी है, वह दृश्य है, लेकिन उसके पीछे का श्रम अदृश्य है। इसी प्रकार, निर्माण स्थल पर काम करने वाला श्रमिक उस इमारत का निर्माता है, पर इमारत की पहचान में वह अनुपस्थित है। यह 'अदृश्य श्रम' आधुनिक सभ्यता की संरचना का आधार है।

परीक्षा की शुचिता

इस समय परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे समय में चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 'गाओकाओ' पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रही है। बड़े पैमाने पर ली जाने वाली इस परीक्षा का व्यवस्थित तरीके से संपन्न होना एक बड़ी उपलब्धि है। वहां परीक्षा के दौरान सरकार, प्रशासन और समाज मिल कर ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिससे विद्यार्थियों का ध्यान भंग न हो। पुलिस, स्वयंसेवी संगठन और स्थानीय प्रशासन छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। जबकि भारत में बार-बार प्रश्नपत्र लीक और भर्ती घोटाले युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाते हैं। लाखों विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन जब प्रश्नपत्र लीक होने या धांधली की खबरें सामने आती हैं, तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि दोषियों की जिम्मेदारी तय करने और उन्हें सजा दिलाने की प्रक्रिया प्रायः लंबी होती है। कुछ समय तक विवाद रहता है, जांच समितियां बनती हैं, लेकिन धीरे-धीरे मामला स्मृति से ओझल हो जाता है। परीक्षा प्रणाली की शुचिता पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

मानवाधिकारों का प्रश्न

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों के साथ शुरू से भेदभाव और शोषण की नीति अपनाई गई। वहां मूलभूत सुविधाओं जैसे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सड़कों का अभाव दिखाई देता है। वहां के लोग अपनी दुर्दशा से निराश हैं। वे पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। यह दुखद है कि वहां बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे नागरिकों पर लगातार पाक सेना का दमन चक्र चल रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे को भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया है और दमन के खिलाफ दुनिया का ध्यान खींचा है। हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षाकर्मियों ने गोलियां चलाईं। इस घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मौत हो गई। वहां व्यापक रूप से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। विश्व समुदाय को इस पर ध्यान देना चाहिए।

– विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

जड़ता का मानस

'अंधविश्वास की मार' (संपादकीय, 12 जून) पढ़ा। इसमें कोई दोराय नहीं कि अंधविश्वास की जड़ें भारतीय समाज में बहुत गहरी हैं। जादू-टोने या डायन के नाम पर हत्या जैसे प्रकरण तो इसकी पराकाष्ठा हैं। देश में आज भी गांवों से लेकर शहरों तक झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र से इलाज होता है, जिससे कई लोग मर जाते हैं। झाड़-फूंक से पथरी और पीलिया का इलाज करने वाले कोने-कोने में हैं और अच्छे खासे पढ़े-लिखे लोग भी इनके पास जाते हैं। ताबीज और अंगूठियां तो कई लोग धारण करते हैं। दुकानों या घरों के बाहर नींबू-मिर्च टांगना आम है। नजर लग जाना और नजर उतारने को हम अंधविश्वास मानते ही नहीं। आज भी कोई भी गाड़ी शोरूम से तब तक बाहर नहीं निकलती जब तक नारियल फोड़ कर पूजा न कर ली जाए। शिक्षा और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ आर्थिक बदलाव के लिए हैं। इनसे हमारी रूढ़िवादी मान्यताओं या मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आ रहा है।

– बृजेश माथुर, गाजियाबाद

पेड़ और प्रकृति

पिछले कुछ वर्षों से देश के लगभग सभी पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन बढ़ गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है- पहाड़ों पर वृक्षों की लगातार कटाई। सड़कें बनाने या भवन निर्माण के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। पहाड़ों पर वृक्ष काटे जाते हैं, तो वहां चट्टानें कमजोर पड़ जाती हैं। जब बारिश होती है, तब वहां भूस्खलन शुरू हो जाता है। लोगों को चाहिए कि वे अपने घरों या अन्य सभी प्रकार के भवनों के आसपास कभी भी वृक्षों को न काटें। पहाड़ी इलाकों में सड़कों के निर्माण या विस्तार के समय वृक्षों को ज्यादा नुकसान न हो। उनको जड़ों से न उखाड़ा जाए। पेड़ों की लगातार कटाई न केवल पहाड़ों के लोगों के लिए, बल्कि मैदानी इलाकों के लिए भी हानिकारक है। अभी भी वक्त है। हम वृक्षों के काटने से होने वाले नुकसानों को लेकर जाग जाएं, नहीं तो फिर पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा।

– राजेश कुमार चौहान, जलंधर

रोमांचक डेरिवेटिव सौदे के जोखिम को भी समझें

जनसत्ता कारोबाजार

डेरिवेटिव ट्रेडिंग में निवेशक किसी वास्तविक संपत्ति को सीधे खरीदने-बेचने के बजाय, उसके भविष्य के मूल्य पर आधारित अनुबंध का व्यापार करते हैं। सरल शब्दों में, डेरिवेटिव का अपना कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं होता। यह अपनी कीमत उस अंतर्निहित संपत्ति से प्राप्त करता है, जिस पर यह आधारित होता है। अंतर्निहित संपत्ति वह वस्तु या संपत्ति होती है जिससे डेरिवेटिव अपना मूल्य लेता है। इसमें शामिल हैं, शेयर (जैसे- रिलायंस या टीसीएस), कमोडिटी (जैसे- सोना, चांदी या कच्चा तेल), मुद्राएं (जैसे- डालर या यूरो), बाजार सूचकांक (जैसे- निफ्टी या सेंसेक्स)। मान लीजिए, आज किसी शेयर की कीमत 100 रुपए है। आप एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं जिसमें आप तय करते हैं कि आप 3 महीने बाद इस शेयर को 110 रुपए में खरीदेंगे।

यदि 3 महीने बाद उस शेयर की कीमत 150 रुपए हो जाती है, तो भी आप उस शेयर को 110 रुपए में ही खरीद सकेंगे और बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। यही इसका रोमांच है। इसके विपरीत शेयर की कीमत अगर 110 रुपए से कम हो जाती है, तो भी आपको इसी भाव पर खरीदना होगा। इसमें नुकसान संभव है। या जोखिम है।

मुख्य रूप से चार प्रकार के डेरिवेटिव अनुबंधों का उपयोग किया जाता है। फ्यूचर्स, आप्शंस, फारवर्ड्स और स्वैप स्वैप।

फ्यूचर्स : यह एक निश्चित भविष्य की तारीख और मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने का एक पूर्व-निर्धारित समझौता होता है। इसमें खरीदार और विक्रेता दोनों अनुबंध के नियमों का पालन करने को बाध्य होते हैं।

आप्शंस : यह निवेशक को एक निश्चित तिथि पर संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन कोई बाध्यता नहीं देता। यानी अगर बाजार आपके पक्ष में नहीं है, तो आप ट्रेड से पीछे हट सकते हैं।

फारवर्ड्स : यह फ्यूचर्स की तरह ही होता है, लेकिन यह एक्सचेंजों के बजाय सीधे दो पक्षों के बीच व्यक्तिगत रूप से (ओटीसी) तय किया जाता है।

स्वैप : इसमें दो पक्ष भविष्य के नकदी प्रवाह या ब्याज दरों का आदान-प्रदान करते हैं।

निवेश की बात

ट्रेडिंग की खासियतें

निष्क्रिय शेयरों से पैसा कमाने का अवसर : मान लीजिए आपके पास कुछ निष्क्रिय शेयर हैं। अब आप इन्हें लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हैं। साथ ही, आप इन शेयरों से लाभ भी कमाना चाहते हैं। ऐसे शेयरों के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से लाभ कमाने में डेरिवेटिव्स आपकी मदद कर सकते हैं। ये आपको अपने शेयर बेचे बिना ही पैसा कमाने और ट्रेडिंग करने की सुविधा देते हैं।

आर्बिट्रेज से लाभ उठाएं : आप आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लाभ भी उठा सकते हैं। इसमें, आप किसी संपत्ति को एक बाजार में अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीदकर दूसरे बाजार में अधिक कीमत पर बेच सकते हैं। इससे आपको दोनों बाजारों के बीच कीमतों के अंतर से लाभ कमाने में मदद मिलती है।

अपने निवेशों की सुरक्षा करें : डेरिवेटिव्स का एक सबसे महत्वपूर्ण उपयोग या लाभ यह है कि यह आपके निवेशों को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने में मदद करता है।

जोखिम का हस्तांतरण : डेरिवेटिव्स के माध्यम से आप अपना जोखिम भी स्थानांतरित कर सकते हैं। जो निवेशक अपना जोखिम कम करना चाहते हैं, वे डेरिवेटिव्स का उपयोग करके अपना जोखिम उन व्यक्तियों को हस्तांतरित करते हैं जो अधिक लाभ कमाना चाहते हैं।

युद्ध का मारा बाजार, एसआइएफ से मिलेगा निवेशकों को सहारा

जनसत्ता कारोबाजार

इस समय युद्ध का मारा शेयर बाजार उबर नहीं पा रहा है। मध्यम अवधि में अच्छे रिटर्न की आशा करने वाले निवेशक परेशान हैं। ऐसे में एसआइएफ सहारा बन सकता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने नई निवेश श्रेणी 'स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स' (एसआइएफ) शुरू किया है। यह शेयर बाजार में मध्यम रिटर्न की अवधि से जूझ रहे निवेशकों के लिए एक महत्त्वपूर्ण समाधान के रूप में उभर सकता है। एसआइएफ म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है। खासकर ऐसे माहौल में जहां निवेशकों के लिए बंपर रिटर्न टेढ़ी खीर है।

स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआइएफ) के बारे में सामान्य रूप से कहें तो यह म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) के बीच के अंतर को कम करते हैं। यह अनुभवी निवेशकों को खास सेक्टर में उच्च जोखिम के साथ उच्च रिटर्न के अवसर प्रदान करते हैं। एसआइएफ निवेशक तकनीक नवउद्यम, फिनटेक और निजी इक्विटी जैसे क्षेत्रों में अवसर तलाशते हैं। फंड मैनेजर के पास डेरिवेटिव के माध्यम से पोर्टफोलियो की नेट वैल्यू का 25 फीसद तक शार्ट-सेल करने की सुविधा होती है। यह दृष्टिकोण निवेश रणनीतियों को मदद करता है। इक्विटी-फोकस्ड स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (एसआइएफ) में कम से कम 80 फीसद एसेट को इक्विटी और संबंधित इंस्ट्रूमेंट के लिए आबंटित किया जाना चाहिए। यह अनुभवी निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है। नए निवेशकों को इसमें हाथ नहीं आजमाना चाहिए या फिर विशेषज्ञ की सलाह के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

शुद्ध इक्विटी फंड उन अवधियों के लिए उपयुक्त होते हैं जब बाजार बहुत ज्यादा रिटर्न प्रदान करते हैं। जब बाजार मध्यम रिटर्न के दौर में प्रवेश करते हैं, तो निवेशकों को अन्य श्रेणियों की जरूरत होती है जो जोखिम को कम करके बेहतर परिणाम उत्पन्न कर सके। सेबी ने जो एसआइएफ ढांचे का निर्माण किया है वह पारंपरिक म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन उत्पादों के बीच मौजूद अंतर को दूर करते हुए निवेश का मध्यम मंच तैयार करता है। यह दस लखिया निवेशकों के लिए अच्छा मंच साबित हो सकता है।

20 फीसद या उससे अधिक वार्षिक रिटर्न की उम्मीद

फंड्स का फंडा

करने वाले निवेशकों के लिए एसआइएफ उपयुक्त नहीं है। इसी तरह, पूंजी संरक्षण चाहने वाले निवेशकों को भी इनसे बचना चाहिए। एसआइएफ उन दीर्घकालिक निवेशकों के लिए हैं जो अस्थिरता को समझते हैं। पोर्टफोलियो मूल्य में आवधिक उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और कम से कम 10 लाख रुपए का निवेश करने को तैयार हैं, जो नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा है।

पारंपरिक मल्टी-एसेट फंडों के विपरीत, जिन्हें सोने और चांदी जैसी विशिष्ट परिसंपत्ति श्रेणियों में निवेश बनाए रखना अनिवार्य होता है, 'एक्टिव एसेट एलोकेटर' (एसआइएफ) श्रेणी अनिवार्य आवंटन से बंधी नहीं होती है। सेबी ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्तिगत स्कीम के लिए अलग से आवश्यक होने के बजाय किसी विशेष एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) द्वारा आफर की जाने वाली सभी एसआइएफ रणनीतियों को कवर करने वाले पैन लेवल पर 10 लाख रुपए की न्यूनतम निवेश सीमा लागू होती है। सेबी ने एसआइएफ को तीन मुख्य निवेश दृष्टिकोणों के तहत काम करने के लिए अधिकृत किया है। इक्विटी-ओरिएंटेड, डेट-ओरिएंटेड और हाइब्रिड रणनीतियां।

यह अधिक रकम निवेश की सुविधा देता है। फिक्स्ड-इनकम चाहने वालों के लिए अच्छा है। म्यूचुअल फंड और पीएमएस विभिन्न निवेश सेगमेंट को पूरा करते हैं, तो एसआइएफ मध्यम आधार प्रदान करके अंतर को कम करते हैं। 50 लाख की जरूरत वाले पीएमएस की तुलना में एसआइएफ के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्ति (एचएनआइ) और उच्च जोखिम क्षमता वाले अनुभवी निवेशों के लिए यह तैयार किया गया है। जो अत्याधुनिक रणनीतियों और व्यापक एक्सपोजर सीमाओं की तलाश करते हैं। एसआइएफ फंड मैनेजर को कस्टमाइज्ड उत्पाद बनाने में सक्षम बनाते हैं, जो पारंपरिक म्यूचुअल फंड में शामिल नहीं होते हैं।

इसमें व्यापक डाइवर्सिफिकेशन है। एसआइएफ लंबी अवधि या कम लिक्विड एसेट में फंड आवंटित करने के लिए अधिक सुविधा प्रदान करते हैं, जो लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए प्रतिबद्ध इन्वेस्टर के लिए रिटर्न को संभावित रूप से बढ़ा सकते हैं। एसआइएफ लांच करने के लिए वाले एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) का न्यूनतम आपरेशनल इतिहास तीन वर्षों का होना चाहिए।

सेबी ने एसआइएफ को तीन मुख्य निवेश दृष्टिकोणों के तहत काम करने के लिए अधिकृत किया है। इक्विटी-ओरिएंटेड, डेट-ओरिएंटेड और हाइब्रिड रणनीतियां। यह अधिक रकम निवेश की सुविधा देता है। फिक्स्ड-इनकम चाहने वालों के लिए अच्छा है। म्यूचुअल फंड और पीएमएस विभिन्न निवेश सेगमेंट को पूरा करते हैं, तो एसआइएफ मध्यम आधार प्रदान करके अंतर को कम करते हैं। 50 लाख की जरूरत वाले पीएमएस की तुलना में एसआइएफ के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए की आवश्यकता होती है।

गिरते शेयर बाजार में अपनाएं विपरीत निवेश की रणनीति

जनसत्ता कारोबाजार

पश्चिम एशिया के हालात, अमेरिका की अस्थिर कर नीति और वैश्विक व्यापार की अनिश्चितताओं के कारण दुनिया के शेयर बाजार भी उथलपुथल के दौर से गुजर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में भी मायूसी का आलम है। अधिकांश समय बाजार में गिरावट का माहौल रहता है। ऐसे में आम निवेशक के सामने दुविधा रहती है कि वो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में निवेश की सबसे सटीक रणनीति है विपरीत निवेश यानि 'कंट्रैरियन इन्वेस्टिंग'। यह आजमाया हुआ फार्मूला है। विश्व के दिग्गज अरबपति वारेन बफेट, चार्ली मंगर, लेखक डेविड ड्रेमन, रे डेलियो, जान टेम्पलटन, माइकल बरी और जार्ज सोरोस, सभी ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने गिरते बाजार में विपरीत निवेश रणनीति अपनाने वाले निवेशकों के रूप में अपनी पहचान बनाई है। ये लोग अपने लेखन में, अपनी सलाह में, इस नीति पर चलने की सलाह भी देते हैं।

आखिर कंट्रैरियन इन्वेस्टिंग (विपरीत निवेश) क्या है? तो यह एक ऐसी निवेश रणनीति है, जिसमें निवेशक बाजार के प्रचलित रुझान और बहुमत सोच (झुंड मानसिकता) की विपरीत दिशा में काम करते हैं। इसकी रणनीति है कि किसी भी आर्थिक कारण से जब शेयर बाजार में ज्यादातर लोग शेयर बेच रहे हों तब खरीदें, और जब सब खरीद रहे हों तब बेचें। विपरीत निवेश रणनीति के प्रमुख पहलू हैं कि बहुमत के डर का फायदा उठाएं। जब बाजार में घबराहट या मंदी का माहौल होता है और लोग पैनिक में आकर मजबूत कंपनियों के शेयर भी बेच देते हैं, तब कंट्रैरियन निवेशक उन्हें कम कीमत पर खरीद लेते हैं। इस रणनीति में लालच से बचने के गुर अपनाए जाते हैं। जब बाजार अत्यधिक आशावादी (ओवर प्राइस्ड) होता है और किसी शेयर या

कंट्रैरियन इन्वेस्टिंग (विपरीत निवेश) क्या है? तो यह एक ऐसी निवेश रणनीति है, जिसमें निवेशक बाजार के प्रचलित रुझान और बहुमत सोच (झुंड मानसिकता) की विपरीत दिशा में काम करते हैं। इसकी रणनीति है कि किसी भी आर्थिक कारण से जब शेयर बाजार में ज्यादातर लोग शेयर बेच रहे हों तब खरीदें और जब सब खरीद रहे हों तब बेचें।

शेयर सूत्र

सेक्टर की कीमत उसके वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है, तब ये निवेशक मुनाफा वसूल करके बाहर निकल जाते हैं। यह रणनीति सिर्फ अलग दिखने के लिए नहीं, बल्कि बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित होती है। निवेशक कंपनी के वास्तविक मूल्य का विश्लेषण करते हैं और धैर्य के साथ सही समय का इंतजार करते हैं।

कंट्रैरियन इन्वेस्टिंग के मूल विचार को गहराई से समझना जरूरी है। शार्ट-टर्म में शेयर बाजार डर और लालच जैसी भावनाओं से संचालित होते हैं। इसके कारण अच्छी कंपनियों के शेयर भी कभी-कभी अपनी सही कीमत से काफी नीचे गिर जाते हैं। एक कंट्रैरियन निवेशक का मानना होता है कि बाजार की अति-प्रतिक्रिया हमेशा के लिए नहीं रहती, और अंततः शेयर की कीमत उसके वास्तविक मूल्य पर लौट आती है। कोई भी शेयर जो सस्ता मिल रहा है, जरूरी नहीं कि वह हमेशा ऊपर ही जाए। इसलिए गहन शोध बहुत जरूरी है। विपरीत निवेश का मतलब है कि बाजार में हालात जितने खराब दिखते हैं, लाभ कमाने के अवसर उतने ही बेहतर होते हैं। कंट्रैरियन निवेशक तब उत्साहित होते हैं जब किसी अच्छी कंपनी के शेयर की कीमत में अचानक, लेकिन अनुचित रूप से गिरावट आती है। लेकिन विपरीत निवेश रणनीति में लार्ज और मिडकैप आकार की मजबूत कंपनियों के शेयर का चुनाव करना चाहिए।

'कंट्रैरियन' और 'वैल्यू इन्वेस्टिंग' काफी हद तक समान हैं। 'वैल्यू इन्वेस्टिंग' पूरी तरह से वित्तीय आंकड़ों पर केंद्रित होती है, जबकि 'कंट्रैरियन इन्वेस्टिंग' में बाजार की लोकप्रियता का भी आकलन किया जाता है। जब परिसंपत्तियों का मूल्यांकन गिरता है, तो विपरीत मूल्य निवेश रणनीति कारगर साबित होती है, जिससे निवेशकों को रियायती मूल्य पर मूल्यवान शेयर खरीदने का मौका मिलता है। दूसरी ओर, यह रणनीति तब कारगर नहीं होती जब निवेश इस विश्वास पर आधारित होता है कि कंपनी भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन अभी तक उसने ऐसा नहीं किया है। दरअसल, चार प्रकार के निवेशक होते हैं। व्यक्तिगत निवेशक, संस्थागत निवेशक, एंजल निवेशक और वेंचर कैपिटलिस्ट। इनमें व्यक्तिगत निवेशक को अधिक सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि बाकी के पास विशेषज्ञ रणनीतिकार होते हैं। व्यक्तिगत निवेशकों को विपरीत निवेश रणनीति से सीखना चाहिए।

शेयर बाजारों में हालिया गिरावट ने शेयरों के 'वैल्यूएशन प्रीमियम' को कम किया है। मतलब कि अब अच्छे शेयरों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि समाप्त हो गई है। अब निवेशक लार्ज-मिडकैप आकार की कंपनियों को अधिक आरामदायक स्तर पर खरीद सकते हैं। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले महीनों में भारत उच्च विकास के दौर में प्रवेश करेगा।

तैयारी

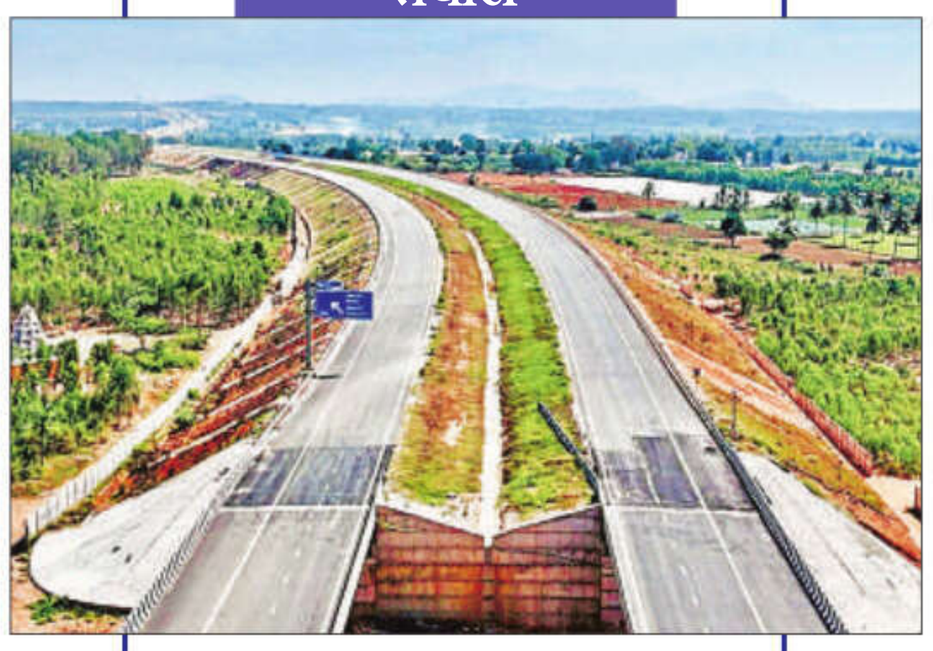

औद्योगिक गलियारे के तहत बनाए गए बंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे का दृश्य।

भारत में सबसे अच्छे निवेश के सात विकल्प

जनसत्ता कारोबाजार

भारत में अपने लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार निवेश करना सबसे महत्त्वपूर्ण है। सात निवेश विकल्प दिए जा रहे, जो सुरक्षा, अच्छे रिटर्न व कर लाभ का शानदार संतुलन प्रदान करते हैं।

म्यूचुअल फंड : बाजार से जुड़े होने के कारण यह लंबी अवधि में सबसे ज्यादा (लगभग 12%-18%) रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड : यह सरकार समर्थित सबसे सुरक्षित लंबी अवधि (15 वर्ष) की योजना है। इसमें निवेश की गई राशि, ब्याज और मिलने वाली मैच्योरिटी, तीनों करमुक्त होते हैं।

राष्ट्रीय पेंशन योजना : सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए यह एक बेहतरीन सरकारी योजना है।

शेयर बाजार और आइपीओ : यदि आपके पास बाजार की समझ है, आप जोखिम उठा सकते हैं, तो सीधे कंपनियों के शेयरों में निवेश करके या आइपीओ में पैसा लगाकर आप कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

सावरेन गोल्ड बांड : यह फिजिकल गोल्ड (सोना) खरीदने का सबसे सुरक्षित और फायदेमंद डिजिटल विकल्प है।

बैंक और पोस्ट आफिस एफडी और रियल एस्टेट भी भारत में सुरक्षित निवेश के विकल्प माने जाते हैं। इसमें नुकसान की गुंजाइस नहीं रहती है।

क्रिप्टोकरंसी में मुनाफा कमाने के हैं कई तरीके

दिव्या तंवर

पश्चिम एशिया संकट के बाद विश्व में जो आर्थिक हालात बने हैं, उसमें क्रिप्टोकरंसी ने अच्छी मजबूती हासिल की है। अरबपति पूंजीपतियों के क्रिप्टो कारोबार में उतरने के बाद से निवेशकों का रुझान और बढ़ा है। लेकिन आम निवेशक क्रिप्टो से कैसे कमाएं, यह जानना जरूरी है। क्रिप्टोकरंसी से पैसे कमाने के मुख्य तरीके हैं- सही समय पर काइन खरीदकर होल्ड करना, डे-ट्रेडिंग, स्टेकिंग के जरिए ब्याज कमाना, और नए प्रोजेक्ट्स के एयरड्राप्स में हिस्सा लेना।

निवेश और होल्डिंग (एचओडीएल) : यह सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। इसमें आप बिटकाइन, इथेरियम जैसे मजबूत क्रिप्टोकरंसी में पैसे लगाते हैं और उन्हें लंबे समय के लिए होल्ड (रखते) करते हैं। जब भविष्य में उन क्रिप्टोकरंसी की कीमत बढ़ती है, तो आप उन्हें बेचकर मुनाफा कमाते हैं।

क्रिप्टो ट्रेडिंग : इसमें आप कम समय में मुनाफा कमाने के लिए क्रिप्टोकरंसी खरीदते और बेचते हैं।

क्रिप्टो करामात

क्रिप्टोकरंसी को कम कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचना स्पाट ट्रेडिंग कहलाता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप क्रिप्टोकरंसी की कीमत घटने या बढ़ने, दोनों परिस्थितियों में पैसे कमा सकते हैं। हालांकि, यह काफी जोखिम भरा होता है और इसके लिए बाजार की अच्छी समझ होनी चाहिए। क्रिप्टो एसआइपी : आप शेयर बाजार की तरह हर महीने एक निश्चित राशि क्रिप्टो में निवेश करके लंबे समय में भारी मुनाफा कमा सकते हैं।

स्टेकिंग : अगर आप अपनी क्रिप्टोकरंसी को लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी एक्सचेंज (जैसे- वजीरएक्स या व्हाइन डीसीएक्स) पर लाक या स्टेक

कर सकते हैं। इसके बदले में ब्लाकचेन नेटवर्क आपको ब्याज के रूप में अतिरिक्त क्वाइन देता है, जिससे आपकी पैसिव इनकम होती है।

एयरड्राप्स : कई नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपनी मार्केटिंग और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लोगों को मुफ्त में अपने टोकन देते हैं। इसे एयरड्राप्स कहते हैं। इनके सोशल मीडिया टास्क पूरे करके या गिवअवे में शामिल होकर आप मुफ्त व्हाइन प्राप्त कर सकते हैं और बाद में उन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं।

लिक्विडिटी फार्मिंग और लेंडिंग : आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफार्म्स का इस्तेमाल करके अपनी क्रिप्टो एसेट्स को उधार दे सकते हैं। आपको उधारकर्ताओं से ब्याज और फीस के रूप में अच्छी कमाई होती है।

क्रिप्टो यील्ड फार्मिंग : क्रिप्टोकरंसी में यील्ड फार्मिंग और स्टेकिंग दोनों ही निष्क्रिय आय कमाने के लोकप्रिय तरीके हैं, लेकिन दोनों की कार्यप्रणाली और जोखिम अलग-अलग हैं। स्टेकिंग का मुख्य उद्देश्य ब्लाकचेन नेटवर्क (जैसे एथेरियम) को सुरक्षित और चालू रखना है। आप अपने क्रिप्टो व्हाइन्स को एक तय अवधि के लिए ब्लाकचेन नेटवर्क पर लाक (जमा) कर देते हैं, जो नेटवर्क के प्रूफ-आफ-स्टेक (पीओएस) मैकेनिज्म को समर्थन देता है। नेटवर्क आपको लेनदेन प्रमाणित करने के बदले ब्याज देता है, जो आम तौर पर स्थिर होता है। इसमें जोखिम है कि आपके फंड लाक हो जाते हैं, जिन्हें आप तुरंत नहीं बेच सकते। यील्ड फार्मिंग का संबंध विकेंद्रीकृत वित्त से है। इसमें आप अपनी क्रिप्टोकरंसी को तरलता प्रदान करने के लिए विभिन्न डीईएफआइ प्रोटोकाल (जैसे- उधार देने वाले प्लेटफार्म) के तरलता पूल में जमा करते हैं। बदले में आपको ट्रेडिंग फीस या अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा चुकाया गया ब्याज मिलता है, और अक्सर अतिरिक्त गवर्नेंस टोकन भी दिए जाते हैं। यह अधिक जटिल है। क्रिप्टोकरंसी की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे आपके रिटर्न का डालर के समकक्ष मूल्य बढ़ या घट सकता है।

जोखिमों को समझना

जब आप क्रिप्टोकरंसी को स्टेक करते हैं, तो आप आमतौर पर इसे एक नेटवर्क वैलिडेटर के पास लाक कर देते हैं, जो ब्लाकचेन को बनाए रखने में मदद करने वाला एक भागीदार होता है। यदि वैलिडेटर या नेटवर्क विफल हो जाता है, या वैलिडेटर गलत व्यवहार करता है, तो आपको 'स्लैशिंग' नामक दंड के माध्यम से अपने कुछ स्टेक किए गए टोकन खोने पड़ सकते हैं या पुरस्कार से वंचित होना पड़ सकता है।

> जब तक महिलाओं को हर प्रकार के उत्पीड़न से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं। -नेल्सन मंडेला

आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और जी-7 को समेटे प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद-आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

मोदी और मैक्रों

ऐसे समय में, जब विश्व व्यवस्था गहरे बदलावों के दौर से गुजर रही है, तब प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा और दोनों देशों की बढ़ती निकटता सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों का विषय नहीं, बल्कि यह बदलती वैश्विक राजनीति में भारत व फ्रांस के साझा दृष्टिकोण का भी संकेत है। गौरतलब है कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की यह सातवीं आधिकारिक फ्रांस यात्रा है। इससे पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फरवरी में भारत का दौरा किया था, तब दोनों देश आपसी रिश्तों को खास वैश्विक रणनीतिक सहयोग का दर्जा देने पर सहमत हुए थे। दरअसल, दोनों देशों के संबंधों की खासियत ही यह रही है कि वे समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। 1976 में जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को लेकर दुनिया भर में देश की आलोचना हो रही थी, तब वह फ्रांस के प्रधानमंत्री जैक्स शिराक ही थे, जो हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने को राजी हुए थे। इसी तरह, 1998 में भी जब भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद कई पश्चिमी देशों ने नई दिल्ली से दूरी बना ली थी, तब फ्रांस उन चुनिंदा देशों में से था, जिन्होंने भारत के साथ संवाद व सहयोग का रास्ता खुला रखा। जाहिर है कि ये घटनाएं दोनों देशों की व्यावहारिक सोच व दूरदर्शिता का सुबूत हैं, कि उन्होंने किस तरह से कूटनीतिक तौर पर इन रिश्तों की संवेदनशील प्रकृति को बनाए रखा। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को सिर्फ एक औपचारिक राजनयिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, यह उस रणनीतिक साझेदारी को अधिक गहरा करने का अवसर भी है, जिसने पिछले तीन दशकों में लगातार विस्तार पाया है। मैक्रों का यह कहना अहम है कि भारत अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र में दुनिया का अगुआ बना हुआ है। इस संदर्भ में फ्रांस में आयोजित 'भारत इनोवेट्स' कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य भारत की उभरती नवाचार क्षमता, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीकी उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है।

प्रधानमंत्री मोदी ने उचित ही इसे भारतीय युवा प्रतिभा और फ्रांस की विशेषज्ञता के बीच का पुल बताया है, जो नए अवसर पैदा करेगा। यह देखते हुए कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, तकनीकी रूप से उन्नत फ्रांस के साथ उसका जुड़ाव निवेश व व्यापार के लिहाज से ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के युवाओं, शोधकर्ताओं और उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ाने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आज जब दुनिया नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और जी-7 को समेटे प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद-आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है।

हक के लिए लड़ती महिलाओं को सलाम

अफगानिस्तान के हेरात में महिलाओं पर हुई गोलीबारी महज एक स्थानीय घटना नहीं मानी जा सकती। यह उस वैश्विक संघर्ष का हिस्सा है, जिसमें महिलाएं अपने जीवन, अपने शरीर और अपने भविष्य पर स्वयं निर्णय लेने के अधिकार के लिए लड़ रही हैं। यह लड़ाई वस्त्रों की नहीं, स्वतंत्रता की है।

अफगानिस्तान के हेरात में हिजाब संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप में महिलाओं की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शन पर गोलीबारी कर दो लोगों की हत्या किए जाने की खबर ने दुनिया को एक बार फिर याद दिलाया है कि महिलाओं की स्वतंत्रता का मुद्दा आज भी कई देशों में जीवन और मृत्यु का मुद्दा बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों के नारे थे, 'शिक्षा, काम, स्वतंत्रता।' ये तीनों मांगें ऐसे मूलभूत मानवाधिकार हैं, जिन्हें दुनिया के अधिकांश लोग स्वाभाविक मानते हैं। लेकिन, अफगानिस्तान की अनेक महिलाओं को इन्हीं अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर अपनी जान तक देनी पड़ रही है।

यह दृश्य नया नहीं है। कुछ वर्ष पहले ईरान में महसा अमीनी की मृत्यु के बाद लाखों महिलाएं सड़कों पर उतर आई थीं। उन पर आरोप था कि उन्होंने अनिवार्य हिजाब 'ठीक तरह से नहीं पहना' था। उनकी मृत्यु ने पूरे देश में 'महिला, जीवन और स्वतंत्रता' से जुड़े ऐतिहासिक आंदोलन को जन्म दिया। उस आंदोलन को दबाने के प्रयास में सैकड़ों लोग मारे गए। अफगानिस्तान व ईरान की राजनीतिक व्यवस्थाएं एक जैसी नहीं हैं। पर, दोनों मामलों में एक समानता स्पष्ट दिखाई देती है- महिलाओं के पहनावे को राज्य के नियंत्रण का विषय बना दिया गया है। जब राज्य किसी वयस्क महिला को यह बताने लगे कि उसे क्या पहनना चाहिए, तब आमतौर पर शिक्षा, रोजगार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी धीरे-धीरे सीमित होने लगते हैं।

तस्लीमा नसरीन
जानी-मानी लेखिका

अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा लगभग पूरी तरह बंद कर दी गई है। अनेक कार्यक्षेत्रों में महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और सार्वजनिक जीवन में उनकी उपस्थिति सीमित कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों और अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों ने बार-बार इन नीतियों की आलोचना की है। लेकिन, इस कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। वह है

महिलाओं का प्रतिरोध। ईरान की तरह अफगानिस्तान की सड़कों पर और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम महिलाओं का एक वर्ग यह कह रहा है कि हम अपने जीवन के बारे में निर्णय स्वयं लेंगे। हम शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता चाहते हैं। उन्होंने यह दिखा दिया है कि महिलाओं का अपना संघर्ष ही दरअसल बदलाव की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है।

मेरी सोच यह है कि स्त्री-विरोध, भेदभाव और हिंसा के विरुद्ध मुस्लिम महिलाओं को ही सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरना होगा। कोई भी पहनावा यदि स्वेच्छा से पहना जाए, तो वह अलग बात है। पर, यदि राज्य, परिवार, समाज या धार्मिक पुलिस उसे जबरन थोपे, तो फिर वह व्यक्तिगत पसंद नहीं रह जाती, इसके बजाय वह स्वतंत्रता का प्रश्न बन जाती है।

इतिहास में हर बड़ा सामाजिक परिवर्तन कुछ साहसी लोगों के विरोध से शुरू हुआ है। आज अफगानिस्तान की वे महिलाएं, जो गोलियों के सामने भी 'शिक्षा, काम, स्वतंत्रता' का नारा लगा रही हैं, वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुनियाभर की महिलाओं की स्वतंत्रता के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई स्त्री हिजाब, नकाब या बुर्का स्वेच्छा से पहनती है? मैं उस संस्कृति के विरुद्ध हूं, जो महिलाओं के पहनावे को धार्मिक कर्तव्य बना देती है और अपराधबोध या भय के जरिये उन्हें नियंत्रित करती है। वास्तविक स्वतंत्रता तो तभी आएगी, जब कोई महिला बिना किसी धार्मिक, सामाजिक या सरकारी दबाव के अपने वस्त्र स्वयं चुन सकेगी। यदि इस तरह का माहौल बनता है, तो स्वतंत्र और दबाव-मुक्त परिस्थितियों में हिजाब, बुर्का या नकाब पहनने वाली मुट्ठीभर महिलाएं ही होंगी। कोई महिला यदि फैशन, मौसम या व्यक्तिगत पसंद के कारण अपने बाल ढकना चाहे, तो यह उसका अधिकार है, लेकिन बाल ढकने को नैतिक या धार्मिक अनिवार्यता के रूप में थोपे जाने का मैं घोर विरोध करती हूं। मेरे विचार में हिजाब, बुर्का और नकाब के पीछे तर्क नहीं, बल्कि पितृसत्तात्मक षड्यंत्र और गहरा स्त्री-विरोध मौजूद है।

अपने जीवन को जोखिम में डालकर सड़कों पर उतर आना कोई सहज काम नहीं है। ईरान की लड़कियां जानती थीं कि विरोध की कीमत भयानक हो सकती है। वे जानती थीं कि गिरफ्तारी, यातना और यहां तक कि मौत की सजा भी उन्हें मिल सकती है। फिर भी, उन्होंने विद्रोह किया। सड़कों पर हिजाब जलाकर उन्होंने यह घोषणा की कि अब वे भय को स्वीकार नहीं करेंगी। अफगानिस्तान की महिलाओं की स्थिति तो और भी कठोर है। वर्षों से उन्हें शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया है। फिर भी आज वे भी सड़कों पर उतर आई हैं। वे जानती हैं कि यह रास्ता चुनना महंगा पड़ सकता है। अफगानिस्तान जैसे गहरे स्त्री-विरोधी और दमनकारी वातावरण में किसी महिला का विरोध केवल एक महिला का विरोध नहीं होता, बल्कि वह लाखों महिलाओं की आवाज बन जाता है। ये स्त्रियां दुनिया को संदेश देना चाहती हैं कि वे अब उत्पीड़न, भेदभाव और अपमान का जीवन स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वे शिक्षा, काम, स्वतंत्रता और इन्सान की तरह जीने का अधिकार चाहती हैं। अफगानिस्तान और ईरान की सड़कों पर खड़ी होकर अपने अधिकारों की मांग करने वाली महिलाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वतंत्र और समान अधिकारों वाले समाज का सपना गढ़ रही हैं। शिक्षा, काम और स्वतंत्रता की मांग के लिए जिन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर सड़कों पर उतरने का साहस दिखाया है, उनके प्रति मेरा गहरा सम्मान है। जिस देश में महिलाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है, वहां विरोध करना असाधारण साहस का परिचायक है।

किसी भी राज्य, सरकार या धार्मिक प्राधिकरण को यह अधिकार नहीं है कि वह लोगों के मूलभूत अधिकारों की मांग का उत्तर गोलियों से दे। शिक्षा, काम और स्वतंत्रता मांगना अपराध नहीं है; बल्कि उस मांग को कुचलने के लिए क्रूरता और बर्बरता का सहारा लेना अपराध है। अफगानिस्तान की सड़कों पर खड़े होकर आज जो लोग 'शिक्षा, काम, स्वतंत्रता' का नारा लगा रहे हैं, वे केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वे उन वंचित, अपमानित, उपेक्षित और तिरस्कृत महिलाओं की ओर से भी बोल रहे हैं, जो इन्सानी अधिकारों से वंचित हैं। स्वतंत्रता का संघर्ष लंबा हो सकता है, पर इतिहास इस बात का साक्षी है कि मनुष्य की मुक्ति की आकांक्षा को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। आज अफगानिस्तान की महिलाओं का संघर्ष किसी ड्रेस कोड के विरुद्ध नहीं है, बल्कि महिलाओं पर धार्मिक और राजनीतिक प्रभुत्व के विरुद्ध है। उनका संघर्ष मूलतः इन्सान की तरह जीने का संघर्ष है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

वर्नर हाइजेनबर्ग

प्रारंभिक ज्ञान कभी-कभी अहंकार उत्पन्न करता है। पर जब वह ज्ञान परिपक्व होता है, जब मनुष्य वास्तविकता की अथाह जटिलता और रहस्य का सामना करता है, तब उसका अहंकार टूटने लगता है।

अस्तित्व भी एक रहस्य ही है

जब कोई युवा मन पहली बार विज्ञान के संसार में प्रवेश करता है, तो उसे लगता है कि उसने प्रकृति के रहस्यों की चाबी पा ली है। वह देखता है कि बिजली आकाशीय देवताओं का क्रोध नहीं, बल्कि विद्युत आवेशों का नतीजा है। ग्रहों की गति किसी अदृश्य शक्ति की मनमानी से नहीं, बल्कि गणितीय नियमों से संचालित होती है। जीवन की अनेक प्रक्रियाएं रसायन और जीव विज्ञान के सिद्धांतों से समझी जा सकती हैं। इस पहले अनुभव में विज्ञान मनुष्य को एक अद्भुत आत्मविश्वास देता है। उसे लगता है कि जिन प्रश्नों के उत्तर पहले धर्म, मिथक या दर्शन में खोजे जाते थे, वे अब प्रयोगशालाओं और समीकरणों में मिल सकते हैं। और यहीं एक सूक्ष्म खतरा भी उपस्थित होता है।

विज्ञान का पहला घूंट अक्सर मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि वास्तविकता पूरी तरह समझी जा सकती है। जैसे कि जो कुछ है, वह केवल पदार्थ है, ब्रह्मांड एक विशाल मशीन मात्र है, और रहस्य नाम की कोई चीज नहीं बची। इस अवस्था में ईश्वर, आत्मा, या आध्यात्मिकता जैसी अवधारणाएं उसे फिजूल लगने लगती हैं। विज्ञान ने अनेक अंधविश्वासों को चुनौती दी है। लेकिन विज्ञान की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जब शोधकर्ता प्रकृति के रहस्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है, तब उसका आत्मविश्वास धीरे-धीरे विनम्रता में बदलने लगता है। प्रकृति हमारी सहज धारणाओं से कहीं अधिक रहस्यमय है। ज्ञान बढ़ने का अर्थ प्रश्नों की गहराई बढ़ना है। हम जान सकते हैं कि तारे कैसे बनते हैं, लेकिन यह प्रश्न बना रहता है कि ऐसा ब्रह्मांड है ही क्यों, जिसमें तारे बन सकें। विज्ञान जितना गहरा होता जाता है, उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि वास्तविकता का अंतिम आधार यांत्रिक व्याख्या से परे है। विज्ञान अपनी सर्वोच्च सफलता में हमें विनम्र बनाता है। वह हमें यह दिखाता है कि ज्ञान और रहस्य विरोधी नहीं, बल्कि सहयात्री हैं। सच्चा वैज्ञानिक वह है, जो जितना अधिक जानता है, उतना ही अधिक विस्मित होता जाता है। यह एक ऐसी गहराई है, जिसमें प्रत्येक खोज हमें और अधिक गहराई की ओर ले जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि प्राकृतिक विज्ञान का पहला घूंट मनुष्य को नास्तिक बना सकता है, लेकिन गिलास के तल में ईश्वर उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। यहां ईश्वर शब्द से मेरा आशय उस अंतिम रहस्य से है, जो समस्त अस्तित्व के पीछे विद्यमान है, उस गहन व्यवस्था से है, जो ब्रह्मांड को अर्थ और संरचना प्रदान करती प्रतीत होती है, उस विस्मय से है, जो तब उत्पन्न होता है, जब हम समझते हैं कि हमारी बुद्धि वास्तविकता को छू तो सकती है, पर उसे पूरी तरह अपने अधिकार में नहीं ले सकती। प्रारंभिक ज्ञान कभी-कभी अहंकार उत्पन्न करता है। पर जब वह ज्ञान परिपक्व होता है, जब मनुष्य वास्तविकता की अथाह जटिलता और रहस्य का सामना करता है, तब उसका अहंकार टूटने लगता है। और उसी विनम्रता में वह अनुभव करता है कि अस्तित्व केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, वह एक रहस्य भी है।

विनम्रता को अपनाएं

सूत्र

ज्ञान का आरंभ मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि उसने सत्य को पा लिया है, परंतु ज्ञान की परिपक्वता उसे सिखाती है कि सत्य अधिक रहस्यमय है। जो व्यक्ति सीखते-सीखते विनम्र हो जाता है, वही वास्तविक बुद्धिमत्ता के निकट पहुंचता है। खोज हमें स्मरण कराती है कि अस्तित्व विस्मय, गहराई और अनंत संभावनाओं से भरा एक अद्भुत रहस्य है।

दूसरा पहलू

वैज्ञानिकों ने अमेजन के जंगलों के नीचे छिपी ऐसी दुनिया का खुलासा किया है, जिसने इतिहासकारों व पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है।

खोया हुआ साम्राज्य, जिसे पेड़ों ने छिपा रखा था

■ *जोस इरियार्टे*

क्या आप सोच सकते हैं कि जिसे हम सदियों से एक 'विशाल और रहस्यमयी जंगल' समझते रहे, उसके नीचे एक भव्य और सुनियोजित शहरी नेटवर्क छिपा हुआ है? ऐसा माना जाता रहा है कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन वन की कठिन जलवायु, बाढ़, सूखा और खराब मिट्टी सभ्यताओं के विकास में बाधा थी। पर, वैज्ञानिकों ने 'लिडार' तकनीक की मदद से अमेजन के घने जंगलों के नीचे छिपी एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया है, जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है।

इस खोज में सबसे प्रमुख नाम बोलीविया की 'कसारबे संस्कृति' का है, जो करीब ईस्वी 500 से 1400 के बीच यहां फल-फूल रही थी। लगभग न्यू जर्सी जितने बड़े इलाके में फैली यह सभ्यता वास्तुकला और शहरी नियोजन का एक बेजोड़ अजूबा थी। यहां के मुख्य और बड़े शहरों में 20 मीटर से भी ऊंचे पिरामिड, सार्वजनिक सभाओं के लिए विशाल मंच और मानव-निर्मित ऊंचे चबूतरे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस सभ्यता के सभी बड़े निर्माण एक खास दिशा में झुके हुए हैं, जो दर्शाता है कि उनका जीवन खगोल विज्ञान और ब्रह्मांडीय मान्यताओं से गहराई से प्रेरित था। कसारबे के लोग प्रकृति के बीच रहकर 'लो-डेंसिटी ट्रॉपिकल अर्बनिज्म', यानी कम घनत्व वाले वन-नगरों को बसाने में माहिर थे। उन्होंने घने जंगलों के बीच में खुली जगहें, बाग और खेत बनाए। एक ऐसी बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली तैयार की, जिससे लोग सूखे और बाढ़, दोनों मौसमों में खेती कर सकें। उन्होंने फसलें उगाने के साथ जीवों को पालतू बनाने की कला भी सीख ली थी। अमेजन की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए चारकोल, हड्डियों और जैविक कचरे को मिलाकर एक विशेष मिट्टी तैयार की, जिसे आज 'अमेजोनियन डार्क अर्थ' कहा जाता है। लिडार तकनीक ने बोलीविया के साथ-साथ इक्वाडोर की उपानो घाटी और ब्राजील के रहस्यमय 'सन विलेजेस' जैसी बस्तियों को भी उजागर किया। वैज्ञानिक मानते हैं कि अमेजन के सीने में 10,000 से अधिक ऐसी और प्राचीन संरचनाएं दफन हैं, जिन्हें खोजा जाना बाकी है।

कसारबे और अमेजन की ये लुप्त संस्कृतियां आज के जलवायु संकट से जूझ रहे आधुनिक विश्व को एक बहुत बड़ा सबक देती हैं।

अमेजन के सीने में अब भी 10,000 से अधिक प्राचीन संरचनाएं दफन हैं, जिन्हें खोजा जाना बाकी है। ये प्राचीन सभ्यताएं हमें विकास के सबक देती हैं।

कसारबे और अमेजन की ये लुप्त संस्कृतियां आज के जलवायु संकट से जूझ रहे आधुनिक विश्व को एक बहुत बड़ा सबक देती हैं। आज जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तब अमेजन की ये प्राचीन सभ्यताएं हमें विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन का एक महत्वपूर्ण सबक देती हैं।

-द कन्वर्सेशन

आंकड़े

फीफा और रिकॉर्ड

फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार तीन देश मेजबान हैं, 48 टीमें भाग ले रही हैं और कुल 104 मैच खेले जाएंगे, जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था।

2026	104
2022	64
1978	38
1934	17
1930	18

आंकड़े फीफा वर्ल्ड कप में साल दर साल खेले गए मैचों के, संख्या में। | स्रोत : फीफा

जब भगवान श्रीकृष्ण ने राजा मयूरध्वज की दानवीरता परखने का निश्चय किया, तब एक ऐसी घटना घटी, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए।

दानवीरता की परीक्षा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, राजा मयूरध्वज धर्म और दानशीलता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। एक बार भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने राजा की दानवीरता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे ब्राह्मण और शिष्य का वेश धारण करके राजा के दरबार में पहुंचे।

राजा ने दोनों अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत किया व उनकी इच्छा पूछी। तब ब्राह्मण रूप में आए श्रीकृष्ण ने कहा कि एक सिंह उनके पुत्र को खाने के लिए बैठा है। सिंह ने यह शर्त रखी है कि यदि राजा मयूरध्वज अपने शरीर का आधा भाग काटकर उसे दे दें, तभी बालक का जीवन बच सकता है। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजा ने बिना किसी संकोच के दान देने का निश्चय कर लिया। जब राजा अपने शरीर का आधा भाग अर्पित करने लगे, तब उनकी एक आंख से आंसू निकला। ब्राह्मण ने इसका कारण पूछा। राजा ने उत्तर दिया कि उन्हें पीड़ा का दुख नहीं है, बल्कि इस बात का खेद है कि शरीर का दूसरा भाग दान देने के अवसर से वंचित रह जाएगा।

अंतर्यात्रा
संकलित

राजा की त्याग भावना देखकर श्रीकृष्ण व अर्जुन अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा की प्रशंसा की और उन्हें धर्म, करुणा तथा सर्वोच्च दानशीलता का आदर्श घोषित किया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 15 जून, 1962

मिग जेट की खरीद से ब्रिटेन व अमेरिका की नींद हराम

मिग जेट की खरीद से ब्रिटेन व अमेरिका की नींद हराम

रूस के मिग जेट विमान खरीदने से भारत को रोकने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका, दोनों परेशान हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच इस मसले पर वार्ता जारी है और वे प्रयास कर रहे हैं कि रूस भारत को सैन्य साजो-सामान न दे सके।

हर घर में हो रक्त मित्र

जरूरत सिर्फ रक्तदान शिविरों को बढ़ाने की नहीं, बल्कि ऐसी संस्कृति विकसित करने की है, जिसमें रक्तदान को सम्मानजनक नागरिक कर्तव्य माना जाए।

परीक्षित निर्भय | **मुद्दा**

जिस तरह हमें घर में सैनिक या शिक्षक होने पर गर्व होता है, उसी तरह हर घर में एक 'रक्त मित्र' का होना सामाजिक जिम्मेदारी का ही प्रतीक है। किसी सड़क दुर्घटना, जटिल प्रसव या गंभीर बीमारी के बाद अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों की पहली चिंता इलाज की नहीं, बल्कि रक्त की व्यवस्था बन जाती है। फोन की संपर्क सूची खंगाली जाती है, फोन किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर अपील की जाती है। इन परिस्थितियों में यदि परिवार के पास एक रक्त मित्र हो, तो संकट काफी हद तक कम हो सकता है। ऐसे में, सवाल यह है कि क्या हमारे समाज में हर घर के पास ऐसा कोई 'रक्त मित्र' है?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2024-25 में देश में 1.46 करोड़ यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इसमें 74.55 फीसदी हिस्सा स्वैच्छिक रक्तदान से आया है। भारत जैसे विशाल देश में हर दो सेकंड में किसी न किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता पड़ती है। गंभीर मामलों में रक्त जीवन-मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकता है। इसलिए, रक्त की उपलब्धता केवल स्वास्थ्य सेवाओं का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और सामुदायिक उत्तरदायित्व का भी प्रश्न है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, यदि किसी देश की कुल जनसंख्या का केवल एक फीसदी भी नियमित रक्तदान करे, तो देश की सभी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, पर भारत के लिए समस्या केवल रक्त संग्रहण की नहीं है। असली चुनौती यह भी है कि जरूरत के समय सही रक्त सही व्यक्ति तक पहुंच सके। देश में लगभग 4,541 लाइसेंस प्राप्त ब्लड सेंटर और ब्लड बैंक कार्यरत हैं, जिनमें सरकारी, गैर-सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर रक्त की उपलब्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन केंद्रों को केंद्रीय ई-रक्तकोष पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। कई गंभीर रोगों के उपचार तथा सड़क दुर्घटनाओं के मामलों ने रक्त की आवश्यकता को पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ा दिया है। ऐसे में, केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हो सकते। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी अनिवार्य है। कुछ लोग मानते हैं कि रक्तदान से कमजोरी आती है या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि डॉक्टर बार-बार स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वस्थ व्यक्ति नियमित अंतराल पर सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। जरूरत है कि रक्तदान को आपातकालीन प्रतिक्रिया के बजाय नियमित सामाजिक दायित्व के रूप में देखा जाए।

यहीं से रक्त मित्र की अवधारणा महत्वपूर्ण हो जाती है। रक्त मित्र वह व्यक्ति है, जो स्वयं रक्तदान के लिए तैयार हो, दूसरों को इसके लिए प्रेरित करे और आवश्यकता पड़ने पर रक्तदाताओं का नेटवर्क उपलब्ध करा सके। देश के विभिन्न हिस्सों में हजारों ऐसे लोग हैं, जिन्होंने रक्तदान को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बना लिया है। वे न केवल स्वयं रक्तदान करते हैं, बल्कि जरूरतमंदों को रक्तदाताओं से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। यही लोग समाज के वास्तविक रक्त मित्र हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऐसे कई परिवार हैं, जिन्होंने रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी बना लिया है। विद्यानगर कॉलोनी निवासी प्रदीप गुप्ता केवल अलीगढ़ ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक जाकर 50 से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं। वहीं श्यामपुर निवासी चौधरी अजय सिंह और उनका परिवार पूरे शहर में रक्तवीर के नाम से जाना जाता है। परिवार के सदस्य मिलकर अब तक 399 बार रक्तदान कर चुके हैं। वहीं, प्रयागराज के पुराना कटरा निवासी 40 वर्षीय अंशुल तिवारी 44 बार रक्तदान कर चुके हैं, तो गोरखपुर के दीनानाथ सिंह और सुनील मणि त्रिपाठी जैसे कई लोग नियमित रक्तदान करके समाज के लिए प्रेरणा बने हुए हैं।

आज आवश्यकता केवल रक्तदान शिविरों की संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि ऐसी सामाजिक संस्कृति विकसित करने की है, जिसमें रक्तदान को सामान्य और सम्मानजनक नागरिक कर्तव्य माना जाए। जिस प्रकार हर परिवार किसी डॉक्टर या अस्पताल का नंबर अपने पास रखता है, उसी प्रकार यदि हर घर एक रक्त मित्र से जुड़ा हो, तो आपात स्थिति में बहुमूल्य समय बचाया जा सकता है। जिस तरह हर घर में एक शिक्षक, एक सैनिक या एक समाजसेवी होने पर गर्व किया जाता है, उसी तरह हर घर में एक रक्त मित्र होना भी सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनना चाहिए। देश को ऐसे समाज की जरूरत है, जहां रक्त की आवश्यकता पड़ने पर कोई व्यक्ति अकेला न पड़े। यही संवेदनशील, जागरूक और जीवन के प्रति उत्तरदायी समाज की पहचान होगी।

अमर उजाला **Job Alert**

Real-time job alerts amarujala.com/jobs

एम्स, नई दिल्ली में निकली भर्ती

जूनियर इंजीनियर, ऑफिस असिस्टेंट व अन्य पद खाली

1484 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 30 जून, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 30 वर्ष
यहां आवेदन करें : aiimsexams.ac.in

यूपीएससी की अधिसूचना ■ 538 पद

एसोसिएट प्रोफेसर, साइंटिस्ट आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 03 जुलाई, 2026
पात्रताएं : बीई, बीटेक, एमएससी व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : upsconline.nic.in

आईआईटी, कानपुर में मौके ■ 80 पद

डिप्टी रजिस्ट्रार, जूनियर असिस्टेंट आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 03 जुलाई, 2026
पात्रताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : iitk.ac.in/recruitment

डीबीईओ में नौकरी के अवसर ■ 29 पद

प्रयोगशाला सहायक व अन्य पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 20 जून, 2026
पात्रताएं : बीएड, डीएलएड व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : kushinagar.nic.in

मंत्रिमंडल सचिवालय में मौके ■ 25 पद

सीनियर फिल्ड ऑफिसर के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि : 12 जुलाई, 2026
आयु-सीमा : अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : cabsec.gov.in

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ■ 24 पद

एएसआई के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 07 जुलाई, 2026
वेतनमान : रुपये 29,200 से लेकर रुपये 92,300 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : cisfrectt.cisf.gov.in

यहां भी हैं रोजगार के अवसर...

उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन : जनरल मैनेजर, मैनेजर-लीगल और फार्मासिस्ट के पद खाली।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 01 जुलाई, 2026
- upmscl.in

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद : कंसल्टेंट के पदों पर रिक्तियां।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 04 जुलाई, 2026
- icssr.org

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

रोशनी यहां है

इस बार
मेजर अभिलाषा बराक
क्यों
यूएन की ओर से सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया

अमेरिका की नौकरी छोड़ बनीं देश की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर

अभिलाषा बराक का पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनना और वर्तमान में लेबनान में दुनिया के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र में तैनात होना खासकर उन लड़कियों के लिए संदेश है, जो मानती हैं कि कुछ क्षेत्र उनके लिए कठिन या असंभव हैं।

अभिलाषा बराक की कहानी सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण है कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो, तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। बचपन से उनका सपना पायलट बनने का था। वह सेना के माहौल में पली-बढ़ीं, इसलिए देशसेवा और वर्दी के प्रति आकर्षण स्वाभाविक था। लेकिन किसी भी बड़े लक्ष्य की तरह उनके सामने भी चुनौतियां थीं। उन्होंने सपने को सिर्फ कल्पना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा, प्रशिक्षण और निरंतर मेहनत के जरिये उसे वास्तविकता में बदला। जब वह भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनीं, तो यह केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी। यह खासकर उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश था, जो मानती हैं कि कुछ क्षेत्र उनके लिए कठिन या असंभव हैं। उन्होंने दिखाया कि परंपरागत सीमाएं बदली जा सकती हैं और नए रास्ते बनाए जा सकते हैं। हाल ही में, उन्हें वर्ष 2025 के लिए *संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार* से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान सिर्फ उड़ान कौशल के लिए नहीं था, बल्कि संघर्षपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं और लड़कियों के सशक्तीकरण और उनकी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए था। इसका मतलब है कि एक सच्चा सैनिक केवल अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है।

भाई की पासिंग आउट परेड देख पक्का किया इरादा

अभिलाषा बराक हरियाणा के रोहतक की रहने वाली हैं और एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की बेटी हैं। बचपन से ही सैन्य वातावरण में पली-बढ़ीं अभिलाषा के मन में देशसेवा के संस्कार गहराई से विकसित हुए। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा द लॉरेंस स्कूल, सनावर से प्राप्त की और वर्ष 2016 में दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अमेरिका में एक उच्च वेतन वाली नौकरी मिली, लेकिन लगभग एक वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत लौट आईं। अभिलाषा के भाई, अविनाश बराक भी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। उनके भाई वर्ष 2013 में इंडियन मिलिटरी एकेडमी की पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने। अभिलाषा ने अपने भाई की वह गौरवपूर्ण परेड देखी, और उसी क्षण उनके भीतर भी वर्दी पहनकर देशसेवा करने का संकल्प और मजबूत हो गया।

कभी ज्वाइन नहीं कर सकीं एयरफोर्स

अभिलाषा इंडियन एयर फोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहती थीं। उन्होंने इसके लिए परीक्षाएं भी पास कीं, लेकिन कथित तौर पर निर्धारित हाइट मानक पूरा न होने के कारण उनका चयन नहीं हो पाया। कहा जाता है कि फाइटर पायलट बनने के लिए तय शारीरिक मानक होते हैं, और वह उस सीमा से बहुत कम अंतर से बाहर हो गईं। इसके बावजूद उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और लगातार मेहनत जारी रखी। जूडो, हॉर्स राइडिंग और अन्य गतिविधियों में भी वे हमेशा आगे रहीं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उनका चयन पूरा नहीं हो पाया। कभी शारीरिक मानकों की वजह से, तो कभी सीमित अवसरों के कारण। कई बार असफलताओं का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपना रास्ता बदला। आगे चलकर उन्होंने भारतीय सेना में चयन प्राप्त किया।

आर्मी एविएशन कॉर्प्स को चुना

अभिलाषा बराक वर्ष 2018 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के माध्यम से भारतीय सेना में शामिल हुईं। उन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स को चुना, जहां उस समय महिलाओं की भूमिका सीमित थी। 2019 में उन्होंने आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स की टुकड़ी का नेतृत्व किया, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेजिमेंट को 25 वर्ष पूरे होने पर "प्रेसिडेंट्स कलर्स" प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2022 में महाराष्ट्र के नाशिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में अपना प्रशिक्षण पूरा किया और भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर पायलट बनीं।

लेबनान में निभा रहीं अहम भूमिका

अभिलाषा बराक इस समय लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के तहत भारतीय बटालियन के साथ एंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल प्वाइंट के रूप में तैनात हैं। यह मिशन इस्राइल-लेबनान सीमा क्षेत्र में संचालित होता है और दुनिया के सबसे संवेदनशील शांति मिशनों में से एक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, मेजर बराक स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास स्थापित करने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। अभिलाषा बराक लगभग 650 भारतीय शांति सैनिकों में शामिल हैं, जिनमें 13 महिलाएं हैं।

युवाओं को सीख

- मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
- सपना बड़ा हो तो शुरुआत छोटी होने से फर्क नहीं पड़ता।
- रुकावटें लक्ष्य बदलने का कारण नहीं, बल्कि नया रास्ता खोजने का अवसर होती हैं।

आज का दिन

15 जून, 1896

जापान के सैनरिकु तट पर 8.5 तीव्रता के भूकंप के बाद भीषण सुनामी आई। लगभग 38 मीटर ऊंची लहरों से करीब 22,000 लोगों की जान चली गई थी।

- 1846 : अमेरिका और ब्रिटेन ने ओरेगन संधि पर हस्ताक्षर किए।
- 1864 : अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान पीटर्सबर्ग की घेराबंदी शुरू हुई थी।
- 1929 : प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा गायिका सुरैया का जन्म हुआ था।
- 1996 : अमेरिकी गायिका एला फिट्जगेराल्ड का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : द्वितीय ज्येष्ठ अमावस्या/द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा। कल : ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले। राहुकाल : दिन में 15.00 से 16.30 तक।

- सूर्योदय : 05.27
- सूर्यास्त : 19.16

(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 26 ज्येष्ठ मास शक 1948, आषाढ़ मास 02 प्रविष्टे, 29 जिल्हेज हिजरी 1447, द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया 24.52 तक उपरांत तृतीया, आर्द्रा नक्षत्र 16.11 तक उपरांत पुनर्वसु नक्षत्र, वृद्धि योग 24.34 तक उपरांत ध्रुव योग, बालव करण 14.41 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा मिथुन राशि में दिन-रात।

राशिफल

amarujala.com/astrology ■ पं. विनोद त्यागी

मेष : मानसिक तनाव एवं कानूनी मामले में उलझने से बचें। स्वश्रम से इच्छापूर्ति में सफल रहेंगे।

वृष : भविष्य के प्रति आशान्वित रहेंगे। किसी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में धैर्य बनाए रखें।

मिथुन : धैर्य बनाए रखें। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। नौकरी में नई परेशानी आ सकती है।

कर्क : उतावलेपन पर नियंत्रण रखें। पैतृक संपत्ति संबंधी मामला उलझ सकता है। व्यवसाय में सावधानी बरतें।

सिंह : समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश हो सकता है। नौकरी में तालमेल बना रहेगा।

कन्या : दिनमान सामान्य रहेगा। नौकरी में व्यवहार कुशलता बनाए रखें। कार्य विशेष में अवरोध आएंगे।

तुला : नए क्षेत्रों में जान-पहचान बढ़ेगी। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

वृश्चिक : नई योजना में सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में सावधानी बरतें। व्यवसाय में सामान्य लाभ होगा।

धनु : आरोग्य सुख मिलेगा। राजनीतिक संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।

मकर : मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी। नौकरी में धैर्य बनाए रखें। व्यवसाय में उत्तम लाभ होगा।

कुंभ : मनोकामना पूर्ति का अवसर मिलेगा। चली आ रही समस्या से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा।

मीन : सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में नई उपलब्धि संभव है। आर्थिक स्थिति से संतुष्ट रहेंगे।

सुडोकू

9	5							
					6		4	
3		2	8			1		
			6	8	9			1
4		8		2		5		9
7			1	4	5			
		1			7	3		8
	7		3					
							2	7

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

9	5	4	2	3	1	7	8	6
1	8	7	5	9	6	2	4	3
3	6	2	8	7	4	1	9	5
5	2	3	6	8	9	4	7	1
4	1	8	7	2	3	5	6	9
7	9	6	1	4	5	8	3	2
2	4	1	9	6	7	3	5	8
8	7	9	3	5	2	6	1	4
6	3	5	4	1	8	9	2	7

ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी भी शक के घेरे में मिलीभगत के सबूत मिलने पर कम होंगे अधिकार

राममंदिर दान राशि में गबन का मामला

एसआईटी को 7 दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने का दायित्व सौंपा गया

ट्रस्टियों से पूछताछ कर सकती है एसआईटी

संवाद न्यूज एजेंसी

अयोध्या। राम मंदिर दान राशि गबन प्रकरण की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसके दायरे के विस्तार की चर्चा भी तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, मामले में केवल कर्मचारियों या बाहरी लोगों की भूमिका ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट से जुड़े कुछ प्रभावशाली पदाधिकारियों और ट्रस्टियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।

बताया जा रहा है कि जिन पांच संदिग्धों के नाम अब तक सामने आए हैं, उनमें से कुछ का संबंध ट्रस्ट के प्रभावशाली लोगों से होने की बात भी सामने आ रही है। इसी वजह से गठित एसआईटी केवल धन के लेन-देन और तकनीकी पहलुओं की ही जांच नहीं करेगी, बल्कि यह भी पता लगाएगी कि किसी स्तर पर संरक्षण, लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई।

एसआईटी को सात दिन में प्रारंभिक और 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट देने का दायित्व सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी यह भी जांच करेगी कि दान राशि के कथित गबन की प्रक्रिया कितने समय से चल रही थी, इसमें किन-किन लोगों की भूमिका थी और क्या किसी जिम्मेदार पदाधिकारी की जानकारी या लापरवाही के कारण यह संभव हो पाया। यदि जांच में किसी ट्रस्टी या पदाधिकारी की संलिप्तता अथवा गंभीर प्रशासनिक चूक के प्रमाण मिलते हैं, तो उनके अधिकार सीमित किए जाने या अन्य कार्रवाई की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी और भूमिका स्पष्ट हो सकेगी

तीन वरिष्ठ अधिकारियों वाली एसआईटी का किया गया है गठन

यह भी पता लगाया जाएगा कि किसी स्तर पर संरक्षण, लापरवाही या मिलीभगत तो नहीं हुई

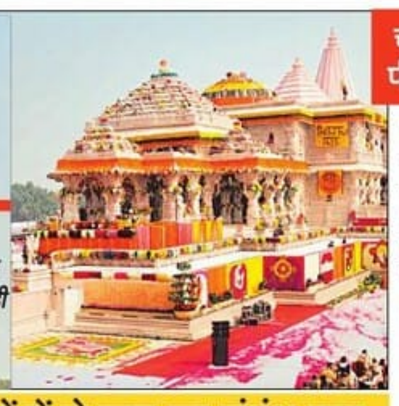

पांच संदिग्धों में से कुछ का संबंध ट्रस्ट के प्रभावशाली लोगों से होने की आशंका

चढ़ावे में घपले की जांच के लिए पीएमओ से अयोध्या आए अफसर

मामले के तूल पकड़ने के बाद केंद्र भी सक्रिय हो गया है। रविवार को पीएमओ की तरफ एक बड़े अफसर के मंदिर पहुंचने की चर्चा है। अफसर अपने स्तर से जांच पड़ताल के बाद जानकारी जुटाकर पीएमओ को देंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

- **चंपत राय बीमार, अनिल मिश्रा चिकित्सकीय जांच के लिए केरल गए :** एसआईटी के अयोध्या पहुंचने की तैयारी के बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय अस्वस्थ बताए जा रहे हैं। ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य अनिल मिश्रा चिकित्सकीय परामर्श के लिए केरल गए हैं।

संतों की जांच करना सनातन का अपमान

- **एसआईटी गठन पर अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना**

आगरा। मामले की योगी सरकार के एसआईटी जांच के आदेश पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के बाद अब अफसर साधु-संतों की जांच करेंगे। यह सनातन का अपमान है। वहां कैमरे और लाइट बंद कर दो। जो लेकर गया है, वह प्रभु श्रीराम के सामने अपने आप चढ़ावा वापस कर जाएगा। भगवान भी माफ कर देंगे। संवाद

नृपेंद्र मिश्र ने एसआईटी पर जताया भरोसा

- **निर्माण समिति के अध्यक्ष बोले-24 घंटे से कम समय में जांच समिति गठन सराहनीय**

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने जांच के लिए गठित एसआईटी पर भरोसा जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे से भी कम समय में जांच समिति गठित कर दी। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने समिति गठन के निर्णय की प्रशंसा करते हुए कहा कि एसआईटी में अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। मिश्र ने कहा कि राम मंदिर की फसाड लाइटिंग का कार्य एक माह की देरी से चल रहा है, लेकिन इसे 15 अगस्त तक हैंडओवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पूरी निष्पक्षता से करेगी जांच

वाराणसी। शासन स्तर से गठित एसआईटी पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। जो सहयोग मांगा गया है उसे दिया जाएगा। यह कहना है उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण का। वह रविवार को पुलिस लाइन में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। संवाद

कुल जरूरत के 51% से अधिक उर्वरक भंडार से देश मजबूत स्थिति में

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 के लिए कुल 383.9 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की जरूरत का अनुमान लगाया है। इसके मुकाबले सरकार के पास लगभग 195.79 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक मौजूद है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के मुताबिक, आमतौर पर सिर्फ 33 फीसदी बफर स्टॉक रहता था, लेकिन आज भारत 51% से अधिक के अग्रिम भंडार के साथ मजबूत स्थिति में है ।

विभाग का कहना है कि वैश्विक संकट के बाद भी देश का घरेलू उत्पादन 118.15 लाख मीट्रिक टन रहा। इसमें आयात को भी जोड़ देने पर संकट के बाद से अब तक देश में खाद की कुल उपलब्धता में लगभग 153.79 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई है। यह तब है जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों और हमलों से पूरी दुनिया की आपूर्ति शृंखला चरमरा गई, लेकिन सरकार ने शुरू से ही होर्मुज जलडमरूमध्य संकट के वैकल्पिक रास्ते तलाश कर निर्बाध आपूर्ति पक्की की। ब्यूरो

अशांति फैलाने वालों को शांत करना जानती है सरकार

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले- हम तुष्टिकरण की नहीं, संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं

अमर उजाला ब्यूरो

आगरा। शमसाबाद में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद किसान, जवान और महिला स्वाभिमान रैली में विपक्ष, आतंकवाद और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि 2014 से पहले एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाती थीं। हमने सेना को खुली छूट दी।

सिंधु जल समझौते को निलंबित किया जा चुका है। हरकतों से बाज नहीं आया तो पाकिस्तान को दाना-पानी के लिए भी मोहताज बना दिया जाएगा। हमारी सरकार अशांति और आतंकवाद फैलाने वालों को हमेशा के लिए शांत करना जानती है। हम तुष्टिकरण की नहीं, संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। रैली में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु नदी समझौते को निरस्त कर दिया है, जिससे अब हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान नहीं जा सकेगा। कहा कि देश को नक्सलवाद के खूनी तांडव से मुक्त कराने का श्रेय भी वर्तमान सरकार को जाता है।

रैली के दौरान राजनाथ सिंह। संवाद

महाराणा प्रताप के आदर्श पर चल रही मोदी सरकार

महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप हिंदुस्तान में अद्वितीय संघर्ष के प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर से समझौता कर लेते लेकिन उन्होंने आत्मसम्मान और देश के स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यही कारण है कि आज भी देश में उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती हैं। उनके ही आदर्शों पर चलते हुए मोदी सरकार भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के विचार के साथ काम कर रही है।

भारत ने 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए बनाया सुलभ : मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सस्ता और आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए व्यापक काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ऐसे सभी प्रयासों को आगे भी जारी रखेगी।

पीएम बोले- स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए जारी रहेंगे प्रयास

सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इस बात पर गर्व है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत के लिए जाना जाता है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। उन्होंने कहा, पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना जैसी योजनाओं ने दवाओं, स्टेंट व घुटने के प्रत्यारोपण को सस्ता बनाया है। इससे लाखों लोगों को राहत मिली है और इलाज का खर्च कम हुआ है। देश में मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से चिकित्सा शिक्षा पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई है। एजेंसी

जवानों के पार्थिव शरीर गृहराज्य भेजे

जोरहाट। असम के जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए एएन-32 परिवहन विमान हादसे में जान गंवाने वाले पांचों जांबाज जवानों के पार्थिव शरीरों को रविवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक स्थानों के लिए रवाना कर दिया गया है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक, सभी बलिदानों का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनके गृहराज्यों में किया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने पांचों कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। एजेंसी

युवा ऐसे काम सीखें, जो एआई न कर सके : सीईए

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा- सॉफ्टवेयर नौकरियों और एमबीए का दौर खत्म

नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और एजेंटिक एआई के दौर में दुनिया पूरी तरह बदल गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन का कहना है कि तकनीकी क्रांति के इस दौर में कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर नौकरियों और एमबीए डिग्री का महत्व खत्म हो रहा है। युवाओं को अब व्यावसायिक (ट्रेड) कौशल और इन्सानों पर आधारित ऐसे काम सीखने की जरूरत है, एआई जिनकी आसानी से जगह नहीं ले सकता।

उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण से भारत को भले ही सेवा क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है, लेकिन दुनिया अब बंट रही है। अपने-अपने दायरे में सिमट रही है। ऐसे में भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत करना जरूरी हो गया है। काम के बदलते स्वरूप पर नागेश्वरन ने कहा, तकनीकी तरक्की आपकी रोजगार क्षमता को खत्म नहीं कर सकती। बस जरूरत है भारतीयों को नजरिया बदलने की, जैसे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, जापान, कोरिया या चीन जैसे सफल देशों ने किया। वे व्यावसायिक कौशल को महत्व देते हैं। वेल्डर, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन या बढ़ई जैसे कारीगरों को बहुत सम्मान देते हैं, जबकि भारत में उन्हें एक तरह से अस्वीकार्य और असम्मानजनक तरीके से देखा जाता है। श्रम आधारित विनिर्माण के साथ सेवा क्षेत्र जैसे देखभाल, कुलीनरी आर्ट्स, खाना बनाना, हॉस्पिटल स्टाफ और स्पोर्ट्स एजुकेशन में अब भी काफी गुंजाइश है। खासकर बुजुर्गों की देखभाल और जरूरतों वाले बच्चों की काउंसलिंग जैसे कार्यों में। इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ पूरी दुनिया को काबिल और कुशल लोगों की जरूरत है। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर एआई का असर नहीं पड़ेगा। एजेंसी

श्रम आधारित विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में कुशल लोगों की जरूरत

एआई को लेकर डर ज्यादा

सीईए ने कहा, एआई का वैश्विक श्रम बाजार पर पहले हुए तकनीकी बदलावों की तुलना में कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक असर पड़ने का अनुमान है, क्योंकि यह एक ही समय में सोचने-समझने और कौशल आधारित दोनों तरह की नौकरियों को प्रभावित करता है। हालांकि, अभी एआई से जुड़े खतरे को लेकर डर बहुत ज्यादा है और जानकारी बहुत कम। इसके तर्क में उन्होंने कहा, इतिहास बताता है कि तकनीकी क्रांतियों से अक्सर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ने के बजाय नौकरियों के स्वरूप में बदलाव आता है।

मेमोरी चिप निर्माण में बढ़ेगा निवेश : वैष्णव

कहा- एआई और डाटा सेंटर की बढ़ती मांग से बढ़ा महत्व, आ सकती हैं नई कंपनियां

नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि भारत में मेमोरी चिप निर्माण के क्षेत्र में नए निवेश आने की संभावना है। पहले से मौजूद कंपनियां भी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती हैं ताकि मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर को कम किया जा सके।

समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में वैष्णव ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डाटा सेंटर और उन्नत कंप्यूटिंग तकनीकों की तेजी से बढ़ती जरूरत के कारण दुनियाभर में हाई बैंडविड्थ मेमोरी (एचबीएम) चिप्स की भारी मांग है। इसी वजह से कई तरह के मेमोरी चिप्स की वैश्विक कमी देखी जा रही है। आईटी मंत्री ने कहा कि मेमोरी चिप्स व डाटा स्टोरेज उत्पादों की मांग बढ़ने से वैश्विक आपूर्ति पर दबाव पड़ा है, जिससे कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इसका असर स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पादन लागत पर भी पड़ा है। भारत में डाटा सेंटर निवेश जल्द ही 200 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है, जिसके लिए अरबों गीगाबाइट स्टोरेज क्षमता की आवश्यकता होगी। एजेंसी

कोलकाता : गंगा के नीचे बनेगी देश की पहली मालवाहक सुरंग

कोलकाता। हुगली नदी के नीचे सफल मेट्रो रेल परिचालन के बाद अब पश्चिम बंगाल एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर अग्रसर है। गंगा के तल से होकर देश की पहली ऐसी मालवाहक सड़क सुरंग बनाने की योजना तैयार की गई है, जो विशेष रूप से ट्रकों और कंटेनर वाहनों के लिए समर्पित होगी। 11 हजार करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह को सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ना है, जिससे माल परिवहन की गति बढ़ेगी और परिवहन लागत में भारी कमी आएगी। ब्यूरो

भास्कर बिजनेस गाइड

नई दिल्ली, सोमवार 15 जून, 2026

भास्कर एक्सप्लेनर

स्पेसएक्स, ओपनएआई, एंथ्रोपिक पब्लिक हो रहीं... मस्क का इश्यू फेसबुक के 17 आईपीओ की बराबरी कर रहा

ऐतिहासिक... तीन कंपनियां, 20 अरबपति, 16 हजार करोड़पति

भास्कर न्यूज | मुंबई

इस महीने तीन कंपनियां एक साथ जिस पैमाने पर पैसा बनाने (वेल्थ क्रिएशन) जा रही हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं है। इलॉन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेसएक्स पहले ही 1.77 ट्रिलियन डॉलर (₹168 लाख करोड़) के वैल्युएशन पर शेयर बाजार में उतर चुकी है। दुनिया की दो सबसे ताकतवर एआई कंपनियां ओपनएआई और एंथ्रोपिक भी जल्द आईपीओ के जरिए पब्लिक होने वाली हैं। तीनों का मिला-जुला मार्केट कैप करीब 4 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग ₹380 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है।

प्राइवेट मार्केट रिसर्च फर्म सैक्रा के विश्लेषण के मुताबिक, इन तीन मेगा-आईपीओ से 20 से अधिक नए डॉलर अरबपति (कम से कम ₹9,500 करोड़ की संपत्ति) बनेंगे। साथ ही 16,000 से अधिक लोग डॉलर करोड़पति (₹95 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति) भी बनेंगे। सैक्रा के रिसर्च हेड मार्सेलो बाल्वे का कहना है, 'इस स्तर का वेल्थ क्रिएशन इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया।' इसके चलते दुनियाभर के निवेशकों की नजर इन पर है। भारत में भी इनको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है।

इनकी संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी... ?

आईपीओ के दम पर दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर' का उदय...

इलॉन मस्क: पहले से दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। स्पेसएक्स की लिस्टिंग के बाद दुनिया के पहले 'ट्रिलियनेयर' बन गए हैं यानी उनकी कुल संपत्ति 104 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है।

ग्रेग ब्रॉकमैन: ओपनएआई के सह-संस्थापक और प्रेसिडेंट ग्रेग ब्रॉकमैन ने हाल ही में एक अदालत को बताया था कि कंपनी में कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 2.85 लाख करोड़ रुपए की हो गई है।

डारियो अमोदेई: एंथ्रोपिक के सह-संस्थापक और सीईओ डारियो अमोदेई की संपत्ति पहले ही ₹76,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। आईपीओ के बाद बढ़ सकती है। वे 536वें सबसे अमीर हैं।

ग्वेन शॉटवेल: स्पेसएक्स की सीओओ ग्वेन शॉटवेल की कुल नेटवर्थ ₹32 हजार करोड़ आंकी गई है। स्पेसएक्स की 11वीं एम्प्लॉई शॉटवेल के पास कंपनी में 1% से भी कम हिस्सेदारी है।

भारतीय भी मालामाल: नई दिल्ली के फैमिली ऑफिस को स्पेसएक्स से 100 गुना रिटर्न

भारत में भी एआई-स्पेस बूम का असर दिख रहा है। नई दिल्ली के एक फैमिली ऑफिस ने 2017 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन (स्पेसएक्स) में निवेश किया था। तब कंपनी करीब ₹2 लाख करोड़ के वैल्युएशन पर थी। ईसोप सेकंडरी मार्केट के जरिए डिस्काउंट के साथ ₹1.7 लाख करोड़ वैल्युएशन पर यह निवेश हुआ था। इस माह ₹199.7 लाख करोड़ वैल्युएशन से इस निवेश पर 100 गुना तक रिटर्न मिला।

2017 से अब तक बड़ी टेक कंपनियों के रिटर्न, एनवीडिया का 45 गुना, टेस्ला का 28 गुना

कंपनी	रिटर्न
स्पेसएक्स	100 गुना
एनवीडिया	45 गुना
टेस्ला	28 गुना
अमेजन	5 गुना
माइक्रोसॉफ्ट	5 गुना

नोट: रिटर्न 12 जून तक के वैल्युएशंस के आधार पर

स्पेसएक्स ढाई दशक निजी बनी रही कंपनी

स्पेसएक्स 24 साल बाद पब्लिक हुई है। तुलना के लिए जब फेसबुक 2012 में 104 अरब डॉलर (करीब ₹10 लाख करोड़) के वैल्युएशन पर लिस्ट हुई थी, तब उसकी तत्कालीन सीओओ शेरिल सैंडबर्ग की 0.07% हिस्सेदारी ₹694 करोड़ की थी। वही 0.07% हिस्सेदारी स्पेसएक्स में आज ₹11,413 करोड़ के बराबर होती। यही वजह है कि सैक्रा इसे 'फेसबुक का 17 आईपीओ' कह रही है।

भारतीय निवेशक कैसे करें एंट्री?

अमेरिकी आईपीओ में आवंटन मुख्यत: संस्थागत निवेशकों और बैंकों को मिलता है। एप्रिशिएट के सीईओ शुभो मौलिक कहते हैं, 'कोई रिटेल लॉटरी नहीं, कोई गारंटीड आवंटन नहीं, कोई ब्रोकरेज रूट नहीं है। भारतीय निवेशक लिस्टिंग के बाद ही इनमें पैसा लगा सकते हैं, जब प्राइस डिस्कवरी हो चुकी होती है।' निवेश के तीन रास्ते हो सकते हैं...

1. एलआरएस: आरबीआई की इस सुविधा के तहत भारतीय सालाना 2.5 लाख डॉलर (₹2.4 करोड़) तक विदेश में निवेश कर सकते हैं। कई फिनटेक प्लेटफॉर्म और ब्रोकरेज गिफ्टी सिटी व एलआरएस के जरिए अमेरिकी शेयरों में निवेश की सुविधा देते हैं।

2. ईटीएफ: क्रेनशेयर्स, एजिक्स ईटीएफ, एआरके वेंचर फंड जैसी संस्थाओं में एंथ्रॉपिक, ओपनएआई और स्पेसएक्स की हिस्सेदारी है। इसके अलावा एसएसएसीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करने वाले ईटीएफ भी एक विकल्प हैं।

3. पोस्ट लिस्टिंग: मौलिक जैसे विशेषज्ञों की राय है कि लिस्टिंग के बाद पहले दिन की तेजी पकड़ने की कोशिश न करें। कुछ तिमाहियों के बाद, जब वैल्युएशन कम हो जाए, तब लंबी अवधि के नजरिए से ऐसे शेयर खरीदने में समझदारी होगी।

कितना निवेश करें और किसके लिए सही?

ओट्टो मनी के सीईओ अपूर्व गुप्ता की सलाह है कि एआई का मौका सिर्फ ओपनएआई और एंथ्रॉपिक तक सीमित नहीं है। इसमें हार्डवेयर (एनवीडिया, माइक्रॉन, टीएसएमसी), डेटा सेंटर इंफ्रा, एप्लिकेशन लेयर भी शामिल हैं। ऐसे में निवेशकों का पोर्टफोलियो का दायरा बढ़ाने की जरूरत है।

भारतीय निवेशकों का पोर्टफोलियो ऐसा हो

निवेशक प्रोफाइल	अमेरिकी टेक/एआई	वैकल्पिक तरीके
आक्रामक	15-20%	ETF+PL*
मध्यम	8-12%	ईटीएफ/ AI फंड
रक्षात्मक	5% तक	केवल ईटीएफ

PL- पोस्ट लिस्टिंग स्रोत: एप्रेसिएट

सिर्फ लिस्टिंग गेन के नजरिये से निवेश कराना जोखिम भरा

वैसे लोग स्पेसएक्स, ओपनएआई और एंथ्रोपिक के शेयरों में पैसा लगा सकते हैं जो 5-7 साल का नजरिया रखते हैं, जोखिम सहने की क्षमता ऊंची है और पोर्टफोलियो पहले से अच्छी तरह डायवर्सिफाइड है। जो निवेशक सिर्फ 'लिस्टिंग गेन' के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए यह सही जगह नहीं है।

यदि निवेश की सोच रहे तो ये सावधानियां जरूरी...

- ✔ स्पेसएक्स, ओपनएआई और एंथ्रोपिक, तीनों कंपनियां आक्रामक वैल्युएशन पर लिस्ट हो रही हैं। कुछ तिमाहियों के बाद बाजार की वास्तविकता सामने आ सकती है।
- ✔ स्पेसएक्स में X (ट्विटर) का मर्जर और टेस्ला को भी इसमें शामिल करने की संभावना ने इसे 'प्योर-प्ले स्पेस कंपनी' की परिभाषा से अलग कर दिया है।
- ✔ निवेशकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि अभी 84 फीसदी से अधिक वोटिंग राइट्स सिर्फ मस्क के पास हैं।

इनपुट: न्यूयॉर्क टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, फॉर्च्यून

भास्कर Q&A

लंबी अवधि के लिए आईटी, ऑटो, बैंक में भी मौके तलाशें

भास्कर एक्सपर्ट

जिगर एस पटेल
सीनियर मैनेजर, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स

Q ओएनजीसी और सुजलॉन एनर्जी के शेयर क्या लंबे समय के लिए होल्ड करूं? -पूरन
ONGC को होल्ड रखें। सुजलॉन के लिए डेली क्लोजिंग बेसिस पर ₹50 का स्टॉपलॉस लगाएं।

Q पीसी ज्वेलर्स, साकुमा एक्सपोर्ट्स, HDFC, ICICI बैंक पर सलाह दें? -काशी
ICICI, HDFC होल्ड करें। PC ज्वेलर में ₹7 का स्टॉपलॉस रखें। साकुमा के फंडामेंटल्स जांचें।

Q विप्रो (₹240), स्टार हेल्थ (₹595), ITC (₹375), क्रॉम्पटन (₹380) के शेयर घाटे में हैं, क्या करूं?
मौजूदा भाव पर विप्रो जोड़ें। स्टार हेल्थ, आईटीसी होल्ड रखें।

Q दो साल पहले IRFC ₹175 पर लिया था। क्या करना चाहिए? -प्रवेश देवांगन
मौजूदा भाव पर और खरीदारी करें। डेली क्लोजिंग बेसिस पर ₹80 का स्टॉपलॉस मेंटेन करें।

Q एमआरएफ किस भाव पर खरीदने की सलाह है? -राजा
खरीदारी कर सकते हैं, पर ₹1.2 लाख का स्टॉपलॉस मेंटेन करें।

Q मेरे पास एचएफसीएल के 200 शेयर हैं, जिन्हें ₹116 पर खरीदा था। बेचूं या होल्ड रखूं? -मुकेश कुमार सोलंकी
₹160 का ट्रेलिंग स्टॉपलॉस लगाएं और इस शेयर में बने रहें।

Q पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर के कुछ डिफेंसिव शेयर? -विनय
एचएएल, बीईएल और बीडीएल पर भरोसा कर सकते हैं। निजी सेक्टर में पारस डिफेंस बेहतर।

Q विप्रो का शेयर ₹181 पर है। इसे खरीदना ठीक है या गिरावट आ सकती है? -हर्ष
मौजूदा भाव पर खरीदारी करें। 2 साल के लिए होल्ड करें।

Q लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे शेयर बताएं, जिन्हें हर गिरावट पर खरीद सकूं? -रवि
आप फ्रंटलाइन आईटी कंपनियों, प्राइवेट सेक्टर के टॉप बैंकों के मजबूत शेयर चुन सकते हैं।

Q बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एनएसडीएल के शेयरों में मुझे 45-50% का नुकसान हो रहा है। इनको लेकर क्या रणनीति अपनाएं? -निकुल
मौजूदा भाव पर और शेयर जोड़ें और 2 साल के लिए होल्ड करें।

Q पेटीएम के शेयर भाव में 4 साल से सुधार नहीं दिख रहा है। क्या करूं? -उल्हास
डेली क्लोजिंग बेसिस पर 1,020 रुपए का सख्त स्टॉपलॉस लगाएं। इसके ट्रिगर होने पर निकल जाना ही बेहतर होगा।

Q मेरे पास हैवेल्स इंडिया के 300 शेयर (₹1,327) और एचडीएफसी के 350 शेयर (₹850) हैं। एवरेज करना सही होगा? -दीपक सिंह धाकड
मौजूदा भाव पर और शेयर खरीदकर एवरेज कर सकते हैं। इन्हें 1 साल के लिए होल्ड करें।

यदि आपके मन में शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई सवाल हों, तो यह क्यूआर कोड स्कैन करके हमारे पास भेजें। एक्सपर्ट इनके जवाब देंगे।

प्राइमरी मार्केट

निफ्टी में रिकवरी, बैंक निफ्टी में उछाल ने बढ़ाया निवेशकों का भरोसा

ब्रेकआउट से सेंसेक्स-निफ्टी जोश में

सुदीप शाह
वाइस प्रेसिडेंट, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च हेड, एसबीआई सिक्युरिटीज

पिछले हफ्ते निफ्टी में काफी उतार-चढ़ाव रहा। पहले चार दिन बाजार 355 अंकों के दायरे में ऊपर-नीचे होता रहा। पर निफ्टी को हर बार 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर के पास खरीदारी का समर्थन मिला। यानी जब भी बाजार इस स्तर के करीब आया, निवेशकों ने खरीदारी की। यह स्तर 22,182 से 24,602 की पिछली तेजी का अहम जोन है। इस जोन को हफ्ते में 3 बार परखा और हर बार बाजार चढ़ा। यानी निचले स्तरों पर मजबूत खरीदारी मौजूद है। शुक्रवार को बाजार का मिजाज अचानक बदला। पश्चिम एशिया से सकारात्मक खबरें आईं और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई। इससे निफ्टी ने तेजी दिखाई। अगले कुछ सत्र यह तय करेंगे कि यह केवल एक उछाल है या असली तेजी की शुरुआत।

तकनीकी चार्ट पर बाजार में मजबूती के पांच बड़े संकेत

संकेत	स्थिति
निफ्टी 20-दिन के औसत से ऊपर	मई 2026 के बाद पहली बार
RSI 50 पार + 9 दिवसीय औसत पार	खरीदारी की ताकत बढ़ी
बैंक निफ्टी आरएसआई 60 पार	फरवरी 26 के बाद पहली बार
एफआईआई लॉन्ग-शॉर्ट रेशियो	7.5% से 10% (बिकवाली घटी)
पीसीआर बुलिश डायवर्जेंस	भाव नीचे, पीसीआर ऊपर(ट्रेंड पलटा)

जब पीसीआर और एफआईआई डेटा एक साथ सकारात्मक हों, तो तेजी की नींव मजबूत होती है, भले ही कीमतें अभी नीचे हों।

निफ्टी... खरीदारी तेज होने के ठोस संकेत दिख रहे हैं
बीते हफ्ते निफ्टी 1.1% चढ़ा। मई 2026 के बाद पहली बार 20 दिनों के औसत से ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा आरएसआई 50 के ऊपर आ गया है और 9 दिनों के औसत से भी ऊपर निकल गया है। स्टोकास्टिक ऑसिलेटर ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है। खरीदारी के संकेतक तेज हो रहे हैं।
अगला लक्ष्य: 23,800-24,000
सपोर्ट जोन: 23,300-23,350

सेंसेक्स... फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, तेजी का संकेत
सेंसेक्स ने शुक्रवार को फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट किया, यानी सिकुड़ती रेंज से ऊपर निकला। करीब 2% की साप्ताहिक बढ़त के साथ यह 20-दिवसीय औसत से ऊपर आ गया। आरएसआई भी गिरती ट्रेंडलाइन तोड़ चुका है। इसका मतलब है कि खरीदारी की रफ्तार बढ़ रही है।
अगला लक्ष्य: 76,500-77,200
सपोर्ट जोन: 74,500-74,600

बैंक निफ्टी... फिलहाल पूरे मार्केट को थाम रखा है
इस हफ्ते बैंकिंग सेक्टर सबसे आगे रहा और उसने मुख्य सूचकांकों को थामे रखा। बैंक निफ्टी ने 'सिमेट्रिकल ट्रायएंगल' से ब्रेकआउट किया, 20 व 50 दिन के औसत से ऊपर है और आरएसआई फरवरी 2026 के बाद पहली बार 60 पार। बड़े निवेशकों का भरोसा बैंकिंग में लौट रहा है।
अगला लक्ष्य: 57,500-58,300
सपोर्ट जोन: 56,000-56,200

पीसीआर, एफआईआई डेटा क्या कह रहा?... 8 जून को निफ्टी 23,070 के निचले स्तर तक गया, फिर भी पीसीआर बढ़कर 0.84 पर टिका। यह तेजी का संकेत। एफआईआई का लॉन्ग-शॉर्ट रेशियो 7.5% से 10% पहुंचा। यानी ये भरोसा दिखा रहे हैं।

प्राइमरी मार्केट

पांच एसएमई आईपीओ जुटाएंगे ₹253 करोड़

भास्कर न्यूज | मुंबई

इस हफ्ते मेनबोर्ड पर कोई आईपीओ नहीं आ रहा है। लेकिन एसएमई सेगमेंट में पांच कंपनियां बाजार से 252.69 करोड़ रुपए जुटाने जा रही हैं। इनमें सबसे बड़ा इश्यू क्ले क्राफ्ट इंडिया का है। इसका आईपीओ से 110.11 करोड़ जुटाने का लक्ष्य है। लीपफ्रॉग इंजीनियरिंग सर्विसेज 88.51 करोड़ जुटाएगी। लियोटेक इंडस्ट्रीज 36.02 करोड़ और दीक्षा पॉलिमर्स 17.9 करोड़ जुटाएगी। ये आईपीओ 17 जून को खुलकर 19 जून को बंद होंगे। एविएंस बायोमेडिकल्स का आईपीओ 18 जून को खुलकर 22 जून को बंद होगा।

तीन कंपनियों की होगी लिस्टिंग: उत्कल स्पेशियलिटी इंडस्ट्रीज के शेयर 17 जून को लिस्ट होंगे। सुसान इलेक्ट्रिकल्स इंडिया की लिस्टिंग 18 जून को होगी। होराइजन रिक्लैम 19 जून को लिस्ट होगा।

एनएसई इस हफ्ते दाखिल करेगा ड्राफ्ट: देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज एनएसई इस हफ्ते सेबी के पास आईपीओ के दस्तावेज दाखिल कर सकता है।

क्रिप्टो अपडेट

क्वांटम हैकिंग की जद में 70 लाख बिटकॉइन

न्यूयॉर्क| भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर अटैक से दुनिया के करीब 70 लाख बिटकॉइन खतरे में हैं। कॉइनबेस की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से 50 लाख बिटकॉइन एक्टिव यूजर्स और क्रिप्टो एक्सचेंजों के कोल्ड वॉलेट के हैं। बार-बार एक ही एड्रेस इस्तेमाल करने से इनकी 'पब्लिक की' उजागर होने से ये बिटकॉइन सीधे हैकर्स के निशाने पर आ गए हैं। फिलहाल कोई कंप्यूटर इस सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता, लेकिन तकनीकी बदलावों में वर्षों लगेंगे। इस संकट से निपटने के लिए डेवलपर्स को माइग्रेशन शुरू करने करने की चेतावनी दी गई है। इसके तहत असुरक्षित कॉइन फ्रीज करने या सुरक्षा अपग्रेड की डेडलाइन तय करने जैसे समाधानों पर विचार चल रहा है।

इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजी

टेलीकॉम, डिफेंस शेयरों पर भी दांव

कंज्यूमर, बैंक शेयरों में फंड निवेश बढ़ा

भास्कर न्यूज | मुंबई

मई में लार्ज-कैप म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों का उत्साह कुछ ठंडा रहा। एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक, इस कैटेगरी में अप्रैल के 2,525 करोड़ की तुलना में मई में 1,593 करोड़ शुद्ध निवेश हुआ। वैसे समग्र निवेश (निकासी एडजस्ट करने से पहले) 5,050 करोड़ रहा और कैटेगरी का कुल एयूएम 3.97 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया। फंड हाउस ने बीते महीने मोटे तौर पर कंज्यूमर, बैंकिंग शेयरों में निवेश बढ़ाया।

मई महीने में टॉप-3 फंड हाउस की रणनीति...

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड: इसमें सबसे ज्यादा 2,005 करोड़ का शुद्ध निवेश हुआ। इसने पोर्टफोलियो में ब्रिटानिया, ग्रासिम, कोटक महिंद्रा बैंक और टीवीएस मोटर जोड़े, जबकि अशोक लेलैंड समेत चार शेयरों को बाहर किया। इस फंड ने बीते पांच वर्षों में सालाना औसतन 12.36% रिटर्न दिया।

निप्पन इंडिया: इसने पोर्टफोलियो में भारती एयरटेल, एचएएल और जुबिलेंट फूडवर्क्स जोड़े, लेकिन कोई शेयर नहीं बेचा और महज 0.25% कैश रखकर लगभग पूरा पैसा बाजार में लगा दिया। इसका पांच साल का रिटर्न 14% रहा।

एचडीएफसी लार्ज कैप... सबसे रूढ़िवादी राह चुनी। इसकी मैनेजमेंट टीम ने पोर्टफोलियो में न तो कोई नया शेयर जोड़ा और न ही किसी शेयर को इससे बाहर निकला। इसने 5 साल में 11% रिटर्न दिया।

गोल्ड ईटीएफ

गलत सौदे से बचाने को बड़े निवेश पर पाबंदी

भास्कर न्यूज | मुंबई

म्यूचुअल फंड कंपनियों ने गोल्ड ईटीएफ में बड़े निवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। अब एक बार में अधिकतम 25 करोड़ रुपए ही जमा हो सकेंगे। यह पाबंदी मई 2026 में 725 करोड़ रुपए की निकासी के बाद आई है, जो पिछले 5 वर्षों में सोने के निवेश का सबसे प्रदर्शन है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इस कदम से निवेश के भारी दबाव को संभालने और आपके पैसे को सुरक्षित रखने की अंदरूनी कवायद कर रही हैं।

वजह: वेल्थी डॉट इन के को-फाउंडर आदित्य अग्रवाल के मुताबिक, सप्लाई चेन टूटने या आयात लागत बढ़ने पर फंड हाउस मांग के अनुसार असली सोना नहीं खरीद पाते। ऐसे में नए ईटीएफ यूनिट बनाना मुश्किल होता है और रिटर्न का घरेलू सोने के भाव से अंतर बढ़ जाता है, जिसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ऐसी स्थिति में गोल्ड ईटीएफ का बाजार मूल्य उसकी वास्तविक कीमत (एनएवी) से काफी ऊपर चला जाता है।

सक्सेस मंत्रा

'नर्ड इकोनॉमी' का सबक: हर चर्चित ब्रांड निवेशकों को अमीर नहीं बनाता, जानिए हैस्ब्रो, गेम्स वर्कशॉप की कहानी

फैन खोए तो ब्रांड भी हारा, वफादारी बची तो 5 साल में पैसे तीन गुना

भास्कर न्यूज | लंदन

अगर 'नर्ड इकोनॉमी' (दिमागी और शौकिया खेलों का बाजार) के लिए कोई सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, तो वह यकीनन लॉकडाउन का दौर था। उस वक्त घरों में बंद उपभोक्ताओं के पास पर्याप्त समय और खर्च करने के लिए पैसा थे। लेकिन हर कंपनी लॉकडाउन के बाद मिले इस मौके को भुनाने में कामयाब नहीं रही। एक ही उभरते बाजार ने एक कंपनी ने निवेशकों का पैसा पांच साल तीन गुना कर दिया, जबकि दूसरी का रिटर्न सिर्फ 2% रहा। गेम्स वर्कशॉप और हैस्ब्रो की कहानी बताती है कि किसी भी बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी ग्राहकों की वफादारी और प्रोडक्ट्स की

कमी बनाए रखने की क्षमता होती है। दरअसल, लॉकडाउन के दौर ने हमें जो कुछ दिया उनमें 'नर्ड इकोनॉमी' यानी गेम्स, कॉमिक्स और फैंटेसी के शौकीनों की जेब से चलने वाली अर्थव्यवस्था का उभार शामिल है। लोगों ने बोर्ड गेम्स, फैंटेसी फिगर्स और कार्ड गेम्स पर खर्च किया। लेकिन सभी इस बूम का फायदा बराबर नहीं उठा पाए। ब्रिटिश कंपनी 'गेम्स वर्कशॉप' और अमेरिकी दिग्गज है हैस्ब्रो, दोनों एक ही बाजार में थे, लेकिन तकदीर और हालात इन्हें बिल्कुल अलग-अलग मुकाम पर ले गई। गेम्स वर्कशॉप साई-फाई (साइंस फिक्शन) और फैंटेसी थीम पर आधारित मिनिएचर फिगर गेम्स बनाती है। यह एक ऐसा शौक है, जो एक बार लग जाए तो छूटता नहीं है। हैस्ब्रो के पास मैजिकः द गैदरिंग (एमटीजी) और डंजन्स एंड ड्रैगन्स (डी एंड डी) जैसे ब्रांड हैं, जिनके दीवाने दुनियाभर में करोड़ों में हैं। इस दशक में गेम्स वर्कशॉप के निवेशकों ने डिविडेंड समेत अपना पैसा तीन गुना किया और कंपनी लंदन के एफटीएसई 100 ब्लू-चिप इंडेक्स में शामिल हो गई। दूसरी तरफ हैस्ब्रो में 2020 की शुरुआत में लगाया 1 डॉलर आज भी सिर्फ 1.02 डॉलर ही है। यानी पांच साल में लगभग शून्य रिटर्न। हैस्ब्रो की सबसे बड़ी गलती थी स्कारसिटी यानी संसाधनों की कमी की इकोनॉमी को न समझना। बैंक ऑफ अमेरिका के विश्लेषकों ने 2022 में कहा था कि कंपनी बहुत ज्यादा एमटीजी कार्ड छाप रही है। इससे सेकंडरी मार्केट बर्बाद हो रहा है और खिलाड़ियों का उत्साह ठंडा पड़ रहा है। इस कार्ड-प्रिंटिंग रणनीति पर कुछ शेयरधारकों ने इस साल कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी किया है। हैस्ब्रो की एक और समस्या यह है कि वह अब भी बच्चों के खिलौनों के कारोबार से बंधी है। नर्फ गन, स्क्रैबल और माई लिट्ल पोनी इसमें शामिल है। यह बाजार मुश्किल दौर में है। इस डिवीजन की बिक्री पिछले 15 में से 14 तिमाहियों में घटी है। हालांकि 'विजाड्र्स ऑफ द कोस्ट' डिवीजन, जो एमटीजी डी एंड डी बनाती है, का पहली तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन 51% रहा और एमटीजी की आमदनी सालाना एक-तिहाई से ज्यादा बढ़ी। लेकिन नर्ड इकॉनमी में सफलता का रास्ता नाजुक है। यहां के ग्राहक वफादार हैं, मगर बगावत पर उतर आएं तो बॉयकॉट से भी नहीं चूकते।

एआई से दूर, ट्रेंड की परवाह नहीं, फिर भी शानदार रिटर्न

गेम्स वर्कशॉप के सीईओ केविन राउंट्री ने जनवरी में निवेशकों को बताया था कि उनकी टीम का कोई भी अधिकारी अभी एआई को लेकर उत्साहित नहीं है। इस हफ्ते कंपनी को सफाई देनी पड़ी कि उनके वॉरहैमर स्पेस मरीन की फिगर में दिखी छठी उंगली एआई जनरेटेड नहीं थी। इसके बावजूद या शायद इसीलिए गेम्स वर्कशॉप का शेयर 32 गुना फॉरवर्ड अर्निंग्स पर ट्रेड करता है। दूसरी तरफ हैस्ब्रो सिर्फ 15 गुना पर है। नर्ड्स भीड़ के पीछे नहीं चलते। अभी तक यही रणनीति काम आ रही है।

कॉरपोरेट माइलस्टोन

ग्लोबल पेटेंट रैंकिंग में जियो टॉप-20 में पहुंची

भास्कर न्यूज | मुंबई

जियो प्लेटफॉर्म्स ने वैश्विक पेटेंट रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 'वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन' की 'पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी' रैंकिंग में कंपनी 320 पायदान की छलांग लगाकर 20वें स्थान पर पहुंच गई है। जियो ग्लोबल टॉप-20 में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय टेक कंपनी है। जियो अब हुवेई, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों के क्लब में शामिल हो गई है। कंपनी के पेटेंट 5जी, 6जी, एआई और क्लाउड तकनीकों से जुड़े हैं। 31 मार्च 2026 तक जियो ने 6,817 पेटेंट फाइल किए हैं। इनमें से 1,009 को मंजूरी मिल चुकी है। जियो प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन आकाश अंबानी ने इस उपलब्धि को भारत को वैश्विक डीप-टेक हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया।